सूर्योदय दि. 08-08-2020
दिल्ली स्टै. टा.
सूर्यास्त दि.30-17/33 दि.5 -17/37

अधिकतम तापमान 31.1°
न्यूनतम तापमान 34.1°

ओपन सर्च

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक

RNI No.DELHIN/2015/66886

महिलाएं-छोटे कारोबारियों के लिए..... पृष्ठ-7

E-mail | opensearchdelhi@gmail.com Facebook | https://www.facebook.com/opensearch.co.in Website | www.opensearch.co.in

वर्ष : 05 अंक : 244 नई दिल्ली, शनिवार, 08 अगस्त-2020 ` मूल्य : 02 रूपए | पृष्ठ : 08

एक नज़र

गृह मंत्रालय ने बंदरगाहों और गोदामों में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा करने को कहा

नयी दिल्ली। लेबनान की राजधानी बेरूत में भयावह विस्फोट के बाद केन्द्र सरकार ने देश के सभी प्रमुख बंदरगाहों और गोदामों की सुरक्षा स्थिति की समीक्षा करने तथा यह पता लगाने को कहा है कि इन जगहों पर किसी तरह की विस्फोट सामग्री तो नहीं पड़ी है। सरकार ने सभी एजेन्सियों से यह सुनिश्चित करने के लिए भी कहा है कि इन स्थानों पर जरूरी सुरक्षा उपायों को लागू किया जा रहा है। गृह मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड और केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल आदि एजेन्सियों को बेरूत विस्फोट के मद्देनजर सर्वेक्षण करने को कहा है। सीमा शुल्क बोर्ड ने मंत्रालय के आदेश के बाद सभी संबंधित अधिकारियों को यह पुष्टि करने के लिए कहा है कि गोदामों और बंदरगाहों पर किसी तरह की विस्फोटक सामग्री तो नहीं पड़ी है।

हैंडलूम दिवस पर शाह ने बुनकरों को दी बधाई

नई दिल्ली। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय हैंडलूम दिवस पर बुनकरों को बधाई दी है। शुक्रवार को शाह ने ट्वीट कर कहा कि वर्ष 2014 के बाद पहली बार मेहनती बुनकरों के सच्चे कौशल का पोषण किया जा रहा है और उन्हें उनका उचित श्रेय दिया जा रहा है। गृहमंत्री ने ट्वीट में यह भी कहा कि बुनकरों को और बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2015 में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के विकास की मुख्यधारा में लाने के लिए सात अगस्त को राष्ट्रीय हैंडलूम दिवस घोषित किया। प्रधानमंत्री मोदी की सरकार बुनकर समुदाय के समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री मोदी का मंत्र 'वोकल फॉर लोकल' निश्चित रूप से हथकरघा क्षेत्र का मनोबल बढ़ाएगा। आइए सभी वोकल फॉर हैंडमेड को प्रधानमंत्री मोदी के आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने में मदद करने का संकल्प लें।

देश में कोरोना की जांच के लिए 1370 लैब स्थापित

नई दिल्ली। देश में कोरोना की जांच के लिए अबतक 1370 लैब स्थापित किए जा चुके है। केन्द्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटों में 5 लाख 74 हजार से ज्यादा टेस्ट किए गए। देश में अबतक कुल 2,27,24,134 टेस्ट किए जा चुके हैं। देश के उन राज्यों में सबसे ज्यादा टेस्ट कराए जा रहे हैं, जहां कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। दिल्ली में भी कोरोना की गति तेज थी लेकिन ज्यादा टेस्टिंग के कारण नए मामले बढ़ने में कमी आई।

बसपा विधायकों को उच्च न्यायालय के नोटिस कराये तामिल

जैसलमेर। राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा बहुजन समाजवादी पार्टी (बसपा) के छह विधायकों के कांग्रेस में सम्मिलित होने के मामले में जारी किए गए नोटिस आज विधायकों को तामिल कराये गये। जैसलमेर जिला सत्र न्यायधीश के न्यायालय रीडर एवं दो अन्य न्यायिक कर्मियों की टीम ने शुक्रवार को सूर्यगढ़ होटल में जाकर इन विधायकों को नोटिस तामिल करवाए। इस अवसर पर जैसलमेर पुलिस अधीक्षक अजय सिंह एवं अन्य पुलिस अधिकारी मौजूद थे। इन बसपा विधायकों के शनिवार को इसका जवाब उच्च न्यायालय में दाखिल करने की संभावना है।

केरल में विमान हादसा
17 की मौत, कई घायल

केरल एयर इंडिया विमान हादसा, चीख-पुकार और एंबुलेंस के सायरन की आवाज से दहल गया क्षेत्र

मलप्पुरम.एजेंसी

दुबई से आ रहे विमान के एकाएक खाई में गिर जाने से यहां चारों ओर चीख-पुकार, खून से सने कपड़े, डरे सहमे रोते हुए बच्चे और एंबुलेंस के सायरन की आवाजों ने क्षेत्र को दहला दिया। एअर इंडिया एक्सप्रेस का विमान शुक्रवार शाम कोझिकोड हवाई पट्टी से फिसल कर खाई में गिर गया और दो हिस्सों में टूट गया। इस दुर्घटना में कम से कम 17 लोगों की मौत हो गई। बारिश के बीच, स्थानीय नागरिकों और पुलिस सहित बचाव कर्मियों ने विमान से घायल पुरुष और महिलाओं को बाहर निकालने में फुर्ती दिखाई। विमान तेज आवाज के साथ दो बड़े टुकड़ों में टूट गया और यात्रियों को समझ ही नहीं आया कि पल भर में क्या हो गया। इलाके में चीख पुकार मच गई। बचावकर्मियों ने लोगों को बाहर निकाला। इस दौरान चार से पांच साल के छोटे बच्चे बचाव कर्मियों की गोद में चिपके दिखाई दिए और यात्रियों का सारा सामान यहां वहां बिखरा था। तेज आवाज सुन कर स्थानीय लोग भी मदद के लिए दौड़ पड़े। एक स्थानीय व्यक्ति ने कहा कि तेज आवाज सुन कर वह हवाई अड्डे की ओर भागे। उन्होंने कहा, ''छोटे बच्चे साटो के नीचे फंसे हुए थे और यह बेहद दुखद था। बहुत से लोग घायल थे। उनमें से कई की हालत गंभीर थी।''

उन्होंने कहा, पैर टूटे हुए थे...मेरे हाथ और कमीज घायलों के खून से सनी हुई थी। बचाव अभियान में शामिल एक अन्य व्यक्ति ने टीवी चैनल को दिये साक्षात्कार में कहा, घायल पायलट को विमान से कॉकपिट तोड़कर निकाला गया।

राहत एवं बचाव कार्य जारी है: मुरलीधरन

केंद्रीय देश राज्य मंत्री वी. मुरलीधरन ने शनिवार को कहा है कि केरल में कोझिकोड हवाई विमान हादसे के शिकार लोगों को बचाने के लिए सरकार की ओर से कोशिशें जारी है। श्री मुरलीधरन ने कहा कि करीपुर एक ऊंचाई पर स्थित हवाई अड्डा है और इस हादसे को लेकर अधिकारियों की ओर से और अधिक सूचना प्राप्त होने का इंतजार किया जा रहा है। उन्होंने ट्वीट कर कहा,यह एक ऊंचाई पर स्थित हवाई अड्डा है, केंद्र सरकार, एयर इंडिया मंत्रालय तथा नागरीय विमानन प्राधिकरण की ओर से कोशिशें जारी हैं। अधिकारियों की ओर से और सूचना प्राप्त होने का इंतजार है। सूत्रों के अनुसार नागर विमानन महानिदेशालय ने एक पहाड़ी की चोटी पर हवाई अड्डा के स्थित होने के कारण इसे जोखिम वाले हवाई अड्डा के रूप में चिह्नित कर रखा है।

जारी किए हेल्पलाइन नंबर

UAE में भारतीय दूतावास और समुदाय ने परिवारों की मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं। दुबई में भारत के महावाणिज्य दूत डॉ अमन पुरी ने कहा कि हम यात्रियों और चालक दल की सुरक्षा के लिए प्रार्थना करते हैं। हमें जब भी इस हादसे से संबंधित कोई सूचना प्राप्त होगी हम आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे हेल्पलाइन +97156 5463903, +971543090572, +971543090572, +971543090575 लगातार काम कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि भारतीय वाणिज्य दूतावास यात्रियों और उनके परिजनों की हर संभव सहायता के लिए उपलब्ध है।

नई शिक्षा नीति से नए भारत की नींव रखी जाएगी : पीएम मोदी

- राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर बोले पीएम मोदी, यह 21वीं सदी के भारत की नींव तैयार करने वाली नीति है

नयी दिल्ली.एजेंसी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कहा कि तीन-चार साल के विचार-मंथन और लाखों सुझावों के बाद नई शिक्षा नीति को मूर्त रूप दिया गया है और यह नए भारत की नींव रखने का काम करेगा।श्री मोदी ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत उच्च शिक्षा में होने वाले परिवर्तनकारी सुधारों पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि आज हर विचारधारा के लोग इस नयी शिक्षा नीति पर मंथन कर रहे हैं। इस नीति का कोई विरोध नहीं कर रहा है क्योंकि इसमें कुछ भी एकतरफा नहीं है। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ कोई सर्कुलर नहीं बल्कि एक महायज्ञ है, जो नए देश की नींव रखेगा और एक सदी तैयार करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि शिक्षा नीति में देश के लक्ष्यों का ध्यान रखना जरूरी है ताकि भविष्य के लिए पीढ़ी को तैयार किया जा सके। कई दशकों से शिक्षा नीति में बदलाव नहीं हुआ था इसलिए समाज में भेड़चाल को प्रोत्साहन मिल रहा था। कभी डॉक्टर, कभी इंजीनियर कभी वकील बनाने की होड़ लगी हुई थी लेकिन अब युवा क्रिएटिव विचारों को आगे बढ़ा सकेगा, अब सिर्फ पढ़ाई नहीं बल्कि वर्किंग कल्चर को विकसित किया गया है। युवाओं में क्रिटिकल सोच विकसित करना होगा। उन्होंने कहा, हमारे सामने सवाल था कि क्या हमारी नीति युवाओं को अपने सपने पूरा करने का मौका देती है। क्या हमारी शिक्षा व्यवस्था युवा को सक्षम बनाती है। नई शिक्षा नीति को बनाते समय इन सवालों पर गंभीरता से काम किया गया है।

नई शिक्षा नीति-2020

केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल और केंद्रीय मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री संजय धोत्रे के अलावा राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा तैयार करने के लिए गठित समिति के अध्यक्ष और सदस्यों के साथ-साथ प्रख्यात शिक्षाविद् व वैज्ञानिक भी इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने इस सप्ताह की शुरुआत में नई शिक्षा नीति-2020 को मंजूरी प्रदान की थी। नई शिक्षा नीति ने 34 साल पुरानी शिक्षा नीति को बदला है, जिसे 1986 में लागू किया गया था।

महाराष्ट्र से बिहार तक 'किसान रेल' की शुरुआत

नई दिल्ली.एजेंसी।

कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर और रेल मंत्री पीष गोयल ने देवलाली (महाराष्ट्र) से दानापुर (बिहार) तक चलने वाली देश की पहली 'किसान रेल' को शुक्रवार को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पायलेट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू की गई यह ट्रेन चार राज्यों से होकर चलेगी। समारोह में कृषि भवन से, वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए दोनों मंत्रियों ने किसानों के लिए ट्रेन चलाने की संकल्पना एवं इसे साकार करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार जताया। श्री तोमर ने कहा कि किसानों की समृद्धि एवं देश के कोने-कोने तक खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने में किसान रेल बहुत कारगर सिद्ध होगी। श्री तोमर ने कहा कि आज किसानों की एक बड़ी अनिवार्य आवश्यकता को भारत सरकार ने पूरा किया है। प्रधानमंत्री के संकल्प के अनुरूप वित्त मंत्री ने किसानों की भलाई के लिए बजट में बड़ी घोषणाएं की थी। उसके बाद कोरोना संकट आ खड़ा हुआ, लेकिन इस दौरान भी किसानों ने अथक परिश्रम कर कृषि कार्य प्रभावित नहीं होने दिया। फसल कटाई, उपार्जन, ग्रीष्मकालीन बुआई सभी काम अच्छे से हुआ। उन्होंने कहा कि यह रेल किसानों के उत्पाद एक से दूसरे स्थान पर सस्ते किराए में ले जाने में सफल होगी, यह पूरा विश्वास है। किसानों की आय दोगुनी करने के लिए सरकार के स्तर पर सभी प्रयास हो रहे हैं। नये अध्यादेश लाए गये हैं, अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम में बदलाव किया गया है, किसानों को कानूनी बंधनों से आजादी मिल गई है। देश में 10 हजार कृषक उत्पादक संगठन (एफपीओ) गठित करने का बड़ा अभियान होने वाला है।

भारत में पहली बार एक दिन में कोविड-19 के 60,000 से अधिक मामले सामने आए, कुल मामले 20 लाख के पार पहुंचे

नई दिल्ली.एजेंसी।

भारत में 24 घंटे के भीतर पहली बार कोविड-19 के 60,000 से अधिक मामले सामने आने के साथ ही शुक्रवार को देश में संक्रमण के कुल मामलों की संख्या 20 लाख को पार कर गई। वहीं, इस बीमारी से उबरने वाले मरीजों की संख्या 13.78 लाख हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह जानकारी दी।

महज दो दिन पहले ही कोरोना वायरस के मामलों का आंकड़ा 19 लाख के पार पहुंचा था।देश में कोविड-19 के मामलों को एक लाख तक पहुंचने में 110 दिन का वक्त लगा था और 59 दिन में यह आंकड़ा 10 लाख के पार चला गया। इसके बाद संक्रमण के मामलों को 20 लाख का आंकड़ा पार करने में महज 21 दिन का वक्त लगा।यह लगातार नौवां दिन है जब कोविड-19 के एक दिन में 50,000 से अधिक मामले सामने आए हैं।स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा सुबह आठ बजे अद्यतन किए गए आंकड़ों के अनुसार एक दिन में कोविड-19 के 62,538 मामले आने से संक्रमण के कुल मामले 20,27,074 पर पहुंच गए।बीते 24 घंटे में 886 और लोगों के इस संक्रामक रोग से दम तोड़ने से मृतकों की कुल संख्या 41,585 हो गई है।

साथ ही इस दौरान कोरोना वायरस संक्रमण से उबरने वाले मरीजों की संख्या बढ़कर शुक्रवार को 13,78,105 हो गई। यानी देश में स्वस्थ होने वाले मरीजों की दर 67.98 प्रतिशत है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में फिलहाल 6,07,384 मरीज उपचाराधीन हैं जो कि संक्रमण के कुल मामलों का 29.96 प्रतिशत है। मरने वाले लोगों की दर गिरकर 2.07 प्रतिशत रह गई है।

दिल्ली में कोरोना संक्रमण के स्वस्थ मामले नये से कम

राजधानी दिल्ली में शुक्रवार को कोरोना वायरस (कोविड-19) महामारी के नये मामलों की तुलना में स्वस्थ होने वालों की संख्या में गिरावट बनी रही। इस सप्ताह के शुरु में नये मामले एक हजार से कम रहने से रिकवरी दर में सुधार के साथ ही सक्रिय मामले भी घटकर 10 हजार से नीचे आ गए थे,किंतु अब यह फिर बढ़कर इससे ऊपर निकल गए। दिल्ली स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से आज जारी आंकडों के अनुसार पिछले 24 घंटों में 1192 नये मामलों से कुल संक्रमितों की संख्या 1,42,723 पर पहुंच गई। इस दौरान 1108 मरीजों के स्वस्थ होने से कोरोना को मात देने वालों का कुल आंकड़ा 1,28,232 हो गया। देश में दिल्ली का स्थान सर्वाधिक रिकवरी वाले राज्यों में शामिल है। फिलहाल दिल्ली का रिकवरी दर 89.84 प्रतिशत है।

प्रदीप कुमार जोशी को यूपीएससी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया

नई दिल्ली (ओपन सर्च)

शिक्षाविद् प्रोफेसर प्रदीप कुमार जोशी को शुक्रवार को संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। यूपीएससी भारत के नौकरशाहों एवं राजनयिकों समेत अहम पदों पर नियुक्ति के लिए सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन करता है। जोशी अभी तक आयोग के सदस्य थे। छत्तीसगढ़ एवं मध्यप्रदेश के लोक सेवा आयोगों के अध्यक्ष रहे जोशी मई 2015 में यूपीएससी के सदस्य बने थे। एक अधिकारी ने बताया कि यूपीएससी के अध्यक्ष के तौर पर जोशी का कार्यकाल 12 मई 2021 तक होगा। जोशी को अध्यक्ष बनाए जाने के बाद यूपीएससी में अब एक सदस्य का पद रिक्त हो गया है। इस समय भीम सेन बस्सी, एयर मार्शल ए एस भोंसले (सेवानिवृत्त), सुजाता मेहता, मनोज सोनी, स्मिता नागराज, एम सत्यवती, भारत भूषण व्यास, टी सी ए आनंद और राजीव नयन चौबे यूपीएसए के अन्य सदस्य हैं। आयोग भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय विदेश सेवा समेत अहम सेवाओं के लिए तीन चरणों में वार्षिक सिविल सेवा परीक्षा आयोजित कराता है।

मनोज सिन्हा ने ली जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल पद की शपथ

श्रीनगर.एजेंसी।

केन्द्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के दूसरे उपराज्यपाल के रूप में श्री मनोज सिन्हा ने आज यहां पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। राजभवन में आयोजित एक संक्षिप्त कार्यक्रम में जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल ने श्री सिन्हा को शपथ दिलायी। श्री सिन्हा ने अंग्रेजी भाषा में शपथ ली। इससे पूर्व मुख्य सचिव बीवीआर सुब्रह्मण्यम ने श्री सिन्हा को जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल नियुक्त किये जाने संबंधी राष्ट्रपति के आदेश को पढ़ कर सुनाया। शपथ ग्रहण समारोह में चुनींदा अतिथि ही शामिल हुए। पहले उपराज्यपाल श्री गिरीश चंद्र मुर्मू ने पांच अगस्त को पद से त्यागपत्र दिया था और कल उन्हें भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियुक्त किया गया है। राष्ट्रपति

भवन ने कल सुबह श्री मुर्मू के त्यागपत्र को स्वीकार किये जाने और श्री सिन्हा को उपराज्यपाल नियुक्त किये जाने की घोषणा की थी। घोषणा के बाद श्री सिन्हा कल दोपहर श्रीनगर पहुंच गये थे और शपथ एवं कार्यभार ग्रहण करने से पहले कल दिनभर उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक की और परिस्थितियों की जानकारी ली। शपथ लेने के बाद मनोज सिन्हा ने कहा, कश्मीर भारत का स्वर्ग है, मुझे यहां भूमिका निभाने का अवसर दिया गया है। 5 अगस्त एक महत्वपूर्ण तारीख है। सालों बाद जम्मू-कश्मीर मुख्यधारा में आया है। सालों बाद यहां कई परियोजनाएं शुरू हुई। मेरी प्राथमिकता उन परियोजनाओं को आगे ले जाना है। उन्होंने कहा, किसी के खिलाफ कोई पक्षपात नहीं होगा। संवैधानिक शक्तियों का उपयोग लोगों के कल्याण के लिए किया जाएगा। मैं लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि उनकी वास्तविक शिकायतों को सुना जाएगा और हम समाधान का रास्ता खोजने की कोशिश करेंगे। यहां विकास को आगे ले जाना मेरा उद्देश्य है।

मनोज सिन्हा बीजेपी के बड़े चेहरे

मनोज सिन्हा को एलजी की जिम्मेदारी मिलने के साथ जम्मू-कश्मीर के उच्चस्थ पद पर राजनीतिक एंट्री हुई है। मनोज सिन्हा पूर्व में गाजीपुर से सांसद रहे हैं और पूर्वी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के बड़े चेहरे हैं। मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में सिन्हा मंत्री रह चुके हैं और उनके पास रेलवे के राज्यमंत्री और संचार राज्यमंत्री का कार्यभार था।

संक्षिप्त समाचार

तेलंगाना में कोरोना के 2207 नए मामले मिले, 12 की और मौत

हैदराबाद (तेलंगाना)। राज्य में गुरुवार को कोरोना के 2,207 मामले दर्ज किये गये हैं। इसके साथ राज्य में अब तक कोरोना के मामलों की संख्या 75,257 हो गई है। राज्य में कल 12 और लोगों की मौत हो गई है। शुक्रवार की सुबह स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपने बुलेटिन में बताया कि कल शाम तक एक ही दिन में कोरोना से 12 लोगों की मौत हो गई। राज्य में अब तक मरने वालों की संख्या बढ़कर 601 हो गई है। बुलेटिन में बताया गया है कि एक दिन में 1,136 लोगों के ठीक होने पर अस्पतालों से डिस्चार्ज किया गया है। राज्य में अब तक 53,239 लोगों की मौत हो चुकी है। बुलेटिन के अनुसार वर्तमान में राज्य में 21,417 मामले सक्रिय हैं। गुरुवार को 23, 495 लोगों को कोरोना परीक्षण किया गया। राज्य में अब तक तेलंगाना में 5,66,984 लोगों का परीक्षण किया जा चुका है। इसके अलावा रंगारेड्डी जिले में 196, वारंगल शहरी में 142, मेचल मालकजगिरी में 136, भद्रादि कोट्टगुडेम में 82, जनगाम में 60, जोगुलम्बा गडवाला जिले में 87, कामरेड्डी में 96, करीमनगर में 93, खम्मम में 85, निजामाबाद में 89 और पेद्दापल्ली में 71 मामले दर्ज किये गये हैं।

मप्र में बच्चे और बुजुर्ग ने कोरोना को जीतकर दिया नया संदेश

भोपाल। कोरोना संक्रमण से जूझ रहे देश के अन्य हिस्सों के साथ मध्यप्रदेश से अच्छी खबरें भी आ रही हैं। राज्य में मासूम बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक कोरोना के खिलाफ जंग जीतने में सफल हुए हैं। कोरोना पर यह जीत नया संदेश दे रही है। राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या हालांकि लगातार बढ़ रही है। अब यह आंकड़ा 37 हजार के करीब पहुंच गया है। वायरस से मौतों का आंकड़ा भी 950 को पार कर चुकी है। वहीं अब तक लगभग 27 हजार मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। राज्य में रिकवरी रेट भी लगभग 74 फीसदी के करीब है और यही बात सरकार व स्वस्थ्य अमले को थोड़ी राहत दे रही है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच दो अच्छी खबरें आई हैं। ये खबरें यह संदेश दे रही है कि अगर बीमारी का समय से पता चल जाए और मरीज को बेहतर इलाज मिल जाए तो बीमारी लाइलाज नहीं है। राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी लोगों से समय रहते परीक्षण और उपचार का परामर्श देते आए हैं। खरगौन जिले में 100 वर्षीय रुक्मिणी देवी ने कोरोना को मात देने में कामयाबी पाई है।

आईटीबीपी के ट्रैकर्स ने पार की फूलों की घाटी, गमशाली, माना पास रवाना

जोशीमठ। आईटीबीपी के 43 जांबाज ट्रैकर्स विश्व धरोहर 'फूलों की घाटी' से गमशाली और माना पास के लिए रवाना हो गए। लंबी दूरी की ट्रैकिंग के लिए यह क्षेत्र पूरी दुनिया में विख्यात है। कोरोना की वजह इस साल यहां देशी-विदेशी पर्यटक और ट्रैकर्स नाममात्र के पहुंचे हैं। हालांकि वन विभाग 1 जून को फूलों की घाटी को खोल चुका है। तब से अब तक मात्र युवा पर्यटक ही फूलों की घाटी का दीदार करने पहुंचे। इसकी मुख्य वजह घाटी के मुख्य पड़ाव घांघरियां में होटल एवं रेस्टोरेंट्स का बंद होना है। इस दौरान लंबी दूरी के ट्रैक पर निकले आईटीबीपी प्रथम वाहिनी के दो दल फूलों की घाटी को पार कर चुके हैं। पहला दल 24 किलोमीटर की पैदल दूरी तय कर चार दिन मे नीती घाटी के गमशाली गांव पहुंचेगा। दूसरा दल 35 किलोमीटर के दुर्गम ट्रैक का पार करते हुए करीब आठ दिन में माणा पास पंहुचेगा। फूलो की घाटी के रेंज ऑफिसर बृजमोहन भारती वैली टू गमशाली वाले दल में आईटीबीपी के 15 हिमबीर और वैली टू माना पास वाले दल में 28 हिमबीर शामिल हैं।

मौसम के पूर्वानुमान के लिए किसान इस्तेमाल कर रहे हैं मेघदूत ऐप

रामगढ़। जिले में किसानों को मेघदूत ऐप काफी सहयोग प्रदान कर रहा है। अभी के समय में कब बारिश होगी और कब मौसम साफ रहेगा, इसकी जानकारी किसान मोबाइल से ही हासिल कर ले रहे हैं। यह जानकारी खेती के लिए काफी सहायक साबित हो रहा है। किसानों को खेती से जुडी समस्याओं के निदान भी ऐप से मोबाइल पर ही मिल रही है। इसके साथ ही कृषि विज्ञान केन्द्र के द्वारा ग्रामीण कृषि मौसम सेवा के तहत किसानों को इस तरह की जानकारी हफ्ते में दो बार विभिन्न माध्यमो से निरंतर दी जा रही है, जिससे किसान काफी लाभान्वित हो रहें है। इस ऐप के द्वारा किसान अपने मोबाइल का इस्तेमाल करके अपने घर से ही मौसम पूर्वानुमान के साथ-साथ कृषि की नई तकनीकों तथा खेती से जुड़ी अनेक जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। यह एप्लीकेशन मूल रूप से हर मंगलवार और शुक्रवार को किसानों के मोबाइल पर अगले पांच दिनों का मौसम का पूर्वानुमान और पिछले हफ्ते में मौसम की क्या स्थिति थी यह भी दिखाता है।

चंपावत में कार खाई गिरी, एक की मौत, दूसरा घायल

नैनीताल। उत्तराखंड के चंपावत जिला में एक कार के गहरी खाई में गिर जाने से एक युवक की मौत हो गयी और दूसरा घायल हो गया है। घायल को जिला अस्पातल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। तामली थाना प्रभारी दीवान सिंह ग्वाल ने बताया कि यह दुर्घटना तामली थाना के अंतर्गत चतुरबोट के पास कल देर रात घटी है। उन्होंने बताया कि पीड़ित राजेन्द्र सिंह महर अपनी कार से कफल्टा निवासी प्रकाश सिंह महर को छोड़ने के लिये उनके घर चतुरबोट जा रहा था। घर से पहले चतुरबोट मोड के पास कार 200 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। ग्वाल ने बताया कि हादसे में प्रकाश की मौत हो गयी जबकि राजेन्द्र सिंह गंभीर रूप से घायल हो गया। दुर्घटना के बारे में आज सुबह उस समय पता चला जब दोनों युवक अपने घर नहीं पहुंचे। परिजनों ने दोनों की ढूंढखोज की। इसी दौरान दुर्घटना का पता चला। पुलिस को सूचना दी गयी।

जम्मू-कश्मीर में कोरोना से सात और लोगों की मौत

श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर में कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत का सिलसिला थम नहीं रहा है। शुक्रवार को भी कोरोना संक्रमण के कारण सात और लोगों की मौत हो गई है। इसके साथ ही कोरोना से मरने वालों की संख्या 453 तक पहुंच गई है। शुक्रवार को इस वायरस से जिन सात लोगों की मौत हुई है उनमें सोपोर की एक 60 वर्षीय महिला, सरसुना अनंतनाग की 65 वर्षीय महिला, चेरसू अवंतीपोरा का 55 वर्षीय व्यक्ति, हवलदार श्रीनगर के दो लोग जिनमें 32 वर्षीय व 65 वर्षीय व्यक्ति, एचएमटी श्रीनगर का 60 वर्षीय व्यक्ति, डलगेट श्रीनगर की एक 65 वर्षीय महिला शामिल है। स्किम्स सौरा अस्तपाल में मरने वाली सोपोर की एक 60 वर्षीय महिला उच्च रक्तचाप, मधुमेह, निमोनिया से ग्रस्त थी।

पटना : अखिल भारतीय फार्मासिस्ट एसोसिएशन बिहार के पटना में राज्य के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के आवास पर वेतन बढ़ाने की मांग कर प्रदर्शन करते हुए।

पलामू में कोरोना संक्रमित की मौत, जिले में अब तक 613 मरीज

पलामू/एजेंसी।

पलामू में आज एक कोरोना संक्रमित की मौत हो गई है। पलामू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में अंत्यपरीक्षण के बाद शव परिजन को सौंप दिया गया है। 48 वर्षीय संक्रमित शहर के हाउसिंग कालोनी का रहने वाला था। पांच अगस्त को टू नेट से हुई जांच में उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इलाज के लिए कोविड केयर सेंटर में उसे भर्ती कराया गया था। शुक्रवार की सुबह उसकी तबीयत ज्यादा खराब हुई तो बेहतर इलाज के लिए रांची रेफर किया गया था। रांची जाने के क्रम में उसकी मौत हो गई। बताया जाता है कि सांस लेने में उसे काफी परेशानी हो रही थी। मेदिनीनगर स्थित पीएमसीएच के अधीक्षक डा केएन सिंह ने घटना की पुष्टि की। बताया कि वह हाइपरटेंशन, डायबिटीज व अन्य बीमारियों से ग्रसित था। उसके परिजनों की कोरोना जांच होगी। बता दें कि पलामू में अब तक कोरोना वायरस के कुल 613 मरीज हो गए हैं। इसमें से

दो की मौत हो गई है और 285 मरीज स्वस्थ हो गए हैं। जिले में अभी भी सक्रिय मरीजों की संख्या लगभग आधी बची हुई है। राज्य में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। झारखंड में कोरोना के कुल 15 हजार से अधिक केस हो गए हैं।

जम्मू कश्मीर की जनता के हित में संवैधानिक अधिकारों का उपयोग करेंगे : मनोज सिन्हा

श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर के नये उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने शुक्रवार को कहा कि वह बिना किसी पक्षपात के राज्य की जनता की भलाई के लिये संवैधानिक अधिकारों का उपयोग करेंगे। श्री सिन्हा ने आज केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के दूसरे उपराज्यपाल की शपथ ग्रहण के बाद कहा कि बिना किसी भेदभाव के राज्य की जनता के कल्याणार्थ वह संवैधानिक अधिकारों का इस्तेमाल करेंगे। उन्होंने कहा, 'मैं राज्य की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं कि उनकी वाजिब शिकायतें सुनी जायेंगी और हम उनके समाधान ढूंढने का प्रयास करेंगे। मेरा लक्ष्य है कि राज्य में विकास की बहार को आगे ले जाऊं।' उपराज्यपाल ने कहा, 'भारत का कश्मीर स्वर्ग है। मुझे राज्य को आगे ले जाने में अपनी भूमिका निभाने का अवसर दि गया है। पांच अगस्त ए महत्वपूर्ण तारीख है, इस दिन वर्षों तक जम्मू-कश्मीर अलग-थलग रहने के बाद मुख्यधारा से जुड़ा। वर्षों बाद यहां कई परियोजनाओं पर काम शुरु हुआ, मेरी प्राथमिकता इन परियोजनाओं के

काम को तेजी से आगे बढ़ाने पर रहेगी।' नरेंद्र मोदी सरकार ने गत वर्ष पांच अगस्त को जम्मू-कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा खत्म कर अनुच्छेद 370 के कुछ प्रावधानों और धारा 35 ए समाप्त कर दी थी और राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया था

opensearch

सीएम नीतीश कुमार 500 बस स्टॉप निर्माण योजना का करेंगे शिलान्यास

पटना/एजेंसी। बिहार में शनिवार को परिवहन विभाग की विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किया जाएगा। इस दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम को सीएम संबोधित करेंगे। इस मौके पर मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत जिलों में 1000 लाभुकों को अनुदान राशि एवं वाहन का वितरण किया जाएगा एवं ग्रामीण क्षेत्रों में 500 बस स्टॉप के निर्माण सहित अन्य योजनाओं का शिलान्यास किया जाएगा। मंत्री परिवहन विभाग सह अध्यक्ष बिहार सड़क सुरक्षा परिषद, संतोष कुमार निराला द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में 500 बस स्टॉप निर्माण की स्वीकृति दी गई है। परिवहन सचिव संजय अग्रवाल ने बताया कि मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत वाहन

खरीदने के लिए अब तक 26267 लाभुकों को अनुदान का भुगतान करते हुए रोजगार दिया गया है। इसमें अनुसूचित जाति के 14455, अनुसूचित जनजाति के 1247 एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के 10565 लाभुकों को रोजगार दिया गया है। शनिवार को जिलों में मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के कुल-1000 लाभुकों को अनुदान राशि एवं वाहन का वितरण किया जाएगा। लाभुकों को वाहन की चाबी संबंधित जिलाधिकारी द्वारा सौंपी जाएगी। गया-75, पूर्णियां-51, मधुबनी-50, मुजफ्फरपुर-40, मोतिहारी-40, पटना-40, भागलपुर-30, सहरसा-30, नालंदा-30 और मुंगेर-29 लाभुकों को वाहन की चाबी संबंधित जिलाधिकारी द्वारा सौंपी जाएगी। परिवहन सचिव ने बताया कि पिछले कुछ वर्षों में ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए यात्रियों को सुरक्षित यात्री पड़ाव उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में परिवहन व्यवस्था को सुदृढ़ करने एवं सार्वजनिक परिवहन से यात्रा करने वाले नागरिकों की सुविधा एवं सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाये जाने के दृष्टिकोण से सड़क सुरक्षा परिषद्, बिहार द्वारा राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में 500 बस स्टॉप का निर्माण किया जा रहा है। इसमें प्रति बस स्टॉप निर्माण की लागत एक लाख 90 हजार 300 रुपये है। इस योजना के लिए राज्य सरकार द्वारा कुल नौ करोड़ 51 लाख 50 हजार रुपये की राशि का आवंटन उपलब्ध कराया गया है।

बिहार में बाढ़ से 21 लोगों की मौत, 69 लाख की आबादी हुई प्रभावित

पटना/एजेंसी।

बिहार की सभी प्रमुख नदियों में उफान जारी है। इस बीच बाढ़ के कारण राज्य के 16 जिलों की 69 लाख की आबादी प्रभावित हो चुकी है। बाढ़ के कारण अब तक 21 लोगों की मौत हो गई है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई हैं। इधर, राज्य सरकार भी बाढ़ पीड़ित परिवारों के बैंक खाते में 6000 रुपये पहुंचाकर आर्थिक मदद देने में जुटी हुई है। राज्य आपदा प्रबंधन विभाग के मुताबिक, राज्य के 16 जिलों के कुल 124 प्रखंडों की 1,185 पंचायतें बाढ़ से प्रभावित हुई हैं। इन क्षेत्रों में करीब 69 लाख की आबादी बाढ़ से प्रभावित हुई है।

आपदा प्रबंधन विभाग के अपर सचिव रामचंद्र डू ने बताया कि बाढ़ प्रभावित इलाकों में 8 राहत शिविर खोले गए हैं, जहां 12 हजार से ज्यादा लोग रह रहे हैं। इसके अलावा बाढ़ प्रभावित इलाकों में कुल 1,402 सामुदायिक रसोईघर चलाए जा रहे हैं, जिसमें प्रतिदिन करीब दस लाख लोग भोजन कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि बाढ़ के दौरान अलग-अलग इलाकों में हुई विभिन्न घटनाओं में 21 लोगों की मौत हुई है। इनमें सबसे अधिक सात लोगों की मौत दरभंगा जिले में तथा छह लोगों की मौत मुजफ्फरपुर जिले में हुई है। इस बीच 23 पालतू पशु की भी मौत हो गई है।उन्होंने बताया कि सभी बाढ़ प्रभावित जिलों में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की 33 टीमें राहत एवं बचाव का कार्य कर रही हैं।

उन्होंने बताया कि अब तक 4,81,939 लोगों को बाढ़ प्रभावित इलाकों से निकालकर सुरक्षित इलाकों में पहुंचाया गया है। अपर सचिव ने बताया कि बाढ़ प्रभावित प्रत्येक परिवार को ग्रेच्युट्स रिलीफ के अंतर्गत 6,000 रुपये की राशि दी जा रही है। अभी तक 4,50,129 परिवारों के बैंक खाते में कुल 27080 करोड़ रुपये जीआर की राशि भेजी जा चुकी है। ऐसे परिवारों को एसएमएस के माध्यम से सूचित भी किया गया है।

मध्य प्रदेश में कोरोना से अब तक 951 लोगों की मौत

भोपाल/एजेंसी। मध्य प्रदेश में कोरोना का कहर लगातार जारी है। अब यहां के पांच जिलों में कोरोना के 343 नये मामले सामने आए हैं, जबकि पांच लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। इसके बाद राज्य में संक्रमित मरीजों की कुल संख्या 36 हजार 907 हो गई है। वहीं, प्रदेश में कोरोना से अब तक 951 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि, प्रदेश का रिकवरी रेट 73 फीसदी से अधिक है और अब तक 27 हजार लोग कोरोना को मात देकर घर आ गए हैं। इंदौर की प्रभारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. पूर्णिमा गाडरिया ने शुक्रवार को बताया कि एमजीएमजी मेडिकल कॉलेज द्वारा गुरुवार देर रात जारी 1961 सेम्पलों की जांच रिपोर्ट में 145 नये पॉजिटिव मिले हैं, जबकि तीन लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। इसके बाद इंदौर में संक्रमितों की कुल संख्या 8159 और मृतकों की संख्या 328 हो गई है। वहीं, भोपाल सीएमएचओ डॉ. प्रभाकर तिवारी के अनुसार राजधानी में शुक्रवार सुबह 131 नये संक्रमित मिले हैं, जबकि दो लोगों की मौत की पुष्टि हुई है।

इसके अलावा कटनी में 31, उज्जैन में 18 और नीमच में 18 नये मामले सामने आए हैं। इन 343 नये मामलों के साथ राज्य में संक्रमितों की कुल संख्या 36,907 हो गई है। इनमें सबसे अधिक इंदौर में 8158, भोपाल 7401, ग्वालियर, 2748, मुरैना 1694, जबलपुर 1641, उज्जैन 1269, खरगौन 856, नीमच 811, सागर 736, बड़वानी 829, खंडवा 688, बुरहानपुर 489, भिण्ड 496, देवास 453, रतलाम 498, मंदसौर 469, धार 474, छतरपुर 376, रायसेन 389, रीवा 402, टीकमगढ़ 322, राजगढ़ 389, विदिशा 364, शाजापुर 306, शिवपुरी 346।

हिमाचल के ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी कोरोना पॉजिटिव पाए

शिमला/एजेंसी। हिमाचल प्रदेश के ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उन्होंने 30 जुलाई को शिमला में राज्य मंत्री के रूप में शपथ ली थी। हिमाचल प्रदेश में वीरवार को कोरोना संक्रमण के 12 मामले सामने आए हैं। जिला सिरमौर में छह लोग संक्रमित पाए गए हैं। हमीरपुर जिला में भी संक्रमण के चार मामले सामने आए हैं। इसके अलावा शिमला और चंबा में एक-एक मामला सामने आया है। इसके अलावा 39 मरीज स?वस?थ हुए हैं। इनमें सोलन जिला से 24, शिमला और मंडी से पांच-पांच, कुल?लू से दो व बिलासपुर के तीन लोगों ने कोरोना संक्रमण को मात दे दी है। प्रदेश में कोरोना की रफ्तार कुछ धीमी पडऩे लगी है। बुधवार को बहुत दिन बाद 37 पॉजिटिव मामले ही आए। पिछले कई दिन से रोजाना 80 से ज्यादा मामले सामने आ रहे थे। प्रदेश में 52 संक्रमितों ने कोरोना को मात दी है। इसके साथ ही प्रदेश में अब तक 1766 कोरोना संक्रमित कोरोना को मात देकर

स्वस्थ हो चुके हैं। अभी तक 60.54 फीसद व्यक्ति स्वस्थ हो चुके है। प्रदेश में कोरोना को मात देने वाले 52 कोरोना संक्रमितों में 25 सिरमौर से, सात मंडी से, कांगड़ा व ऊना से छह-छह, सोलन से चार, चंबा से तीन और शिमला से एक स्वस्थ हुआ है। कोरोना के 37 नए मामलों में चंबा में 17, सोलन में आठ, ऊना से छह, कांगड़ा चार और शिमला में दो नए मामले आए हैं। सोलन में कोरोना के आठ मामले आए, जिनमें छह अर्की में और दो मामले बद्दी से हैं। उधर, चंबा जिला के भरमौर के लाहल गांव में 31 जुलाई को नवविवाहिता के पॉजिटिव आने के बाद कंटेनमेंट जोन में शामिल किए गए कुछ वार्ड को अब प्रशासन ने बफर जोन में तबदील किया है। बीते सप्ताह ही नवविवाहिता के पॉजिटिव आने के बाद पूरी पंचायत को कंटेनमेंट जोन बनाया गया था। उसके प्राथमिक संपर्क में आने वाले सभी लोगों की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद भरमौर प्रशासन ने कंटेनमेंट व बफर जोन में बदलाव किया है।

केंद्र सरकार के मूंग व मूंगफली खरीदने के निर्णय से किसानों के चेहरे खिले

झुंझुनू/एजेंसी। राजस्थान में केंद्र सरकार के किसानों से मूंग और मूंगफली खरीदने के निर्णय से किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। सहकारी समिति झुंझुनू के डिप्टी रजिस्ट्रार संदीप शर्मा ने आज बताया कि केंद्र सरकार ने फिलहाल मूंग एवं मूंगफली का समर्थन मूल्य तय किया है। सात हजार 196 रूपये प्रति क्विंटल की दर से मूंग एवं पांच हजार 275 रूपये प्रति क्विंटल की दर से मूंगफली खरीदी जाएगी। हालांकि अभी उनको लिखित में कोई आदेश नहीं मिला है, आदेश आते ही वह इसकी तैयारी शुरू कर देंगे। किसानों की मांग पर सरकार को बाजरे के समर्थन मूल्य तय करने के लिए भी लिखा जाएगा। पिछले वर्षों में खरीफ सीजन से जिले में किसानों का रुझान मूंगफली की बुवाई के प्रति बढ़ा है। मूंग का उत्पादन तो जिले में पहले से ही अच्छा होता है। झुंझुनू जिले में सबसे ज्यादा बुवाई बाजरे

की फसल की होती है। किसानों का कहना है कि सरकार को बाजरे का समर्थन मूल्य भी तय करना चाहिए। क्योंकि अभी बाजरे का समर्थन मूल्य तय नहीं किया गया है। जबकि इस बार बाजरे की फसल बहुत अच्छी होने की संभावना जताई जा रही है। कृषि विभाग के अधिकारियों के अनुसार इस बार जिले में मूंग की बुवाई का लक्ष्य 55 हजार हैक्टेयर का रखा गया था। लेकिन बरसात के अभाव में महज 30 हजार हैक्टेयर भूमि पर ही मूंग की बुवाई हो सकी है। वहीं मूंगफली का लक्ष्य महज आठ हजार हैक्टेयर की बुवाई का रखा गया था, लेकिन बुवाई 17 हजार 500 हैक्टेयर में हुई है। इसके अलावा बाजरा एक लाख 80 हजार हैक्टेयर, चंवला 20 हजार हैक्टेयर में, कपास 16 हजार 200 हैक्टेयर में, ग्वार 44 हजार हैक्टेयर में फसल की बुवाई की गई है।

संक्षिप्त समाचार

दिल्ली में अब एक घंटे अधिक खुलेंगी शराब की दुकानें

नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने शहर में शराब की दुकानें अब एक घंटे अधिक खोलने का फैसला किया है। अधिकारी ने बताया कि इस कदम से सरकार के राजस्व में भी इजाफा होगा।आबकारी विभाग की ओर से बृहस्पतिवार को जारी आदेश के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी में अब शराब की दुकानें सुबह 10 से रात 10 बजे तक खुलेंगी। पहले दुकानें रात नौ बजे बंद हो जाती थीं। आदेश में कहा, ''दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की राज्य कार्यकरी समति के अध्यक्ष द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए दिल्ली सरकार ने 31 जुलाई 2020 से एल-6, एल-7, एल-8, एल-9 और एल-10 शराब की दुकानों को अब सुबह 10 से रात नौ की बजाय सुबह 10 से रात 10 बजे तक खोलने की अनुमति दी है। यह स्थिति तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक जारी रहेगी।''दिल्ली में 863 शराब दुकानें हैं, जिनमें से 475 का संचालन दिल्ली स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, दिल्ली टूरिज्म एंड ट्रांसपोर्टेशन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, दिल्ली स्टेट सिविल सप्लाइज कॉरपोरेशन और दिल्ली कंज्यूमर कोऑपरेटिव होलसेल स्टोर करते हैं। वहीं करीब 389 दुकानें निजी हैं।

भाजपा ने की दिल्ली दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन की सदस्यता रद्द करने की मांग

नई दिल्ली। दिल्ली दंगों की साजिश रचने की बात पुलिस के सामने स्वीकार करने के बाद आम आदमी पार्टी के सस्पेंडेड पार्षद ताहिर हुसैन को लेकर फिर से राजनीति गरमा गई है. ताहिर हुसैन के मुद्दे को लेकर भाजपा नेता लगातार आम आदमी पार्टी (आप) पर हमलावर हैं. अब भाजपा ने पूर्वी दिल्ली नगर निगम से पार्षद ताहिर हुसैन की सदस्यता रद्द करने की मांग उठाई है. इसके लिए मेयर को पत्र लिखने की तैयारी है. भाजपा की दिल्ली यूनिट के मीडिया संयोजक (कन्वीनर) नीलकांत बख्शी ने कहा, 'दिल्ली पुलिस की इंटेरोगेशन रिपोर्ट के मुताबिक, दंगों की साजिश रचने में ताहिर हुसैन ने अपनी भूमिका स्वीकार कर ली है. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह अपनी पार्टी के पार्षद का अब किस मुंह से बचाव करेंगे? दिल्ली को दंगों की आग में झोंकने को लेकर उन्हें जवाब देना चाहिए.' भाजपा नेता नीलकांत ने कहा कि 'जनवरी, फरवरी से लेकर निगम (कॉर्पोरेशन) की लगातार चार बैठकों में ताहिर की मौजूदगी नहीं थी. जब फरवरी में दंगे हुए थे, तब निगम की बैठकों में ताहिर नहीं जाते थे, इससे साफ पता चलता है कि वह तब दंगे की साजिश रचने में लगे थे. नियम है कि अगर तीन बैठकों में लगातार कोई पार्षद बिना किसी उचित कारण के गायब रहता है तो सदस्यता रद्द करने की व्यवस्था है. अब भाजपा मेयर को पत्र लिखकर इस मामले में कार्रवाई करने की मांग करेगी.' बता दें कि दिल्ली पुलिस की इंटेरोगेशन रिपोर्ट के मुताबिक, ताहिर हुसैन ने यह बात स्वीकार की है कि उन्होंने अपनी छत पर कांच की बोतल, पेट्रोल, एसिड और पत्थर आदि इकट्ठे किए थे. ताहिर हुसैन ने हिंसा भड़काने के लिए अपने परिचित खालिद सैफी को सड़कों पर लोगों को जुटाने की जिम्मेदारी दी थी. उत्तर पूर्वी दिल्ली नगर निगम के वार्ड 59, नेहरू विहार से पार्षद ताहिर हुसैन के दिल्ली दंगों में घिरने पर बीते फरवरी में आम आदमी पार्टी ने सस्पेंड कर दिया था.

मृत्यु दर कम करने में प्लाज्मा थैरेपी कारगर नहीं, लोगों की उम्मीदों पर फिर सकता है पानी

नई दिल्ली। एम्स दिल्ली ने एक परीक्षण में पाया है कि प्लाज्मा थैरेपी कोरोना के मृत्यु दर को कम करने में कारगर नहीं है। एम्स ने 30 मरीजों पर किए गए परीक्षण के आधार पर ये अनुमान लगाया है। डाक्टरों ने पाया कि मृत्यु दर के मामले में कोई लाभ नहीं है, लेकिन एक बड़े अध्ययन में थैरेपी से जीवित रहने की संभावना में सुधार देखा गया। बता दें कि इन दिनों कोरोना से ठीक हो जाने वाले लोगों के शरीर से प्लाज्मा लेकर संक्रमित लोगों के इलाज पर काफी जोर दिया जा रहा, लेकिन अब एम्स की ये स्टडी लोगों की उम्मीदों पर पानी फेर सकती है। डाक्टरों ने कहा कि आपको पता नहीं होगा कि आप बहुत बीमार हैं, लेकिन फिर अगर कोई कोरोना पॉजिटिव शख्स के संपर्क में आता है तो उसे टेस्ट के लिए जाना चाहिए। लोग ये भी न भूलें कि उन्हें डाक्टरों की सलाह पर ऑक्सीमीटर का इस्तेमाल करना चाहिए। एम्स के निदेशक डा. रणदीप गुलेरिया ने कहा कि ये प्रारंभिक विश्लेषण है। 15 मरीजों के दो समूह थे, जिन पर प्लाज्मा थैरेपी की प्रभावशीलता को जानने के लिए एक परीक्षण किया गया। एक समूह को सामान्य उपचार दिया गया, जबकि दूसरे को सामान्य उपचार के अलावा प्लाज्मा भी दिया गया। डा. रणदीप गुलेरिया ने कहा कि परीक्षण में हमने पाया कि मृत्यु दर दोनों समूहों में समान थी। मरीजों को बहुत अधिक लाभ नहीं थे। उन्होंने आगे कहा कि हमें अभी कुछ भी निष्कर्ष निकालने के लिए उस पर और अधिक सबूत चाहिए। वर्तमान परीक्षण से पता चलता है कि प्लाज्मा थैरेपी सुरक्षित है। इससे किसी मरीज को कोई नुकसान नहीं होता है। लेकिन उसी समय में यह बहुत प्रभावी नहीं है। बता दें कि कोरोना से ठीक हो चुके मरीजों के शरीर से लिए गए प्लाज्मा को कोरोना के एक्टिव मरीजों के शरीर में डाला जाता है। इससे उस मरीज के शरीर में कोरोना से लड़ने की एंटीबॉडी बन जाती है।

भ्रष्टाचार के आरोपी आप नेता को पार्टी ने किया निलंबित

नई दिल्ली। राजधानी की बुराड़ी विधानसभा में भ्रष्टाचार में लिप्त आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता को उसके पदों से निलंबित कर दिया गया है। साथ ही साथ उसकी पार्टी की सदस्यता भी रद्द कर दी गई है। नौकरी के नाम पर पैसे मांगने का ऑडियो सामने आने के बाद पार्टी के आला नेताओं द्वारा यह कार्यवाई की गई है। बता दें कि आम आदमी पार्टी के बुराड़ी विधानसभा के उपाध्यक्ष से संबंधित एक ऑडियो आया है जिसमें कुछ पैसों की डिमांड की जा रही है। उसको देखते हुए बुराड़ी विधानसभा से विधायक संजीव झा ने इस पर एक्शन लेते हुए उनको पार्टी से निलंबित कर दिया है। उनका कहना है कि आम आदमी पार्टी का जन्म भ्रष्टाचार मुक्त भारत के लिए हुआ है यदि कोई भी व्यक्ति भ्रष्टाचार में लिप्त पाया जाता है चाहे वह आम आदमी पार्टी का सदस्य ही क्यों ना हो उसका पार्टी से कोई भी संबंध नहीं होगा। इसलिए आम आदमी पार्टी के उपाध्यक्ष पद पर आसीन श्रवण यादव से संबंधित एक ऑडियो मिलने पर उसकी पार्टी की सदस्यता निरस्त कर दी गई है और उनको सभी पदों से निलंबित किया गया है। कुछ दिन पहले बुराड़ी हॉस्पिटल की शुरुआत गोविंद केयर सेंटर के तौर पर हुई है। 800 बेड का यह हॉस्पिटल फिलहाल साढ़े 400 बेड के कोविड-19 सेंटर के तौर पर शुरू किया गया है जहां पर एक एजेंसी द्वारा लोगों की नौकरियां लगवाई जा रही हैं। अब इसी मामले में भ्रष्टाचार की बू भी आने लग गई है। बुराड़ी का यह हॉस्पिटल अभी लोगों के लिए पूरी तरीके से शुरू भी नहीं हुआ है और इसमें नौकरी लगवाने के नाम पर बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार शुरू हो गया है।

दिल्ली सरकार का जॉब पोर्टल 'रोजगार बाजार' का नया मॉडल : गोपाल राय

नई दिल्ली (ओपन सर्च)
देश की राजधानी में कोरोना वायरस के संक्रमण के फैलाव में पिछले कुछ सप्ताहों में कमी आई है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस सफलता को 'दिल्ली मॉडल' से जोड़ते हैं। इसके साथ ही केजरीवाल ने जॉब्स डॉट दिल्ली डॉट जीओवी डॉट ईन नाम से पोर्टल लॉन्च कर दिया। मुख्यमंत्री ने इस बाबत कहा था कि इस पोर्टल का नौकरी देने वाले और नौकरी की चाह रखने वाले दोनों ही फायदा उठा सकते हैं। दिल्ली के श्रम मंत्री गोपाल राय ने शुक्रवार को पत्रकार वार्ता में कहा कि कोरोना काल में दिल्ली में बहुत बड़ी संख्या में लोगों को बेरोजगारी का सामना करना पड़ा। वर्कर्स गांव चले गए थे। क्राइसिस शुरू हो गई, ऐसे में दिल्ली सरकार ने जॉब पोर्टल की शुरुआत की है।

ये रोजगार बाजार में नया मॉडल है, अभी तक 22 लाख जॉब पोस्ट की गयी हैं। इनकी वेरिफिकेशन के लिए टास्क फोर्स बनाया और इनमें से साढ़े तीन लाख को कैंसिल किया गया। गोपाल राय ने बताया कि दस लाख लोगों को जॉब मिल गयी है। आज की तारीख में नौ लाख जॉब्स हैं, लेकिन जॉब सीकर्ज की संख्या इससे कम है। रोजगार बाजार के बारे में दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय ने हाल ही में बताया था कि वेबसाइट पर जाकर रजिस्टर कर लें। जिन्हें नौकरी चाहिए वो अपनी जानकारी इस पर डाल सकते हैं। जिनके पास वैकेंसी है, वे अपनी डिटेल्स डाल सकते हैं। इसके लिए कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है। कोई दलाल इसके लिए पैसे मांगता है तो कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है। ये पूरी तरह निःशुल्क है। कॉलेज से निकलने वाले बच्चे भी वहां रजिस्टर करें जिससे रोजगार मिल सके। उन्होंने बताया कि साइट कैसे काम करेगी, इसका एक वीडियो भी जारी किया गया है।

दूषित जलापूर्ति को ले बुराड़ी की जनता में रोष

नई दिल्ली.एजेंसी। दूषित जलापूर्ति और जलभराव बुराड़ी की बड़ी समस्या बनी हुई है। यह कहना है निगम का चुनाव लड़ चुके कांग्रेस के सीनियर नेता आदेश भारद्वाज का। उनका कहना है कोरोना काल में जनता अन्य समस्याओं से वैसे ही परेशान है। ऐसे में जलभराव और दूषित जलापूर्ति नें लोगो का जीना हराम कर दिया है। वे कहते हैं दूषित जलापूर्ति से जहाँ लोगो के जलजनित बिमारियों से पीड़ित होने का खतरा है वहीं कई कालोनियों में जल भराव से निकलना बड़ना भी मुश्किल हो गया है। पैदल चलना तो बेहद मुश्किल है ही वाहनों को आने जाने में भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आदेश नें इस बाबत मुक्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल को लिखे खत में आशंका जताई है यदि जलभराव समस्या का समाधान नहीं किया गया तो क्षेत्र में मलेरिया, डेंगू पावं पसार सकता है।

डेंजर जोन में शामिल अन्ना नगर की झुग्गियां होंगी शिफ्ट, डूसिब बना रहा योजना

नई दिल्ली.एजेंसी। राजधानी के आईटीओ स्थित अन्ना नगर की झुग्गियों को जल्द वहां से हटाया जाएगा। इन्हें दो चरणों में शिफ्ट करना है। पहले डेंजर जोन में आज गई 50 झुग्गियों को यहां से शिफ्ट किया जाएगा जबकि दूसरे चरण में बाकी झुग्गियों को यहां से हटाकर और कहीं शिफ्ट किया जाएगा।

पिछले दिनों हुई तेज बारिश के बाद यहां करीब 11 झुग्गियां नाले में बह गई थी। हालांकि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ लेकिन कई झुग्गियां चपेट में आ गई। घटना के बाद से करीब 100 झुग्गियों के लोग स्कूल और अन्य जगहों पर शरण लेने के लिए विवश हो गए हैं। इन झुग्गियों को लेकर दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (डूसिब) योजना तैयार कर रहा है। योजना के तहत उन्हें तुरंत राहत देने की कोशिश की जा रही है। इसे लेकर लगातार बैठकों का दौर जारी है। दिल्ली सरकार के शहरी विकास मंत्री सत्येंद्र जैन की अध्यक्षता में हुई बैठक में झुग्गियों को शिफ्ट करने पर विचार किया जा रहा है। अन्ना नगर में करीब एक हजार झुग्गियां हैं। इन सभी झुग्गियों को यहां से शिफ्ट करने की योजना बनाई जा रही है।

योजना के तहत पहले 50 उन झुग्गियों को यहां से शिफ्ट किया जाएगा जो सीधे तौर पर प्रभावित हुई या पानी में बह गई हैं। अन्ना नगर की झुग्गियां रेलवे की जमीन पर भी है ऐसे में इन्हें शिफ्ट करने से पहले रेलवे के साथ भी उच्च स्तरीय बैठक होनी है। सरकार इस संबंध में योजना बना चुकी है।

बता दें कि दिल्ली में हुई मॉनसून की पहली तेज बारिश में 11 झुग्गियां यहां नाले के तेज बहाव में बह गई जबकि 2 दर्जन से ज्यादा झुग्गियां में दरार आ गई है।

opensearch

किसान कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं पूर्व राष्ट्रीय महासचिव भाजपा में हुए शामिल

नई दिल्ली.एजेंसी। किसान कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं उत्तराखंड के पूर्व मंत्री रामकुमार वालिया, किसान कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय महासचिव संजय कपूर एवं दिगम्बर जैन समाज दिल्ली के अध्यक्ष पीडी जैन शुक्रवार को अपने समर्थकों के साथ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। प्रदेश भाजपा कार्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान दिल्ली भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने पार्टी का पटका पहनाकर उनका स्वागत किया।

इस अवसर पर आदेश गुप्ता ने कहा कि भाजपा परिवार का निरंतर विस्तार हो रहा है। रामकुमार वालिया के पार्टी में शामिल होने से पार्टी को नई दिशा और मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा कि चुनाव के वक्त लोगों का पार्टी में शामिल होना स्वाभाविक है लेकिन आम दिनों में भी कई ऐसे संगठन हैं जो भाजपा परिवार से जुड़ रहे हैं। भाजपा द्वारा समाज के लिए किए जाने वाले विकास कार्यों में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम मिलकर दिल्ली की समस्याओं पर संघर्षात्मक एवं सकारात्मक रूप से काम करेंगे। हमें मिलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को साकार करना है और देश को आगे बढ़ाना है। राजकुमार वालिया ने कहा कि जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश का कुशल नेतृत्व किया है उससे हम लोग प्रभावित होकर भाजपा में शामिल हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के अंदर न तो कोई नेतृत्व है और न ही कोई व्यवस्था रह गई है। कांग्रेस परिवारवाद की पार्टी बनती जा रही है, जहां जमीन से जुड़े लोगों को अपमानित किया जाता है। पार्टी के नकारात्मक वातावरण में हमारा दम घुट रहा था।

12 साल की मासूम से हैवानियत करने का आरोपी गिरफ्तार, पहले से दर्ज हैं मर्डर, लूट जैसे केस

नई दिल्ली.एजंसी
दिल्ली पुलिस ने पश्चिम विहार इलाके में 12 साल की बच्ची के यौन उत्पीड़न के मामले में आरोपी कृष्ण को गिरफ्तार किया है. आरोपी दिल्ली के मंगोलपुरी का रहने वाला है. पीरागढ़ी इलाके में ही किसी फैक्ट्री में काम करता है. आरोपी पर पहले एक मर्डर, लूट और छीनाझपटी के कई मामले दर्ज हैं. पुलिस अभी आरोपी का नाम नहीं बता रही है. आरोपी ने बच्ची से बदला लेने के लिए इस घिनौनी वारदात को अंजाम दिया है क्योंकि बच्ची ने उसे लूटपाट करते देख लिया था. डीसीपी शालिनी सिंह के मुताबिक 33 वर्षीय कृष्ण के खिलाफ पोक्सो के तहत मामला दर्ज किया है. आरोपी के खिलाफ कुल 4 केस रजिस्टर्ड हैं. बता दें कि दिल्ली के पश्चिमी विहार

इलाके की रहने वाली बच्ची से मंगलवार शाम को दुष्कर्म का मामला सामने आया था. बच्ची के साथ बहुत ही हैवानियत के साथ दुष्कर्म किया गया है. इसकी वजह से उसकी हालत बहुत ज्यादा गंभीर है. बच्ची को गंभीर चोटें आई है. बच्ची बेहोशी की हालत में है. एम्स में बच्ची का उपचार कर रहे डॉक्टर्स के मुताबिक मंगलवार को जब वह बच्ची अस्पताल आई थी, तब उसकी बहुत ज्यादा बुरी हालत थी. उसकी सर्जरी की गई है. डॉक्टर बच्ची की जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं. हालांकि अभी उसकी हालत नाजुक है. डॉक्टर ने बताया है कि अभी 24 से 48 घंटे तक और इंतजार करना पड़ेगा तभी पता लगेगा कि वह खतरे से बाहर आती है या नहीं. वहीं इससे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एम्स में भर्ती दुष्कर्म पीड़ित बच्ची और उसके परिजनों से मुलाकात की और डॉक्टरों से उसके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली. बच्ची के परिजनों को दिल्ली सरकार की तरफ से 10 लाख रुपये की आर्थिक मदद दी जाएगी. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा, 'उम्मीद करते हैं कि बच्ची सही सलामत ठीक होकर यहां से जाएं. मैंने पुलिस कमिश्नर से भी बात की उन्होंने भी बताया कि पुलिस पूरी कोशिश कर रही है कि दोषियों को पकड़ा जाए और सख्त कार्रवाई की जाए. दिल्ली सरकार अच्छे वकील खड़े करके दोषी को सख्त से सख्त सजा दिलवाएगी.' केजरीवाल ने कहा, 'एक 12 साल की बच्ची के साथ हैवानियत भरी वारदात की जानकारी ने आत्मा को अंदर तक झकझोर दिया है।

मास्क-सैनिटाइजर्स को आवश्यक वस्तु की श्रेणी में लाने की मांग, हाईकोर्ट में याचिका दायर

नई दिल्ली.एजेंसी
मास्क और सैनिटाइजर को आवश्यक वस्तुओं की सूची से हटा कर उन पर 18 फीसदी जीएसटी लगाने के फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। ये याचिका सामाजिक कार्यकर्ता गौरव यादव और वकील आरती सिंह ने दायर की है। याचिका में मांग की गई है कि वित्त मंत्रालय और जीएसटी काउंसिल अल्कोहल से बने सैनिटाइजर पर जीएसटी की दर 18 फीसदी से घटाकर 5 या 12 फीसदी की जाए।

याचिका में मांग की गई है कि केंद्र सरकार के 13 मार्च और 30 जून के उस नोटिफिकेशन को बहाल किया जाए जिसमें मास्क और सैनिटाइजर को आवश्यक वस्तुओं की सूची में शामिल किया गया था। याचिका में मास्क और सैनिटाइजर की कीमत 8, 10, 16 और 100 रुपये फिक्स करने के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती गई है। याचिका में कहा गया है कि जीएसटी घटाने से मास्क और सैनिटाइजर्स की कीमतें कम होंगी।

याचिका में कहा गया है कि कोरोना वायरस के संक्रमण के बाद दुनिया भर के हेल्थकेयर प्रोफेशनल्स की ओर से जारी एडवाइजरी में हाथों को धोते रहने और चेहरे पर मास्क लगाने के निर्देश जारी किए गए।

याचिका में आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 2ए का जिक्र किया गया है जिसमें कहा गया है कि केंद्र सरकार को जो वस्तु लोगों के लिए जरुरी लगती है उसे आवश्यक वस्तु की श्रेणी में डालती है। केंद्र सरकार आवश्यक वस्तु की सप्लाई को रेगुलेट करती है ताकि उनकी कोई किल्लत नहीं हो।

दिल्ली में दरिंदगी की शिकार बच्ची का केस फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाने की मांग

नई दिल्ली.एजेंसी

दिल्ली में दरिंदगी की शिकार बच्ची के परिवार वालों से शुक्रवार को भाजपा नेताओं ने भेंट की। दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष आदेश कुमार गुप्ता ने परिवार के साथ इलाज कर रहे चिकित्सकों से भी बात की। उन्होंने मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में करने की मांग की है ताकि बच्ची को जल्द से जल्द न्याय मिल सके। भाजपा ने अरविंद केजरीवाल सरकार से दस लाख की सहायता राशि को और बढ़ाने की मांग की है।

प्रदेश अध्यक्ष आदेश कुमार गुप्ता के नेतृत्व में पार्टी नेता शुक्रवार को एम्स पहुंचे। दरिंदगी की शिकार 12 वर्षीय बालिका का एम्स में ही उपचार चल रहा है। यहां आदेश गुप्ता ने बच्ची के स्वास्थ्य की जानकारी डॉक्टरों से ली। परिवार के लोगों से घटना के बारे में बात की। बाद में मीडिया से बात करते हुए प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, आज एम्स पहुंचकर दरिंदगी की शिकार हुई बच्ची के परिजनों से मुलाकात की और डॉक्टर से भी बात कर बच्ची की वर्तमान स्थिति के बारे में जाना। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मेरी मांग है कि 10 लाख की सहायता राशि को बढ़ाएं व केस की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में की जाए ताकि दोषियों को जल्द से जल्द सजा मिल सके।

बच्ची के साथ दरिंदगी की घटना, दिल्ली के पश्चिम विहार में बुधवार की शाम हुई थी। 12 वर्षीय बालिका गंभीर रूप से घायलावस्था में लावारिस हालत

में मिली थी। बच्ची के शरीर और प्राइवेट पार्ट्स में गहरे घाव से हालत गंभीर होने पर अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस मामले में दिल्ली महिला आयोग पुलिस से जवाब तलब कर चुकी है।

दिल्ली में कोरोना वायरस के 1192 नए मामले आए सामने, 23 लोगों की मौत

नई दिल्ली.एजेंसी। दिल्ली में शुक्रवार को कोरोना वायरस के 1192 नए मामले सामने आए हैं। जबकि 23 लोगों की मौत हो चुकी है। इसी के साथ कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,42,723 हो गई है। राजधानी में शुक्रवार को 1108 लोगों को डिस्चार्ज किया गया है। दिल्ली में अब तक कुल 1,28,232 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। कोरोना वायरस से दिल्ली में अब तक 4082 लोगों की मौत हो चुकी है। राजधानी में अभी 10409 सक्रिय मरीज हैं।

सम्पादकीय...

ओपन सर्च

एक नजर शहीदों के जन्मदाताओं पर भी

पूरे देश में कारगिल दिवस के अवसर पर शहीदों को श्रद्धांजलि देकर उनके गौरवमयी बलिदान को याद करते हुए देश के अमर सपूतों के प्रति कृतज्ञता पेश की गयी। प्रत्येक वर्ष 26 जुलाई को कारगिल दिवस मनाए जाने के अतिरिक्त भी विभिन्न अवसरों पर देश के शहीदों को याद किया जाता है तथा कृतज्ञ राष्ट्र उनकी अमूल्य कुर्बानियों के प्रति आभार व्यक्त करता है। जिस समय देश का कोई सपूत शहीद होता है तथा सेना विभागीय स्तर पर उसके पार्थिव शरीर को शहीद के घर भेजती है उस समय अंतिम संस्कार के वक्त आम तौर पर कुछ अधिकारी या नेता आदि वहां मौजूद रहकर उसका मान सम्मान करते व तिरंगे में लिपटे शहीद के पार्थिव शरीर को श्रद्धांजलि भेंट करते हैं। इस अवसर पर मीडिया द्वारा शहीद के बारे में, उसके शौर्य, उसकी रुचियाँ उसके परिवार आदि के विषय में समाज को अवगत करता रहता है। बाद में केंद्र सरकार, राज्य सरकारें तथा सेना अपने अपने स्तर पर शहीदों के माता-पिता तथा उसके बीवी बच्चों को उनके जीवन बसर के लिए सांत्वना स्वरूप नकदी, मकान के लिए प्लाट, पेट्रोल पंप, परिवार के किसी सदस्य को सरकारी सेवा, गैस एजेंसी, पेंशन आदि से नवाजते हैं। इस तरह का सहयोग निश्चित रूप से किसी की जान का बदल तो नहीं हो सकता परन्तु इससे शहीदों के परिजनों को अपनी जिन्दिगी गुजारने में कुछ राहत जरूर मिल जाती है। यदि शहीद शादी शुदा होता है तो सभी की हमदर्दी उसकी पत्नी के साथ सबसे अधिक इसलिए होती है क्योंकि वह विधवा हो गयी, उसका जीवन का सहारा चला गया और यदि बच्चे हैं तो उन बच्चों के पालन पोषण का बोझ उसके कन्धों पर आ गया। इसलिए सरकार यदि सरकारी सेवा देने पर विचार करती है तो पहली प्राथमिकता के आधार पर पत्नी को ही सरकारी सेवा देने के लिए चुना जाता है। नकदी की राशि जरूर पत्नी व माता पिता के बीच बाँट दी जाती है परन्तु पेट्रोल पंप व प्लाट आदि भी प्रायः पत्नी के नाम ही आवंटित होते हैं। जबकि पेंशन की राशि में से भी केवल 30 प्रतिशत वृद्ध माता-पिता को मिलती है शेष 70 प्रतिशत पत्नी को। परन्तु आम तौर पर ऐसा देखा गया है की जब तक सरकार द्वारा प्रदत्त सभी सरकारी सांत्वनाएं अथवा सुविधाएँ शहीद फौजी की पत्नी व माता पिता सबको मिल नहीं जातीं तब तक तो शहीद के परिवार में सब कुछ ठीक ठाक नजर आता है और उसका पूरा परिवार एक सुर में बातें करता है और एक सी भाषा बोलता है परन्तु जैसे ही सब कुछ हासिल हो जाता है उसी समय परिवार में तनाव बढ़ना शुरू हो जाता है और फौजी की पत्नी अपने सॉस ससुर से मुंह मोड़ने लगती है। इस तरह के अनेक मामले देखने को मिलेंगे कि शहीद की पत्नी ने अपने दिवंगत पति की शहादत पर मिलने वाली सभी सरकारी सहायताओं को भी ले लिया। यहाँ तक कि सरकारी नौकरी भी ले ली और बाद में अपनी दूसरी शादी भी कर ली। अपने सॉस ससुर यानी शहीद के बुजुर्ग माता पिता से भी रिश्ता खत्म कर अपनी नई दुनिया बसा ली और उसी में अपने जीवन की खुशी ढूंढ ली। जबकि माता पिता अपनी संतान को खोने के गम को सारी उम्र सहने के लिए उसी की यादों करे सहारे जीने को मजबूर रहते हैं। पिछले दिनों कारगिल दिवस के शहीदों को श्रद्धांजलि देते समय एक बार फिर ऐसे ही एक शहीद के बुजुर्ग माता पिताका दर्द उनकी आँखों से आंसुओं की शक्ल में छलका। उन्होंने भी यही बताया कि उनके बेटे की शहादत के बाद उनकी विधवा बहू 70 प्रतिशत सरकारी पेंशन की भी मालिक बनी, अनेक सरकारी सहायता भी ले ली, सरकारी नौकरी भी लेली और सब कुछ मिल जाने के बाद बुजर्गों को उनके हाल पर छोड़ कर दूसरी शादी कर अपनी नई नवेली दुनिया में जा बसी। निश्चित रूप से अब वह युग नहीं रहा जब स्त्रियों अपने पति की मृत्यु के बाद उसके नाम पर या उसके बच्चों की परवरिश को ही अपने जीवन का लक्ष्य मान कर अपना जीवन बसर कर लिया करती थीं। इस सुविधा भोगी युग में कोई युवा विधवा महिला भी यदि दूसरा विवाह करना चाहे तो यह उसका अधिकार भी है और उसके घर के लोग भी अपनी विधवा बेटी को सारी उम्र अकेले जीवन बसर करने के लिए नहीं छोड़ना चाहते। परन्तु किसी शहीद के मां बाप के पास अपने बेटे की यादों के सहारे अपना शेष जीवन जीने बसर करने के सिवा दूसरा कोई विकल्प नहीं रहता। ले देकर बेटे की शहादत के बाद मिलने वाली राशि या सुविधाएँ ही उनके जीवन बसर करने का साधन होती हैं। परन्तु चूंकि पत्नी ही अपने पति की वास्तविक उत्तराधिकारी मानी जाती है इसलिए सरकारी सुविधाओं पर ज्यादा अधिकार भी उसी का होता है जो सरकार उसे देती भी है। हालांकि कुछ परिवार ऐसे भी मिल जाएंगे जहाँ शहीद की विधवा को बेटी जैसा प्यार व सम्मान देकर सारी उम्र शहीद की विधवा को अपने घर की इज्जत समझ कर रखा जाता है और उसे पूरे अधिकार प्राप्त होते हैं। ऐसे में सरकार को कोई ऐसा मापदंड जरूर निर्धारित करना चाहिए जिससे शहीद की विधवा के दूसरी शादी करने की स्थिति में शहीद के मां-बाप के अधिकारों का भी हनन न हो और वे भी आर्थिक रूप से अपना जीवन यापन ठीक ढंग से कर सकें। सरकार को चाहिए की पेट्रोल पंप या प्लॉट जैसी कोई सुविधा यदि दी जाती है तो वह अकेले शहीद की पत्नी के नाम होने के बजाए शहीद के मां बाप के नाम भी हो तथा उससे मिलने वाले लाभ के दोनों ही हकदार हों। और यदि बहू दूसरा विवाह करे तो पेट्रोल पंप या प्लॉट जैसी सुविधाओं और पेंशन आदि से उसे वंचित कर दिया जाए। क्योंकि विधवा ने तो अपना दूसरा विवाह कर अपने जीवन का सहारा ढूंढ लिया परन्तु शहीद के जन्मदाताओं के पास जीवन गुजारने के लिए शहीद की यादों के अलावा केवल वही सुविधाएं व सांत्वनाएं होती हैं जो सरकार द्वारा शहादत के बाद दी जाती हैं।

धर्मनिरपेक्षता और राम मंदिर

प्रो. एनके सिंह

अयोध्या में राम मंदिर के लिए लोगों ने करीब 470 वर्षों तक इंतजार किया। अब जबकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके निर्माण के लिए नींव-पत्थर रखने वाले हैं, निर्माण में देरी करने के लिए कानाफूसी का अभियान शुरू हो गया है। यह कहा जा रहा है कि वैश्विक महामारी कोरोना वायरस को देखते हुए मंदिर निर्माण के लिए यह अनुकूल समय नहीं है। अयोध्या के रास्ते में इसी प्रकार की अन्य बाधाएं भी खड़ी की जा रही हैं।

सबसे बड़ा फंसाने का रास्ता यह है कि तथाकथित धर्मनिरपेक्षता की ओर से बाधा डालते हुए कहा जा रहा है कि चूंकि सरकार का धर्म से कोई लेना-देना नहीं है, इसलिए उसे धार्मिक गतिविधियों में भाग नहीं लेना चाहिए। अब चूंकि शुरुआत हो चुकी है, इसलिए धर्मनिरपेक्षता का प्रश्न हमेशा के लिए सुलझा देना चाहिए। समझने के लिए यह महत्त्वपूर्ण है कि राम मंदिर निर्माण का शिलान्यास समारोह भय और घृणा की आग को नहीं भड़काएगा, जो कि मंदिर तैयार होने के बाद जारी रह सकता है। हमें इससे पूरी समझ और पक्के इरादे के साथ निपटना चाहिए। संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द को शामिल करने की पृष्ठभूमि विचित्र है।

मौलिक संविधान में यह कहीं नहीं लिखा गया है कि देश धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी होगा। वास्तव में प्रारूप समिति ने इस पर विस्तृत विचार किया था। जवाहर लाल नेहरू और डा. भीमराव अंबेडकर इस शब्द को संविधान की प्रस्तावना में डालने के पक्ष में नहीं थे। यहां मैं नेहरू के विचारों का उद्धरण देना चाहूंगा जो कि देश द्वारा तैयार किए गए भविष्य के चार्टर के पीछे मुख्य दिमाग थे। वह उच्च तौर पर बौद्धिक तथा भावुक व्यक्ति थे जिनके बारे में महात्मा गांधी भी सोचते थे कि वह भारत का नेतृत्व करने के लिए पूरी तरह सक्षम हैं। संविधान के निर्माण से इसी तरह कई अन्य समान विवेक व प्रतिभा वाले लोग भी जुड़े थे। डा. राजेंद्र प्रसाद भी एक दक्ष तथा निपुण हस्ती थे जो भारतीय संस्कृति से काफी हद तक प्रभावित थे।

समस्या धर्म पर आधारित आरक्षण के प्रति कटिबद्धता के कारण भी उत्पन्न हुई। जवाहर लाल नेहरू इस पक्ष में थे कि धर्म की स्वतंत्रता का गारंटी मौलिक अधिकारों में दी जानी चाहिए। नागरिकों की समानता के स्पष्ट प्रावधान के साथ इसे संगति से बाहर माना गया। किस प्रकार धर्म के आधार पर विशेष व्यवहार करने के लिए संकेत करने के वास्ते प्रयोग किया गया? अंततः संविधान के बाहर धर्मनिरपेक्षता को छोड़ देना दूरदर्शिता माना गया। वैयक्तिक विश्वास को कोई मसला नहीं माना गया। यह वह था जो राजेंद्र प्रसाद ने नेहरू को तब बताया जब उन्होंने सोमनाथ मंदिर के धार्मिक समारोह से परहेज करने के लिए धर्मनिरपेक्षता की याद दिलाई। राजेंद्र प्रसाद ने नेहरू की सलाह को अनदेखा कर दिया था। वर्ष 1976 में इंदिरा गांधी के पास लोकसभा में भारी बहुमत था। इसी के चलते उन्होंने वामपंथ के प्रति अपना झुकाव दर्शाने के लिए संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद को जोड़ दिया।

भारतीय संस्कृति और इतिहास के प्रति नेहरू के प्यार को उन्होंने ग्रहण नहीं किया। दिमाग संबंधी संताप के बावजूद नेहरू का देश से बड़ा प्यार था। हिंदू महासभा ने उनकी मिश्रित व्यक्तित्व के रूप में व्याख्या की और कहा, 'वह शिक्षा से अंग्रेज, संस्कृति से मुसलमान और जन्म से हिंदू थे।' नेहरू की विफलताओं और तीन बड़ी गलतियों के बावजूद मैं ऐसे विचारों से सहमत नहीं हूं। वह नेता व बौद्धिक रूप में एक महान व्यक्ति थे। उनकी पहली गलती यह थी कि उन्होंने भारत का विभाजन स्वीकार कर लिया। दूसरी बड़ी गलती चीन के साथ भारत की लड़ाई में देश की रक्षा में विफल होना तथा कृष्णा मेनन का समर्थन करना था।

उनकी तीसरी बड़ी गलती यह थी कि वह कश्मीर का मसला संयुक्त राष्ट्र के हवाले करने के लिए सहमत हो गए। लेकिन दिल से वह भारत से प्यार करते थे। वे लोग जो कि आरोप लगाते हैं कि नेहरू संस्कृति में मुसलमान थे, उन्हें डिस्कवरी ऑफ इंडिया तथा उनके अन्य सृजन को पढ़ना चाहिए। वह अपने देश की इतनी चिंता करते थे कि उनकी इच्छा थी कि उनकी मृत्यु के बाद उनकी अस्थियां गंगा व अन्य नदियों में विसर्जित की जाएं। उनके लिए धर्मनिरपेक्षता का अर्थ वही है जो बाद में नरेंद्र मोदी ने 'सर्वे भवंतु सुखिना' के वैदिक संदेश के साथ व्याख्यायित किया है। यही कारण है कि उन्होंने अमरीकी पत्रकार अर्नाल्ड एम. चायलिस को बताया कि भारत में मुसलमान हिंदुओं की संतति हैं।

धर्मनिरपेक्षता को नेहरू ने इस वर्णक्रम में देखा, किंतु उनके अनुयायियों ने इसे विवादास्पद नजरिए से देखा। धर्मनिरपेक्षता सभी के साथ समान व्यवहार का आश्वासन देती है तथा यह अल्पसंख्यकों के साथ पक्षपात का समर्थन नहीं करती है। लेकिन धीरे-धीरे वोट बैंक की राजनीति ने सभी के लिए चिंता को घटा दिया तथा बराबर के अधिकारों की उपेक्षा होने लगी, साथ ही वोट एकत्र करने के लिए एक समुदाय को प्रलोभित किया जाने लगा। यह भुला दिया गया कि भारत की हिंदू संस्कृति है और अन्य धर्मों के साथ बराबर का व्यवहार होगा, लेकिन उनका विशेष समर्थन नहीं होगा। अल्पसंख्यकों के लिए जो समान था, वह मुस्लिम समर्थक बन गया।

परिभाषा ऐसे बदल गई कि मनमोहन सिंह ने कह दिया कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। पक्षपातपूर्ण आचरण कभी भी धर्मनिरपेक्षता नहीं हो सकता। मैं कांग्रेस व भाजपा के सदस्यों को याद दिलाना चाहूंगा कि उन्हें वह नहीं भूलना चाहिए जो नेहरू ने कहा था। 'भारत हिंदू सचेतना की भूमि है जो कि हमेशा के लिए हिंदुओं के लिए स्वाभाविक घर होगा।' मेरे लिए धर्मनिरपेक्षता देश की प्राधान्य संस्कृति है जो अल्पसंख्यकों को से समान आचरण की बात करती है। अंसारी, अयोध्या के राम मंदिर भूमि विवाद में जो वादी थे, को मंदिर शिलान्यास समारोह में बुलाया गया और वह इसमें शामिल भी हुए। यह धर्मनिरपेक्षता की सच्ची आत्मा है।

अब राम राज्य की उम्मीद

अयोध्या में राम मंदिर का भूमि-पूजन संपन्न हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने भूमि-पूजन कर पूजित शिलाएं रखीं। नींव में पवित्र मिट्टी और जल के साथ बहुत कुछ रखा गया है। अब नींव तभी खुलेगी, जब मंदिर निर्माण की प्रक्रिया विधिवत शुरू हो जाएगी। इसी जगह गर्भगृह बनेगा, जहां रामलला की मूर्ति की प्राण-प्रतिष्ठा की जाएगी। अब एक आध्यात्मिक, राजनीतिक और विवादास्पद यात्रा पर विराम लग जाना चाहिए। अब करीब तीन साल की अवधि के बाद भव्य, दिव्य राम मंदिर सामने दिखाई देगा। आंखों के साथ-साथ आत्मा और अनुभूति को चरम सुख और आनंद मिलेगा। यह प्रभु श्रीराम की पाषाण-मूर्ति, भव्य इमारत और एक देवावतार का ही अध्याय नहीं है। राम भारत के हैं, सबमें हैं और राम में भारत है। अब संदर्भ राष्ट्रीय भावना और एकता, अखंडता का है। श्रीराम उनके प्रतीक हैं। भूमि-पूजन के पवित्र अनुष्ठान के दौरान संपूर्ण भारत ही नहीं, अमरीका, ब्रिटेन, जापान और कई देश 'राममय' हुए, उनके गीत-भजन गाए और थिरकते भी रहे। यह टीवी चौनल्स की तस्वीरों से स्पष्ट हो चुका है। असंख्य देशवासी और रामभक्त भावुक भी हुए होंगे! 'राममय' होने की कुछ उपमाएं प्रधानमंत्री ने भी अपने संबोधन में दीं। प्रधानमंत्री ने राम मंदिर आंदोलन की तुलना देश के स्वतंत्रता-संघर्ष से की। दोनों ही आंदोलनों में देश के प्रत्येक भू-भाग ने संघर्ष में हिस्सा लिया, लाखों भारतवासियों ने बलिदान दिए, अंततः देश और प्रभु राम आजाद हुए।

अयोध्या से आगे अब क्या?

अजीत द्विवेदी

opensearch

समान नागरिक संहिता का वादा जरूर अभी अधूरा है पर उसे भी पूरा करने की शुरुआत हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने तीन तलाक के मुद्दे को असंवैधानिक बना दिया है और उसके बाद पिछले साल सरकार ने इसे कानूनी रूप से अपराध भी बना दिया।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल का पहला सवा साल भारतीय जनसंघ और भाजपा की ओर से किए गए गए वादों को पूरा करने का समय रहा। जनसंघ और भाजपा ने मुख्य रूप से तीन वादे किए थे। पहला और सबसे पुराना वादा अनुच्छेद 370 खत्म करने का था, जो जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय ने किया था। मोदी सरकार ने पिछले साल अगस्त में यह वादा पूरा कर दिया। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण भाजपा का दूसरा वादा था उसे भी पूरा कर दिया गया। समान नागरिक संहिता का वादा जरूर अभी अधूरा है पर उसे भी पूरा करने की शुरुआत हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने तीन तलाक के मुद्दे को असंवैधानिक बना दिया है और उसके बाद पिछले साल सरकार ने इसे कानूनी रूप से अपराध भी बना दिया। मुस्लिम समाज में एक से ज्यादा शादियों का मामला भी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। सो, अब सवाल है कि अनुच्छेद 370 खत्म करने और अयोध्या में राम मंदिर का शिलान्यास होने के बाद अब सरकार और भाजपा दोनों क्या करेंगे? क्या सरकार दो टूक अंदाज में समान नागरिक संहिता बनाने की पहल कर सकती है? इसके लिए सभी धर्मों के पर्सनल लॉ को खत्म करना होगा। भाजपा के पास इस तरह के एजेंडे की कमी नहीं है। सरकार ने नागरिकता कानून में संशोधन कर दिया है और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर बनाने की संभावना भी हवा में है। यह अपने आप में बड़ा एजेंडा है। इसी तरह जनसंख्या नियंत्रण की बातें शुरू हो गई हैं और हो सकता है कि आने वाले दिनों में बढ़ती हुई आबादी पर काबू पाने के लिए जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाया जाए। अयोध्या में राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़े एक अहम नेता विनय कटियार ने दो दिन पहले एक अखबार को दिए इंटरव्यू में कहा कि अयोध्या की तरह ही मथुरा और काशी में ऐतिहासिक भूल सुधार होनी है। ध्यान रहे अयोध्या आंदोलन के समय विश्व हिंदू परिषद का नारा था– अयोध्या तो झांकी है, मथुरा–काशी बाकी है।

भारत का एक पुराना मुद्दा पाक अधिकृत कश्मीर, पीओके को भारत में मिलाने का है। जम्मू कश्मीर विधानसभा में और लोकसभा में सीटें खाली रखी गई हैं कि पीओके का विलय भारत में होगा तो इन सीटों पर चुनाव कराया जाएगा। भाजपा के लिए यह भी बड़ा और भावनात्मक मुद्दा है। इसके अलावा चीन के साथ सीमा पर चल रहा टकराव भी है, जिसे हमेशा के लिए खत्म करने का प्रयास किया जा सकता है। कुल मिला कर भाजपा के पास धार्मिक, राजनीतिक, सामरिक और राष्ट्रीयता के कई मुद्दे हैं, जिन पर आगे राजनीति हो सकती है। ये सारे मुद्दे बरसों की चर्चाओं से लोगों के मानस में बैठे हुए हैं। भले अनुच्छेद 370 या राम मंदिर की तरह इनकी बड़ी भावनात्मक अपील नहीं है पर इनका भी महत्व है।

इस समय बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी कमान में भाजपा ऐसे मुकाम पर खड़ी है, जहां वे संतोष के साथ कह सकते हैं कि उन्होंने अपने सारे वादे पूरे कर दिए। भाजपा ने अपनी ऐतिहासिक भूमिका निभा दी। यह मामूली बात नहीं है। विपक्ष दशकों से इस बात के लिए भाजपा का मजाक बनाता रहा था कि मंदिर निर्माण का क्या हुआ! भाजपा का नारा था कि 'मंदिर वहीं बनाएंगे' तो विपक्ष के नेता तंज करते हुए इसमें जोड़ते थे कि 'तारीख नहीं बताएंगे'। अब तारीख बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि मंदिर निर्माण शुरू हो गया। इसी तरह विपक्ष कुछ भी कहता रहे, अनुच्छेद 370 भी खत्म हो गया। जिन लोगों को राजनीति से या भाजपा के एजेंडे से ज्यादा मतलब नहीं है उन्होंने भी संतोष की सांस ली होगी कि चलो ये सारे अध्याय खत्म हुए। तभी सवाल है कि इसके आगे अब क्या? क्या ये सारे काम करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शांति के साथ बैठ जाएंगे कि उन्होंने अपनी ऐतिहासिक भूमिका निभा दी, अब जो होना है सो हो? ऐसी उनकी फितरत नहीं है। वे शांति से बैठने की बजाय नए एजेंडे पर काम शुरू कर सकते हैं या कुछ बचे हुए पुराने एजेंडे को नए सिरे से धार दे सकते हैं। पर यह काम हमेशा मुश्किल होता है। हर व्यक्ति या राजनीतिक दल का इतिहास ऐसा है कि उसे अपनी ऐतिहासिक भूमिका निभाने के बाद नेपथ्य में जाना होता है। कांग्रेस आज अप्रासंगिक हुई है तो कारण यहीं है कि उसने अपनी ऐतिहासिक भूमिका निभा दी है और उसके बाद समय की जरूरत के हिसाब से उसने खुद को रिइन्वेंट नहीं किया। वह अपनी ऐतिहासिक भूमिका निभाने के बाद इस मुगालते में रही कि इसी से उसका काम हमेशा चलता रहेगा।

तभी उसने खुद को रूटीन के काम में ढाल लिया। वह इस बात को नहीं समझ पाई कि रूटीन के काम लोगों को बहुत आकर्षित नहीं करते हैं, भले उनसे उनका भला ही क्यों न हो होता हो! इस मामले में लालू प्रसाद की मिसाल दे सकते हैं। उन्होंने 15 साल तक सामाजिक न्याय की राजनीति की। वे दलित, पिछड़े, अकलियत के मसीहा बने और उनको आवाज देने की राजनीति करते रहे। जब तक वे इस छवि में रहे तब तक उनको वोट की चिंता नहीं करनी पड़ी। परंतु केंद्र में रेल मंत्री बनने के बाद उन्होंने जाति व धर्म के भावनात्मक मुद्दे को काफी हद तक छोड़ दिया। वे रूटीन के काम में लग गए। उनको इस बात का चस्का लग गया कि वे रेलवे का कायाकल्प करेंगे। वे हार्वर्ड और आईआईएम में लेक्चर देने लगे और उधर बिहार में लोगों को लग गया कि लालू प्रसाद अपनी ऐतिहासिक भूमिका निभा चुके हैं और अब बिहार को इसके आगे ले जाने के लिए नए चेहरे की जरूरत है। सो, लोगों ने नीतीश कुमार को चुन लिया। इस मामले में लोगों की आकांक्षाएं अलग ही तरह से काम करती हैं। वे जिससे बहुत ज्यादा संतुष्ट हो जाते हैं उसे ही हटा देते हैं। उन्हें हमेशा कुछ नए की जरूरत होती है। तभी नरेंद्र मोदी और भाजपा के सामने एक बड़ी चुनौती है। वे भी अपनी ऐतिहासिक भूमिका निभा चुके हैं। व्यापक हिंदू समाज गदगद है। सब संतुष्ट हैं कि नरेंद्र मोदी ने वह कर दिया, जो कोई नहीं कर सका था। उन्होंने सारे वादे पूरे कर दिए। इसके बाद मोदी के लिए नया एजेंडा तय करना और उस पर लोगों को उद्वेलित करना बहुत आसान नहीं होगा। दूसरा खतरा यह है कि अगर वे रूटीन की राजनीति पर उतरते हैं यानी जैसे लालू प्रसाद ने रेलवे का विकास शुरू किया था उस तरह मोदी देश का विकास शुरू करते हैं तो हो सकता है कि लोग बोर हो जाएं। वे कुछ नए, रोचक और रोमांचक एजेंडे की तलाश में दूसरे की ओर देखने लग सकते हैं।

नई शिक्षा नीति और भाषा का सवाल

डा. राकेश राणा

नई शिक्षा नीति में कई नए आयाम शामिल है। यह राष्ट्य शिक्षा नीति देश को व्यापक शैक्षिक सुधारों की ओर लेकर जायेगी। इस दृष्टि से नई नीति व्यापक बदलाव की महत्वाकांक्षा के साथ आयी है। जिसमें बहुत कुछ नया भी है और सार्थक प्रभाव डालने वाला भी। अगर इन सब प्रावधानों पर ससमय और ईमादार प्रतिबद्धता के साथ अमल किया गया तो गुणात्मक परिवर्तनों की उम्मीद है। हम अभी नई सदी के शुरुआती दौर में है और संयोग से बहुत सारा घटनाक्रम भी हमारे पक्ष में है। इसका लाभ हम अपनी कमजोरियों को दूर करने और सामाजिक-आर्थिक चुनौतियों से निपटने के लिए शिक्षा के जरिए उठा सकते है। बदलता शैक्षिक परिदृश्य बड़े बदलाव को आयोजित कर सकता है। नई शिक्षा नीति में नया बहुत कुछ है वैसे तो, पर जो सबसे अहम कदम है वह मातृ भाषा को लेकर लिया गया निर्णय है। त्रिभाषा फार्मुर्ला नयी शिक्षा नीति को नए क्षैतिज प्रदान करने वाला साबित होगा। मातृ भाषा अगर प्रारम्भिक शिक्षण का आधार बनती है तो समाज के सभी वर्गों की सहभागिता देश और समाज के विकास में स्वत: ही बड़े स्तर पर बढ़ेगी।

बेहतर शैक्षिक संवाद के लिए मातृ भाषा अहम् है। शिक्षा को अपने समाज के अनुरुप संचालित करने और अपनी भाषाओं में शिक्षण करने से ज्ञान के नए क्षैतिज खुलेंगें। नवाचार के नए-नए आयाम उभरेगें। मातृ भाषा में चिंतन सृजन का परवाज प्रदान करता है। वास्तव में भाषाएं विचारों, विचारधाराओं, कल्पनाओं और अपने व्यापक सामाजिक-दर्शन की स्पष्टता का माध्यम बनती हैं। भारतीय चिंतन दृष्टि व्यापक और गहन होते हुए भी आधुनिक ज्ञान, विज्ञान और वैचारिकी में कोई सफल पायदान स्थापित नहीं कर पायी है। भाषाई दृष्टि से पंगु बने रहना हमारी शिक्षा व्यवस्था की पहले से ही बड़ी कमजोरी रही है। सरकार की नई शिक्षा नीति-2019 में भाषाई आधार को मजबूत बनाते हुए मातृ भाषा को तरजीह मिलना एक सशक्त राष्ट्र के निर्माण की दिशा में सार्थक कदम है। मातृभाषा हमें दूसरां के विचारों, भावों और भाषाओं को सीखने व समझने में सहज रुप से समर्थ बनाती चलती है।

दुनियां के सभी विकसित देशों में शिक्षा का माध्यम मातृ भाषाएं रही हैं।

अनुभव बताते हैं कि बच्चा मातृभाषा में शिक्षा को आसानी से ग्रहण करता है। मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा हासिल करने वाले विद्यार्थी की अधिगम क्षमता ज्यादा होती है। अपनी भाषा के साथ जो मजबूत मनोबल जुड़ा होता है उससे भी बच्चे के व्यक्तित्व विकास में इजाफा होता है उसकी तार्किक दृष्टि भी विकसित होती है। अध्ययन बताते है कि मातृ भाषा में बच्चे का शिक्षण उसके मानसिक, भावनात्मक और नैतिक विकास को भी प्रभावित करता है। मातृभाषा में शिक्षण सरल और सहज बन जाता है। परिणाम बच्चे शनैः शनैः रुचिकर क्षेत्रों में दक्षता हासिल कर अपने क्षेत्र में महारत हासिल कर लेते है। बच्चे में यह दक्षता ही नए विचारों को पनपाने में और उसकी अंतर्दृष्टि को विकसित करने में काम आती है। परिणाम बच्चा में न ही तो विषय की परिपक्कव समझ बन पाती और न ही भाषा की। क्योंकि बचपन की पूरी उर्जा और क्षमता को सीखने के दबाव बिखेर देते है।

नई राष्ट्य शिक्षा नीति-2019 सहभागिता आधारित, बहुआयामी, हितपरक, लोक-केन्द्रित ओर समावेशी प्रक्रिया के तहत राष्ट्य आकांक्षाओं और उददेश्यों को पूरा करने वाली महत्वाकांशी योजना है। नई शिक्षा नीति को तय समय सीमा के अंतर्गत और प्रतिबद्धता के साथ लागू किया जाए तो यह भारत को एक ज्ञानमय समाज में रुपांतरित करने वाली सफल योजना साबित होगी। हमारे पास आज दुनियां तक पहुंचने का शानदार सु-अवसर है जो अब से पहले शायद कभी नहीं था। हमारे पास आज ऐसा नेतृत्व है, जो इन तमाम बदलावों को साकार करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ है। हमें सिर्फसकारात्मक प्रयासों के साथ सहीं दिशा में बढ़ने की आवश्यकता है। आने वाला समय हमें दुनियां का सबसे युवा देश बनाने वाला है। अपनी इस युवा जनशक्ति का सदुपयोग कर हम महाशक्ति बनने की दिशा में सार्थक हस्तक्षेप कर सकते है। अपने युवाओं को नये कौशलों और नये ज्ञान से लैस कर दुनियां में अपना परचम लहरा सकते है। भारत सुपरपावर बनने के अपने सपने को साकार कर सकता है। इस महान उददेश्य को पाने की दिशा में विज्ञान, तकनीक और अकादमिक क्षेत्रों में नवाचार और अनुसंधान करने के अभियान को तीव्र करना होगा। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का आधार बनने वाली इस नयी शिक्षा नीति से इस दिशा में बड़ी उममीद है। नयी शिक्षा नीति के साथ जुड़े नए आयाम, नए मुकाम हासिल कराने में महती भूमिका निभायेगें। नई शिक्षा नीति जिस तरह से मातृ भाषा के प्रति प्रतिबद्धता के साथ नए भारत के निर्माण का आधार प्रस्तुत करती है। इससे नव-सृजन और नवाचारों के जरिए समाज में नए प्रतिमान उभरेंगें। मातृभाषा जब शिक्षा का माध्यम बनेगी तो मौलिकता समाज में रचनात्मकता का अभियान छेड़ेगी। नई नीति में शिक्षा अधिकार कानून के नए क्षैतिजों का विस्तार समाज के कमजोर तबकों को मुख्य धारा में समावेशित करने के नए अवसर उपलब्ध करायेगा। शिक्षा को सतत् विकास और एक ज्ञानवान समाज बनाने की ओर उन्मुख करेगा। भाषा और गणित को नई नीति में प्राथमिकता मिलना बच्चों में लेखन के कौशल और नवाचार का संचार करेगा। सृजनात्मक गतिविधियों का वातावरण पैदा करेगा। शिक्षण के परम्परागत तौर-तरीकों को नई टैक्नोलॉजी के जरिए नवोन्मेष के साथ कहानी, नाटक, समूह चर्चाएं, लेखन और स्मार्ट डिसप्ले बोर्ड, अध्ययन, अध्यापन और संवाद की नई संस्कृति का विकास नई शिक्षा नीति को वाकई नया तो बनाता है। तकनीकी के इस्तेमाल को प्रोत्साहित करने की पहल कोरोना संकट के कारण नई नीति को इस दृष्टि से और अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में ले जायेगी। इसके लिए कंप्यूटर, लैपटॉप व फोन आदि के जरिए शिक्षण को रोचक बनाने में टैक्नोलॉजी शिक्षा के भावी परिदृश्य को बहुत हद तक बदल भी देगी। नई शिक्षा नीति में यशपाल समिति की सिफारिश 'लर्निंग विदाउड बर्डन' और एनसीएफ-2005 को बहुत हद तक स्वीकार लेना सकारात्मक सोच का संकेत है। प्राथमिक स्तर पर शिक्षा में बहुभाषिकता की पहल अति प्रशंसनीय है। नई शिक्षा नीति-2019 ऐसे शिक्षकों को अहमियत देती है जो स्थानीय भाषा जानते-समझते हों। मौलिकता को मथकर रचनात्मक परिणामों में परिवर्तित करने की क्षमता रखते हो। नई जरुरतों के हिसाब से नवाचार और नव-माध्यम ऑलाइन शिक्षण की टैक्नोलॉजी का सदुपयोग कर समय के साथ समाज को सशक्त करने का आहवाहन कर सके।

संक्षिप्त समाचार

ब्राजील में कोविड-19 से अब तक 98 हजार से अधिक लोगों की मौत

रियो डि जेनेरो। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस (कोविड-19) से गंभीर रूप से जूझ रहे लैटिन अमेरिकी देश ब्राजील में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना संक्रमण के 53,139 नये मामले सामने आने के साथ ही संक्रमितों की संख्या 29 लाख को पार कर 29,12,212 हो गयी है। ब्राजील के स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से गुरुवार देर रात जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटों के दौरान इस महामारी से 1237 लोगों की मौत होने से मृतकों की संख्या 98 हजार के आंकड़े को पार कर 98,493 पहुंच गयी है। इससे एक दिन पहले ब्राजील में कोरोना संक्रमण के 57,152 नये मामले सामने आये थे जबकि 1437 लोगों की मौत हुई थी। अमेरिका की जॉन हॉपकिन्स यूनिवर्सिटी के विज्ञान एवं इंजीनियरिंग केन्द्र (सीएसएसई) की ओर से जारी किए गए ताजा आंकड़ों के मुताबिक कोरोना संक्रमितों की संख्या के मामले में ब्राजील (29.12 लाख) पहले से ही अमेरिका (48.76 लाख) के बाद दूसरे स्थान पर है।

अमेरिकी राजदूत ने ईरान को दुनिया में आतंकवाद का नंबर एक प्रायोजक बताया

संयुक्त राष्ट्र। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका की राजदूत कैली क्राफ्ट ने ईरान को ''दुनिया में आतंकवाद का नंबर एक प्रायोजक'' बताया और रूस तथा चीन को आगाह किया कि अगर वे ईरान पर संयुक्त राष्ट्र हथियार प्रतिबंध लगाने वाले प्रस्ताव को बाधित करेंगे तो वे भी आतंकवाद के ''सह-प्रायोजक'' बन जाएंगे।राजदूत कैली क्राफ्ट ने बृहस्पतिवार को कहा कि संयुक्त राष्ट्र को उम्मीद है कि रूस और चीन ''आतंकवाद के नंबर एक प्रायोजक देश के सह-प्रायोजक नहीं बनेंगे'' और पश्चिम एशिया में शांति की महत्ता को पहचानेंगे।उन्होंने कहा कि हालांकि ईरान का समर्थन करने पर रूस और चीन के बीच भागीदारी बहुत स्पष्ट है। उन्होंने कहा, ''वे अपनी सीमाओं के बाहर केवल अराजकता, संघर्ष और अफरातफरी को बढ़ावा देने वाले हैं इसलिए हमें उन्हें अलग-थलग करना होगा।''अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पिओ ने बुधवार को एलान किया था कि उनका देश ईरान पर अनिश्चितकाल के लिए हथियार प्रतिबंध लगाने वाले प्रस्ताव पर अगले हफ्ते मतदान कराने की सुरक्षा परिषद से अपील करेगा।

चिली में कोरोना संक्रमण के 1947 नये मामले सामने आए

सैंटियागो। दक्षिण अमेरिकी देश चिली में भी वैश्विक महामारी कोरोना वायरस (कोविड-19) का प्रकोप लगातार बढ़ता ही जा रहा है। चिली में कोरोना संक्रमितों की संख्या 3,66,671 हो गयी है जबकि 9889 लोगों की इस महामारी से मौत हो चुकी है। चिली के स्वास्थ्य मंत्रालय ने गुरुवार देर रात बताया कि पिछले 24 घंटों के दौरान देश में कोरोना संक्रमण के 1947 नये मामले सामने आये हैं जबकि इस दौरान 97 मरीजों की मौत हुई है। कोविड-19 से संक्रमित होने के मामले में चिली विश्व में अब आठवें नंबर पर पहुंच गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक कोरोना के नये मामलों में 1383 मरीजों में इसके लक्षण हैं जबकि 403 मरीजों में इसका कोई लक्षण नहीं है। चिली में अब तक 3,40,168 लोग कोरोना संक्रमण से पूरी तरह ठीक हो चुके हैं जबकि इस समय देश में कोरोना के 16,614 सक्रिय मामले हैं। चिली की सरकार ने कहा है कि स्थिति में धीरे-धीरे सुधार हो रहा है और संक्रमण के नये मामलों में कमी आ रही है।

अमेरिका में कोविड-19 से अब तक 1.60 लाख लोगों की मौत

वाशिंगटन। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस (कोविड-19) से गंभीर रूप से जूझ रहे अमेरिका में इसके संक्रमण से 1.60 लाख से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिका में यह महामारी विकराल रूप ले चुकी है और अब तक 48 लाख से अधिक लोग इससे संक्रमित हो चुके हैं। अमेरिका की जॉन हॉपकिन्स यूनिवर्सिटी के विज्ञान एवं इंजीनियरिंग केन्द्र (सीएसएसई) की ओर से जारी किए गए ताजा आंकड़ों के मुताबिक अमेरिका में कोरोना से मरने वालों की संख्या 1,60,090 पहुंच गयी है जबकि संक्रमितों की संख्या 48 लाख को पार कर 48,81,974 हो गयी है। अमेरिका का न्यूयॉर्क, न्यूजर्सी और कैलिफोर्निया प्रांत कोरोना से सबसे बुरी तरह प्रभावित है। अकेले न्यूयॉर्क में कोरोना संक्रमण के कारण 32 हजार से अधिक लोगों की मौत हुई है। न्यूजर्सी में अब तक 15 हजार से अधिक लोगों की इस महामारी के कारण मौत हो चुकी है। कैलिफोर्निया में कोविड-19 से अब तक 10 हजार से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है।

ईरान दुनिया में आतंकवाद का नंबर एक प्रायोजक : अमेरिका

संयुक्त राष्ट्र। अमेरिका ने ईरान को दुनिया में आतंकवाद का नंबर एक प्रायोजक करार दिया है। साथ ही रूस और चीन को आगाह किया कि अगर वे ईरान पर हथियार प्रतिबंध लगाने के लिए संयुक्त राष्ट्र (यूएन) में लाए जाने वाले प्रस्ताव को बाधित करेंगे तो वे भी आतंकवाद के सह-प्रायोजक बन जाएंगे। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी दूत कैली क्राफ्ट ने गुरुवार को कहा कि उम्मीद है कि रूस और चीन आतंकवाद के नंबर एक प्रायोजक देश के सह-प्रायोजक नहीं बनेंगे। वे पश्चिम एशिया में शांति की अहमियत को समझेंगे। हालांकि ईरान का समर्थन करने पर रूस और चीन के बीच साझीदारी बेहद स्पष्ट है। उन्होंने कहा, वे (ईरान) अपनी सीमाओं के बाहर सिर्फ अराजकता, संघर्ष और अफरातफरी को बढ़ावा देने जा रहे हैं। इसलिए हमें उन्हें अलग-थलग करने की जरूरत है। इससे पहले बुधवार को अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोंपियो ने एलान किया था कि उनका देश ईरान पर अनिश्चितकाल के लिए हथियार प्रतिबंध लगाने वाले प्रस्ताव पर अगले हफ्ते मतदान कराने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से मांग करेगा।

अमेरिका में एक दिसंबर तक कोरोना से हो सकती है तीन लाख लोगों की मौत

वाशिंगटन। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस (कोविड-19) से गंभीर रूप से जूझ रहे अमेरिका में एक दिसंबर तक इसके संक्रमण के कारण करीब तीन लाख लोगों की मौत हो सकती है। वाशिंगटन यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ मेडिसिन विभाग के स्वास्थ्य मूल्यांकन संस्थान ने गुरुवार को एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर अपनी रिपोर्ट में इस बात का दावा किया है। विज्ञप्ति के अनुसार अमेरिका में एक दिसंबर तक कोविड-19 से मरने वालों की संख्या तीन लाख के करीब पहुंच सकती है। यदि लोग मास्क पहनने, शारीरिक दूरी जैसे अन्य आवश्यक नियमों का पालन करें तो करीब 70 हजार लोगों की जान बच सकती है। अमेरिका की जॉन हॉपकिन्स यूनिवर्सिटी के विज्ञान एवं इंजीनियरिंग केन्द्र (सीएसएसई) की ओर से जारी किए गए ताजा आंकड़ों के मुताबिक अमेरिका में कोरोना से मरने वालों की संख्या 1,60,000 के करीब पहुंच गयी है जबकि संक्रमितों की संख्या 48 लाख का आंकड़ा पार कर 48,76,790 हो गयी है।

इस्तांबुल : तुर्की के इस्तांबुल में लोग मुंह पर मास्क लगाकर सड़कों पर चलते हुए।

अमेरिका ने वीचैट के साथ लेन-देन पर लगाया प्रतिबंध

वाशिंगटन। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के मोबाइल ऐप वीचैट से संबंधित किसी किस्म के लेन-देन पर प्रतिबंध लगा दिया है। श्री ट्रंप ने इस संबंध में कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर कर दिए है। दस्तावेजों पर हस्ताक्षर के 45 दिनों के बाद वीचैट से संबंधित किसी भी तरह के लेनदेन पर प्रतिबंध लागू हो जाएगा।

उल्लेखनीय है कि चीन की सोशल मीडिया, मैसेजिंग एवं भुगतान ऐप्लीकेशन कंपनी वीचैट का अमेरिका समेत दुनियाभर में एक अरब से अधिक लोग इलेक्ट्रॉनिक भुगतान के लिए उपयोग करते है। टिकटॉक की तरह वीचैट भी अपने उपयोगकर्ताओं से सूचनाएं एकत्र करता है। इससे अमेरिका के लोगों के व्यक्तिगत और मालिकाना सम्पति से संबंधित डाटा के चीनी कम्युनिस्ट पार्टी तक पहुंचने का खतरा है।

अमेरिका में टिक-टॉक की कंपनी से लेन-देन पर लगा प्रतिबंध

वाशिंगटन/एजेंसी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर कर चीन के विवादित मोबाइल ऐप टिक-टॉक की कंपनी बाइटडांस से लेन-देन पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। यह प्रतिबंध कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए जाने के 45 दिनों के बाद से लागू होगा। श्री ट्रम्प ने गुरुवार देर रात इस कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए। इस कार्यकारी आदेश के मुताबिक अमेरिका में चीन की बाइटडांस कंपनी अथवा इससे जुड़ी अन्य कंपनियों के साथ किसी भी प्रकार के लेन-देन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अमेरिका में अब कोई भी व्यक्ति अथवा कंपनी बाइटडांस के साथ कोई लेन-देन नहीं कर पायेगी। कार्यकारी आदेश के मुताबिक चीन के मोबाइल ऐप के अमेरिका में प्रसार से [illegible] राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेश नीति और अर्थव्यवस्था को खतरा पैदा होता है। इसलिए ऐसे मोबाइल ऐप विशेष रूप से टिक-टॉक पर कार्रवाई करना आवश्यक है। यह कार्यकारी आदेश हस्ताक्षर होने के 45 दिनों बाद से लागू होगा। चीनी कंपनी बाइटडांस के इस ऐप पर लाखों अमेरिकी नागरिकों की निजी जानकारी चुराने का आरोप है जिसकी ट्रम्प प्रशासन जांच कर रहा है। गौरतलब है कि अमेरिकी नौसेना ने निजी सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए पिछले वर्ष अपने कर्मचारियों से सभी सरकारी उपकरणों से इस ऐप को हटाने का आग्रह किया था।

कोरोना से विश्व में 1.90 करोड़ से अधिक संक्रमित

बीजिंग/जिनेवा/नयी दिल्ली। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस (कोविड-19) का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है और इसके कारण अब तक 1.90 करोड़ से ज्यादा लोग संक्रमित हुए हैं तथा 713,813 लोगों की मौत हो चुकी है। कोविड-19 के संक्रमितों के मामले में अमेरिका दुनिया भर में पहले, ब्राजील दूसरे और भारत तीसरे स्थान पर है। वहीं इस महामारी से हुई मौतों के मामले में अमेरिका पहले, ब्राजील दूसरे, मेक्सिको तीसरे और ब्रिटेन चौथे स्थान पर है जबकि भारत मृतकों की संख्या के मामले में पांचवें स्थान पर है। अमेरिका की जॉन हॉपकिन्स यूनिवर्सिटी के विज्ञान एवं इंजीनियरिंग केन्द्र (सीएसएसई) की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार कोरोना से विश्व में 1[illegible],021,922 लोग संक्रमित हुए हैं तथा 71[illegible],813 लोगों की मृत्यु हुई है। विश्व

महाशक्ति माने जाने वाले अमेरिका में कोरोना से अब तक 4,882,270 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं तथा 160,091 लोगों की मौत हो चुकी है। ब्राजील में अब तक 2,912,212 लोग इसकी चपेट में आ चुके हैं जबकि 98,493 लोगों की मौत हो चुकी है। भारत में कोरोना के बढ़ते प्रकोप के बीच पिछले 24 घंटों में 49,769 लोग स्वस्थ हुए तथा 886 की मृत्यु हुई। इसके साथ ही देश में कोरोना से संक्रमित होने वाले लोगों की संख्या 20,27,074 तथा मृतकों का आंकड़ा 41,585 हो गया है। देश में इस समय कोरोना के 60,7384 सक्रिय मामले हैं। वहीं 1378105 लोग इस महामारी से ठीक हुए हैं। रूस कोविड-19 संक्रमित मामलों में चौथे नंबर पर है और यहां इसके संक्रमण से अब तक 870,187 लोग प्रभावित हुए हैं तथा 14,579 लोगों ने जान गंवाई है। दक्षिण अफ्रीका में कोरोना महामारी का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है जिसके कारण कोरोना से संक्रमित होने के मामले में दक्षिण अफ्रीका पांचवें स्थान पर पहुंच गया है। यहां इससे अब तक 538,184 लोग संक्रमित हुए हैं तथा 9,604 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं मेक्सिको में कोरोना से अब तक 462,690 लोग संक्रमित हुए हैं तथा इस वायरस से मरने वालों की संख्या 50,517 हो गयी हैं। पेरू में भी लगातार हालात खराब होते जा रहे है। यहां संक्रमितों की संख्या 447,624 हो गई तथा 20,228 लोगों की मौत हो चुकी है। कोविड-19 से संक्रमित होने के मामले चिली अब आठवें नंबर पर पहुंच गया है। यहां इससे अब तक 366,671 लोग संक्रमित हुए हैं और मृतकों की संख्या 9,889 है।

opensearch

फोर्टिस अस्पताल में एक कोविड पॉजिटिव मरीज की किडनी स्टोन सर्जरी सफलतापूर्वक संपन्न

नई दिल्ली। फोर्टिस हॉस्पिटल में एक 62 साल की कोविड पॉजिटिव मरीज की किडनी स्टोन सर्जरी सफलतापूर्वक संपन्न हुई। मरीज के दोनों गुर्दों में पथरी थी, जिसमें से एक बाईं मूत्रवाहिनी में प्रवेश कर गई थी और उसे तत्काल सर्जरी की आवश्यकता थी। मरीज की पहले दो एंजियोप्लास्टी हो चुकी थी और वह खून को पतला करने वाली दवाइयां भी ले रहे थे। फोर्टिस हॉस्पिटल बेंगलुरु के डॉ. मोहन केशवमूर्ति और डॉ. कार्तिक राव ने मरीज की जिंदगी बचाने के लिए उसकी सर्जरी की, क्योंकि इस मामले में जरा भी देरी उसकी जान जोखिम में डाल सकती थी। फोर्टिस अस्पताल में हेल्थकेयर कर्मियों के लिए पीपीई के पहनने और उतारने के लिए एक अलग जगह और मरीजों को लाने-ले जाने के लिए एक खास कॉरिडोर के साथ कोविड मामलों के लिए विशेष ओटी बुनियादी ढांचे के कारण यह आपातकालीन सर्जरी संभव हो पाई थी। आगे कोविड से जुड़े डॉक्टरों ने इस मरीज को कोविड के इलाज के लिए अपनी देखभाल में ले लिया। रोगी पेट के निचले हिस्से में असहनीय दर्द के साथ अस्पताल में आया था। उन्हें पेशाव करने में भी दिक्कत हो रही थी। पिछले दो दिनों से उसे दस्त हो रहे थे और उन्हें इस्कीमिक हृदय रोग भी था। उन्होंने सफलतापूर्वक होल्मियम लेजर लिथोट्रिप्सी का सामना किया जो कि मूत्र मार्ग में स्थित स्टोन को हटाने के लिए लेजर का उपयोग करने की एक विधि है। नियमित रोगियों की तुलना में, कोविड -19 वाले संदिग्ध या पुष्टि वाले रोगियों को अक्सर इलाज के बाद ज्यादा नियमित परीक्षण की आवश्यकता होती है। इसके अलावा उनमें पहले से मौजूद दूसरे रोगों पर भी कड़ी निगरानी जरूरी होती है। ऐसा देखा गया है कि दूसरे रोगों से ग्रस्त कोविड मरीजों में मृत्यु दर बिना किसी रोग के ग्रस्त कोविड रोगियों की अपेक्षा ज्यादा होती है। डॉ. कार्तिक राव, कंसल्टेंट यूरोलॉजी, यूरो-ऑन्कोलॉजी, एंड्रोलॉजी, ट्रांसप्लांट एंड रोबोटिक सर्जरी, फोर्टिस हॉस्पिटल, बैंगलोर कहते हैं, हमें तुरंत सर्जरी की तैयारी करनी थी क्योंकि मरीज की हालत बिगड़ रही थी। फोर्टिस अस्पताल में एक नियमित प्रोटोकॉल के रूप में, मरीज का नमूना एकत्र किया गया और उसे तुरंत कोविड परीक्षण के लिए भेजा गया था। सर्जरी के दिन यह पता चला कि रोगी कोविड पॉजिटिव था। मरीज को सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं हो रही थी और उसे ऑक्सीजन की मदद की आवश्यकता नहीं थी इसलिए मरीज की द्विपक्षीय डबल जे स्टेंटिंग के साथ लेफ्ट रिट्रोगेट इंट्ररीनर सर्जरी की गई।

जयशंकर और पोम्पिओ ने कोविड-19 एवं हिंद-प्रशांत को लेकर फोन पर की बातचीत

वाशिंगटन/एजेंसी। विदेश मंत्री एस जयशंकर और उनके अमेरिकी समकक्ष माइक पोम्पिओ ने फोन पर बात की, जिसमें उन्होंने कोरोना वायरस वैश्विक महामारी से निपटने तथा हिंद-प्रशांत क्षेत्र समेत अंतरराष्ट्रीय चिंता के मामलों के संबंध में द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय सहयोग को लेकर चर्चा की। विदेश मंत्रालय के प्रधान उप प्रवक्ता कैले ब्राउन ने बताया कि दोनों नेताओं ने हिंद-प्रशांत और विश्वभर में समृद्धि एवं शांति कायम रखने और सुरक्षा मजबूत करने में भारत एवं अमेरिका के संबंधों की महत्ता की बात दोहराई। भारत और अमेरिका ने संसाधन समृद्ध हिंद-प्रशांत क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर बातचीत की। इस क्षेत्र में चीन अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। इस मामले पर 2018 में गोवा में हुई भारत-अमेरिका समुद्री सुरक्षा वार्ता के तीसरे दौर में भी विस्तार से बातचीत हुई थी। अमेरिका रणनीतिक रूप से अहम भारत-प्रशांत क्षेत्र में भारत को बड़ी भूमिका निभाने के लिए प्रोत्साहित करता रहा है। ब्राउन ने कहा, ''दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय मामलों में निकट सहयोग जारी रखने एवं इस वर्ष बाद में अमेरिका भारत 'टू प्लस टू' मंत्रिस्तरीय वार्ता और चतुष्पक्षीय वार्ता को आगे बढ़ाने पर सहमति जताई।'' भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान ने हिंद-प्रशांत में अहम समुद्री मार्गों को चीन के प्रभाव से मुक्त करने के लिए नई रणनीति विकसित करने के मकसद से नवंबर 2017 में चतुष्पक्षीय गठबंधन को आकार दिया था। पहली 'टू प्लस टू' वार्ता सितंबर 2018 में नयी दिल्ली में हुई थी।

बेरूत विस्फोट में अब तक 149 की मौत

बेरूत। लेबनान की राजधानी बेरूत के पोत पर हुए विस्फोट में मरने वालों की संख्या बढ़कर 149 हो गयी है। लेबनान के ओरियंट ली-जॉर नामक समाचार पत्र ने शुक्रवार को अपनी एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी। मीडिया रिपोर्ट में इससे पहले मृतकों की संख्या 137 बताई जा रही थी। लेबनान की राजधानी बेरूत के पोत पर मंगलवार शाम को हुए भीषण विस्फोट के कारण करीब आधा शहर बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। विस्फोट के कारण 5000 से अधिक लोग घायल हुए हैं। लेबनान के अधिकारियों ने कहा है कि पोत पर यह भीषण धमाका 2750 टन अमोनियम नाइट्रेट के कारण हुआ था, जो असुरक्षित तरीके से पोत के एक गोदाम में रखा गया था।

ट्रंप के खिलाफ दुष्कर्म के केस में देरी की कोशिश नाकाम

न्यूयॉर्क/एजेंसी। न्यूयॉर्क की एक जज ने राष्ट्रपति ट्रंप पर दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली एक महिला के मुकदमे में कथित रूप से देरी की कोशिश को नाकाम करते हुए तल्ख टिप्पणी की है। जज ने कहा कि ट्रंप का राष्ट्रपति पद पर होना उनको इस केस से नहीं बचा सकता है। यही नहीं न्यायाधीश ने अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के हाल की एक व्यवस्था का भी हवाला दिया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप न्यूयॉर्क के अभियोजक की आपराधिक जांच से बच नहीं सकते हैं। मैनहैट्टन की जज वर्ना सॉन्डर्स ने कहा कि यही सिद्धांत ई जीन कैरोल के मानहानि संबंधी मुकदमे पर भी लागू होता है। इसमें ट्रंप के वकील ने दलील दी थी कि संविधान राष्ट्रपति को राज्य की अदालतों में दायर मुकदमे में घसीटे जाने से रोकता है। इस पर जज वर्ना सॉन्डर्स ने कहा कि नहीं... ऐसा नहीं है। न्यायाधीश के इस ताजा फैसले के बाद कैरोल को अपना जारी रखने की इजाजत मिल गई है। बता दें कि ई जीन कैरोल संभावित साक्ष्य

के तौर पर ट्रंप के डीएनए जांच की अपील कर रही हैं। कैरोल का आरोप है कि साल 1990 के दशक में ट्रंप ने उनसे दुष्कर्म किया था। यही नहीं इस केस को वापस लेने पर मजबूर करने के लिए उन्हें अपमानित भी किया गया था।

किसी अमेरिकी कंपनी के टिकटॉक खरीद लेने से सुरक्षा चिंताएं घटेंगी : प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ

ह्यूस्टन/एजेंसी। चीन के स्वामित्व वाले वीडियो साझा करने वाले ऐप टिकटॉक का अनिश्चित भविष्य और एक अमेरिकी कंपनी द्वारा उसकी संभावित खरीद से अमेरिकी उपयोगकर्ताओं के डेटा तक पहुंच को लेकर राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताएं घट सकती हैं। प्रौद्योगिकी क्षेत्र के एक विशेषज्ञ ने यह बात कही है। वर्जीनिया टेक स्कूल ऑफ कम्युनिकेशन में मल्टीमीडिया जर्नलिज्म के सह प्रध्यापक, माइक होर्निंग ने कहा कि टिकटॉक के विकास ने सुरक्षा विशेषज्ञों के बीच चिंताएं बढ़ा दी हैं क्योंकि इसका अल्गोरिद्म बहुत शक्तिशाली है जो उपयोगकर्ताओं की विशेषताओं के आधार पर रूचि के अनुसार कंटेंट तैयार करता है।उनकी इन टिप्पणियों से एक दिन पहले ही प्रौद्योगिकी क्षेत्र की दिग्गज कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने कहा था कि उसके

सीईओ सत्य नडेला और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच हुई चर्चा के बाद वह टिकटॉक के अमेरिकी कारोबार को खरीदने के लिए बातचीत जारी रखेगी। माइक्रोसॉफ्ट के रेडमॉन्ड मुख्यालय से जारी बयान उस वक्त आया था जब ट्रंप ने कहा था कि वह राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों को लेकर अमेरिका में टिकटॉक को प्रतिबंधित करने के लिए शासकीय आदेश या आपात आर्थिक शक्तियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। होर्निंग ने कहा, 'ऐप को लोकप्रियता इसलिए हासिल हुई कि क्योंकि यह एक शक्तिशाली अल्गोरिद्म का इस्तेमाल करता है जो उपयोगकर्ता की विशेषताओं के आधार पर उनके लिए उनकी पसंद का कंटेंट तैयार करता है। यह अल्गोरिद्म उपयोगकर्ताओं के बारे में ऐसे परिष्कृत डेटा को एकत्र करता है जो सरकार एवं निगमों दोनों के लिए आकर्षक होता है।' उन्होंने कहा, 'हालांकि, कंपनी इसे लेकर बहुत पारदर्शी नहीं थी कि वह आपका डेटा किसको बेचती है। उनके डेटा एकत्र करने के तरीके का आकलन दिखाता है कि निजी डेटा को सैकड़ों अन्य कंपनियों के साथ साझा किया जा सकता है।' होर्निंग ने कहा कि क्योंकि यह ऐप चीन का है, इसके इसके डेटा साझा करने के तरीके चीनी कानून के प्रति संवेदनशील हैं जिनके तहत डेटा को चीनी अधिकारियों को उपलब्ध कराना जरूरी होता है। इससे सुरक्षा चिंताएं बढ़ती हैं। उन्होंने कहा कि इस ऐप को किसी अमेरिकी कंपनी द्वारा खरीदे जाने से ये चिंताएं घट जाएंगी कि अमेरिकी डेटा को किसी विदेशी शक्ति के साथ साझा किया जा रहा है।

संक्षिप्त समाचार

कुशीनगर में लुटरों ने सर्राफा व्यापारी को मारी गोली, घायल

कुशीनगर। उत्तर प्रदेश में कुशीनगर के रामकोला क्षेत्र में मोटरसाकिल सवार तीन बदमाशों ने सर्राफ व्यापारी पर गोलिया बरसाकर घायल कर दिया। पुलिस सूत्रों ने गुरूवार को यहां बताया कि रामकोला क्षेत्र में कृष्णा वर्मा की सर्राफ की दुकान है। गुरूवार रात दुकान बंद करके अपने घर लौट रहे थे। इस बीच मोरटसाइकिल सवार तीन बदमाशों ने उनसे जेवरात से भरा बैग लूटने के इरादे से ताबड़तोड़ गोलियां बरसाईं। दो गोली लगने के बाद भी कृष्णा वर्मा ने लुटेरों को जेवर नहीं छीनने दिया। इस वारदात के दौरान ही बगल के पेट्रोल पम्प पर मौजूद कर्मचारियों ने लुटेरों को दौड़ा लिया। उन्हें जेवर छोड़कर भागना पड़ा। उन्होंने बताया कि पुलिस ने घायल कारोबारी को सीएचसी रामकोला पहुंचाया। जहां से डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें गोरखपुर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। रोज की तरह वह गुरुवार की रात को दुकान बंद करने के बाद दुकान का आभूषण डिक्की में रखकर मोटरसाइकि से घर लौट रहा था। शाम को करीब 7 बजे वह चंदरपुर पेट्रोलपंप के पास पहुंचा था इस बीच तीन बदमाशों ने ओवरटेक कर उसे रोक लिया।

गर्भवती को लेकर भटकते रहे परिजन, उपचार में देरी होने पर तोड़ा दम

जौनपुर। उत्तर प्रदेश में जौंनपुर के जिला महिला अस्पताल में इलाज के लिए आई एक गर्भवती महिला की परिसर में ही मृत्यु हो गई। पारिवारिक सूत्रों ने शुक्रवार को यहां बताया कि लाइन बाजार क्षेत्र के सूरज घाट निवासी सत्य प्रकाश सिंह की पत्नी साक्षी सिंह (25) की तबीयत बिगड़ने पर उन्हें निजी एंबुलेंस से परिजन शहर के अस्पताल ले गए। कोरोना जांच कराने का हवाला देते हुए अस्पताल ने भर्ती करने से इंकार कर दिया। परिवार के लोग दोपहर बाद उसे लेकर जिला महिला अस्पताल पहुंच गए। वहां भी चिकित्सकों ने कोविड की जांच कराने के बाद ही भर्ती करने की बात कही। कोरोना की जांच में उसकी रिपोर्ट निगेटिव आई। इस बीच काफी देर होने से महिला की हालत बिगड़ती चली गई। चिकित्सकों ने उसे वाराणसी ले जाने की सलाह दी। परिवार के लोग 108 नंबर एंबुलेंस की इंतजार कर रहे थे। इसी दौरान साक्षी की मृत्यु हो गई। जिला महिला अस्पताल के सीएमएस आरएस सरोज का कहना है कि महिला गर्भवती थी। उसका ऑक्सीजन लेबल बहुत कम हो गया था।

करंट लगने से एक बालिका व एक सफाई कर्मी की मौत

फिरोजाबाद। जनपद में अलग अलग थाना क्षेत्रों के अन्तर्गत विधुत करंट लगने से एक बालिका व एक सफाई कर्मी की मौत हो गयी। पुलिस ने षवों के पोस्टमार्टम जिला अस्पताल में कराये है। जनपद मैनपुरी के थाना बिछवा क्षेत्र के गांव कटका निवासी नरेन्द्र सिंह पाल पुत्र स्व. केषवदयाल जिला पंचायत फिरोजाबाद में सफाई कर्मचारी था। वह थाना लाइनपार क्षेत्र के नगला विष्नू में किराये के मकान में रहता था। गुरूवार को वह विधुत तार लगा रहा था तभी अचानक करंट लगने से उसकी मौत हो गयी। घटना की जानकारी होते ही मृतक के परिजन भी आ गये। जिन्होंने सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने षव का पोस्टमार्टम जिला अस्पताल में कराया है। इधर नरेन्द्र सिंह पाल की मौत की खबर मिलते ही उसकी पत्नी भी आ गयी। मृतक की पत्नी का आरोप है कि उसका पति यहां किसी अन्य महिला के साथ रहता था। जिससे उसके अबैध सम्बंध थे। मृतका की पत्नी ने इस महिला पर करंट लगाकर हत्या करने का आरोप लगाया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। वही थाना नगला खंगर के गांव नगला केसरी निवासी हउद्धेष की पुत्री षालिनी (6) भी करंट लगने से मौत हो गयी।

बेगमपुरा और दून एक्सप्रेस अब नहीं आएगी जौनपुर

जौनपुर। लॉकडाउन के कारण निरस्त चल रहीं कई ट्रेनें हालात सामान्य होने पर पटरियों पर दौड़ेंगी भी तो उनके रूट बदल चुके होंगे। रेलवे बोर्ड ने जिन 50 ट्रेनों का रूट परिवर्तन करने का फैसला लिया है, उनमें बेगमपुरा व दून एक्सप्रेस हैं। यह दोनों ट्रेनें अब जौनपुर होकर नहीं चलेंगी। रेलवे सूत्रों के अनुसार रेलवे जोनल मुख्यालयों ने कई रूटों पर 50 ट्रेनों का मार्ग स्थाई रूप से बदलने का प्रस्ताव रेलवे बोर्ड को भेजा था जिसे बोर्ड ने स्वीकृत कर आदेश जारी कर दिया है। हालांकि, रूट डायवर्जन की तिथि रेलवे अपने नए टाइम टेबल में ही जारी करेगा। उन्होने बताया कि नए रूट से दूरी कम होने के कारण इन ट्रेनों को गंतव्य तक पहुंचने में कम समय लगेगा। यह पहला मौका है, जब इतने बड़े पैमाने पर ट्रेनों का तय रूट बदला जा रहा है। सिटी स्टेशन, सुल्तानपुर होते हुए लखनऊ होकर जम्मूतवी जाने वाली वाराणसी-जम्मूतवी 12237 अप व 38 डाउन बेगमपुरा एक्सप्रेस अब वाराणसी से प्रतापगढ़-रायबरेली-लखनऊ होकर चलेगी। प्रतापगढ़ व रायबरेली में होगा।

जौनपुर स्थित वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय की परीक्षाएं दो सितंबर से

जौनपुर। उत्तर प्रदेश के जौनपुर स्थित वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय की स्थगित यूजी-पीजी (स्नातक-स्नातकोत्तर) परीक्षाएं अब 17 अगस्त की बजाय दो सितंबर से होंगी। यह फैसला कोविड-19 के चलते विश्वविद्यालय प्रशासन ने लिया है। पूर्वांचल विश्वविद्यालय के बीए, बीएससी, बीकॉम व बीएससी एजी, स्नातकोत्तर एमए, एमएससी, एमकॉम व एमएससी एजी, बीएड, एमएड, एलएलबी, एलएलएम, बीबीए-बीसीए सेमेस्टर परीक्षा को शासन ने वैश्विक महामारी कोरोना वायरस व लॉकडाउन के चलते मार्च में ही स्थगित कर दिया था। इसके बाद परीक्षा की तिथि कई बार घोषित की गई लेकिन सरकार ने परीक्षा कराने की अनुमति किसी भी विश्वविद्यालय को नहीं दिया। बीते माह जारी गाइड लाइन के मुताबिक शासन ने विश्वविद्यालयों को अपनी सुविधा अपने तरीके से परीक्षा कराने की सहूलियत दी थी जिसके बाद पूर्वांचल विश्वविद्यालय ने यूजी-पीजी व सेमेस्टर परीक्षा आगामी 17 अगस्त से कराने का निर्णय लिया था। जल्द ही परीक्षा समय सारणी भी जारी होने वाली थी।

बस्ती में सरयू नदी की बाढ़ से 45 गांव प्रभावित 20 गांव पानी से घिरे

बस्ती। उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में सरयू नदी की बाढ़ से 45 गांव प्रभावित हैं तथा 20 गांव पानी से घिरे हुए हैं। जिला प्रशासन द्वारा बाढ़ पीड़ितों को सहायता प्रदान की जा रही है। आज यहां यह जानकारी देते हुए अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व रमेश चंद्र तिवारी ने बताया है कि सरयू नदी की बाढ़ से जिले के हरैया तथा बस्ती तहसील के 45 गांव प्रभावित हैं इन ग्रामों की 15,000 से अधिक जनसंख्या बाढ़ और कटान का सामना कर रही है। प्रशासन द्वारा पीड़ितों को सहायता देने के साथ ही 72 नावों को लगाया गया है।

योगी आदित्यनाथ बोले, इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर में लापरवाही के लिए जिलाधिकारी होंगे जवाबदेह

लखनऊ/एजेंसी। कोरोना संक्रमण को काबू में करने के लिए जिलों में संचालित इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम पूरी सक्रियता से काम करने की नसीहत देते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि इस संबंध में लापरवाही की शिकायत मिलने पर संबंधित जिलाधिकारी की जवाबदेही सुनिश्चित की जाएगी। श्री योगी ने शुक्रवार को अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा बैठक में कहा कि कोविड-19 के संक्रमण की चेन को तोडने के लिए पूरी सतर्कता बरतने के साथ-साथ प्रत्येक स्तर पर प्रभावी कार्यवाही किया जाना आवश्यक है। उन्होंने जिलाधिकारियों से कहा कि वे कोविड-19 के मद्देनजर व्यवस्थाओं की प्रभावी मॉनिटरिंग सुनिश्चित करें। प्रत्येक जिलाधिकारी इस दिशा में अपने जिला में की जा रही कार्रवाई की प्रतिदिन सुबह व शाम नियमित तौर पर समीक्षा करें। उन्होने कहा कि सभी सरकारी तथा निजी चिकित्सालयों में मेडिकल संक्रमण से सुरक्षा के समस्त प्रबंध किए जाएं। इसके साथ ही, सभी सरकारी एवं निजी अस्पतालों में फायर सेफ्टी की भी प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। उन्होंने डीजी, फायर सर्विस को अग्नि सुरक्षा के सम्बन्ध में सभी चिकित्सालयों का निरीक्षण कराने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने डोर-टू-डोर सर्वे के कार्य को प्रभावी ढंग से जारी रखने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि कांटेक्ट ट्रेसिंग का कार्य सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न किया जाए। होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों के स्वास्थ्य की जानकारी इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर द्वारा प्रतिदिन प्राप्त की जाए। एल-2 तथा एल-3 कोविड अस्पतालों में बेड्स की संख्या में वृद्धि की जाए। उन्होंने लखनऊ, कानपुर नगर, वाराणसी, आजमगढ़, प्रयागराज, गोरखपुर तथा बरेली में विशेष सतर्कता बरतते हुए इन जिलों की चिकित्सा व्यवस्थाओं को बेहतर किए जाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने जिला सेवा योजन कार्यालय तथा जिला उद्योग केंद्र को सक्रिय करने के निर्देश दिए और कहा कि इससे आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश बनाने में मदद मिलेगी। उन्होंने बाढ़ व जलमग्न क्षेत्रों में प्रभावित लोगों को समय से राहत सामग्री उपलब्ध कराए जाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि राहत कार्यों को बेहतर ढंग से संचालित करने के लिए आवश्यकतानुसार अतिरिक्त नावों का प्रबन्ध किया जाए। इस अवसर पर मुख्य सचिव आरके तिवारी, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त आलोक टण्डन, कृषि उत्पादन आयुक्त आलोक सिन्हा, अपर मुख्य सचिव सूचना एवं गृह अवनीश कुमार अवस्थी मौजूद थे।

यूपी में कोरोना वायरस से संक्रमित 4,466 नए रोगी मिले

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में शुक्रवार को कोरोना वायरस से संक्रमित 4,466 नए रोगी मिले हैं। बीते 24 घंटे में 95,737 नमूनों की जांच हुई। अब राज्य में कुल 1,13,623 मरीज मिल चुके हैं। पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा 63 मरीजों की मौत हुई और अभी तक 1918 लोगों की जान यह खतरनाक वायरस जान ले चुका है। प्रदेश में 3,432 और लोग डिस्चार्ज हुए हैं। अभी तक 66,834 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। अब राज्य में 44,563 एक्टिव केस हैं। अभी तक प्रदेश भर में 28,93,424 लोगों की कोरोना जांच करवाई जा चुकी है। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस से संक्रमित 58 प्रतिशत रोगी अब तक ठीक हो चुके हैं। बीते महीने भर में ज्यादा रोगी मिलने के कारण रिकवरी रेट में नौ प्रतिशत की गिरावट आई है।

सपा सांसद बोले - अयोध्या में मस्जिद थी, मस्जिद है और मस्जिद ही रहेगी

संभल/एजेंसी। समाजवादी पार्टी (सपा) के सांसद शफीकुर्रहमान बर्क ने अयोध्या में मंदिर निर्माण की बुनियाद रखने के बाद विवादित बयान दिया है। उनका यह बयान सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है और लोग उनकी जमकर आलोचना कर रहे हैं। वायरल हो रहे इस वीडियो में शफीकुर्रहमान बर्क यह कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि अयोध्या में मस्जिद थी, मस्जिद है और मस्जिद ही रहेगी। लोग इस वीडियो को शेयर कर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव से सवाल कर रहे हैं। सपा सांसद वीडियो में कहते हैं, 'वहां संग-ए बुनियाद रखना, जम्हूरियत का कत्ल करना है और सेक्युलरिज्म का कत्ल करना है। इस जम्हूरी मुल्क के अंदर जो अमल हो रहा है, इस अमल पर उन्होंने शायद कभी गौर नहीं किया कि शायद हम जो कुछ भी यहां पर कर रहे हैं, इस बुनियाद पर कर रहे हैं। ठीक है उनकी सरकार है, उन्होंने अपनी ताकत के बल पर संघे

बुनियाद रख दी और अदालत से भी अपने फेवर में करा लिया।

तो कानूनी इंसाफ नहीं है लेकिन हमने सब्र से काम लिया। आज भी हम अल्लाह पर भरोसा करते हैं कि ये जगह हमेशा मस्जिद थी, मस्जिद है और मस्जिद रहेगी। इसको कोई मिटा नहीं सकता है।'

रामनगरी के कायाकल्प की तैयारी शुरू

अयोध्या/एजेंसी। भव्य राम मंदिर के निर्माण के साथ अब रामनगरी अयोध्या के कायाकल्प की तैयारी भी शुरू हो गयी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले से ही अयोध्या के विकास को लेकर संजीदा हैं। उनकी संजीदगी के चलते पहले से ही विकास की कई योजनाओं पर काम चल रहा है। कुछ पाइपलाइन में हैं। भूमिपूजन के दिन 5 अगस्त, 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने संबोधन में अयोध्या के कायाकल्प और इसके नाते पूरे क्षेत्र में बन रही संभावनाओं का जिक्र किया था। उम्मीद थी कि इसी दिन करीब 500 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण भी होगा, पर कुछ वजहों से इस कार्य को टाल दिया गया। फिलहाल सरकार की योजना में और बहुत कुछ शामिल है। खास बात यह है कि यह जो कुछ भी होगा, सब समय से होगा। मसलन

एयरपोर्ट राम के नाम होगा तो मेडिकल कॉलेज जनकपुर के राजा और सीता के पिता दशरथ के नाम पर पर होगा। राम की पौढ़ी को हरिद्वार की हर की पौढ़ी की तर्ज पर बनाने की भी योजना है। गुप्तार घाट से लेकर न्यायघाट तक करीब 10 किमी लंबा रीवर फ्रंट, वैदिक सिटी, सड़कों का चौड़ीकरण, भूमिगत केबिल, पंच कोसी परिक्रमा मार्ग का पुनरुद्धार, मल्टीलेवल पार्किंग, सरयू को अविरल और निर्मल बनाने के लिए अयोध्या और फैजाबाद में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बस स्टैंड आदि बनाना सरकार की कार्ययोजना में शामिल है। राम सर्किट और स्वदेश दर्शन योजना के तहत घाटों के सुंदरीकरण के साथ और भी कई काम पहले हो चुके हैं। अयोध्या के परियोजना निदेशक (डीआरडीए) और नोडल अधिकारी कमलेश सोनी ने बताया कि रानगरी अयोध्या में करीब 2,000 करोड़ रुपये से कायाकल्प होने जा रहा है। उन्होंने बताया कि सहादत गंज से नयाघट राम की पौढ़ी तक फोर लेन बनायी जाएंगी। इसके बीच में आने वाली 800 दुकानों को शिफ्ट किया जाएगा। उन्होंने बताया कि चार हजार बसों के लिए और छोटे वाहनों की पार्किंग बन रही है। गोंडा बस्ती अयोध्या प्रट्रोल पम्प के पास 10 हजार बसों के लिए पार्किंग बन रही है। इसके अलावा 600 एकड़ में टाउनशिप बन रही है। टाउनशिप बनाने के लिए जितने लोगों को यहां से शिफ्ट किया जाएगा, उन सभी को इसी टाउनशिप में रियायित दरों में रहने की सुविधा दी जाएगी। रामजन्मभूमि के लिए एक एलिवेटेड रोड बन रही है।

opensearch

योगी सरकार ने कोरोना मरीजों के लिए आइवरमेक्टिन टेबलेट को दी मंजूरी

गर्भवती महिलाओं और दो वर्ष से कम बच्चों को नहीं दी जाएगी दवा

लखनऊ/एजेंसी। योगी सरकार ने कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए आइवरमेक्टिन टेबलेट को दवा के तौर पर इस्तेमाल करने की मंजूरी दे दी है। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने इस संबंध में शासनादेश जारी किया। इसमें मरीज को दवा की कितनी खुराक देनी है, इस सम्बन्ध में जानकारी दी गई है। शासनादेश में बताया गया है कि महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं डॉ. बीएस नेगी की अध्यक्षता में हुई तकनीकी विशेषज्ञों की बैठक में कोरोना संक्रमण से बचाव एवं उपचार के संबंध में आइवरमेक्टिन टेबलेट का इस्तेमाल किए जाने की संस्तुति की गई। इसमें कहा गया है

कि कोरोना के पुष्ट रोगी के सम्पर्क में आए व्यक्तियों में रोग के सम्भावित संक्रमण से बचाव के लिए प्रति किलोग्राम शरीर के भार पर 200 म्यू ग्राम के हिसाब से पहले व सातवें दिन रात्रि भोजन के दो घंटे बाद व्यस्क व्यक्ति में औसतन 12 मिलीग्राम दवा दी जाएगी।

कोरोना उपचार एवं नियंत्रण में कार्यरत स्वास्थ्य कर्मियों में संक्रमण से बचाव के लिए प्रति किलोग्राम शरीर के भार पर 200 म्यू ग्राम के हिसाब से पहले, सातवें व 30वें दिन और आवृत्ति क्रम में प्रति माह में एक बार आईवरमेक्टिन प्रयोग की जानी चाहिए। इसके साथ ही एसिम्पटोमैटिक या हल्के लक्षणों वाले कोरोना के पुष्ट रोगियों के इलाज में आइवरमेक्टिन को प्रति किलोग्राम शरीर के भार पर 200 म्यू ग्राम के हिसाब से पहले तीन दिनों तक रात्रि में एक बार भोजन के दो घंटे बाद व्यस्क व्यक्ति में औसतन 12 मिलीग्राम दवा दी जाएगी। साथ ही डॉक्सीसाइक्लीन 100 म्यू ग्राम दवा दिन में दो बार पांच दिन तक दी जाएगी। शासनादेश में स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि गर्भवती एवं धात्री महिलाओं तथा दो वर्ष से कम उम्र के बच्चों को यह दवा नहीं दी जाएगी। डॉक्सीसाइक्लीन दवा भी गर्भवती व धात्री महिलाओं तथा 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को नहीं दी जाएगी।

उप्र में होगा देश का पहला नियमित विधानसभा सत्र

लखनऊ/एजेंसी। उत्तर प्रदेश में चार दिन का विधानसभा सत्र 20 अगस्त से शुरू होने वाला है। इस सत्र का अनुभव अलग होगा क्योंकि इसे कोविड -19 महामारी के प्रोटोकॉल के अनुसार आयोजित किया जाएगा। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए विशेष इंतजाम किए जाएंगे। विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित ने कहा, उत्तर प्रदेश विधानसभा इस बात का उदाहरण देगी कि महत्वपूर्ण मामलों पर कानून बनाने के लिए चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी सत्र का आयोजन कैसे किया जाए। मुझे विश्वास है कि हमारे सभी सदस्य देश के सामने एक मिसाल कायम करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि सत्र में जनता से जुड़े गंभीर विषयों को संबोधित किया जा सके। हमें उम्मीद है कि इस संक्षिप्त सत्र के दौरान कोई व्यवधान नहीं होगा। उत्तर प्रदेश पहला ऐसा राज्य होगा जहां महामारी के दौरान नियमित सत्र होगा। फरवरी में हुए आखिरी सत्र के बाद 6 महीनों के भीतर सत्र आयोजित करने के संवैधानिक दायित्व को पूरा करने के लिए यह मानसून सत्र बुलाया गया है।

विधानसभा के प्रधान सचिव प्रदीप कुमार दुबे ने कहा, वायरस के प्रसार को रोकने के लिए केंद्रीय एयर कंडीशनिंग प्रणाली में विशेष फिल्टर का उपयोग किया जाएगा। केंद्रीय कैंटीन बंद रहेगा। सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करने के लिए विधायकों को प्रेस दीर्घा समेत विभिन्न दीर्घाओ में बैठाया जाएगा।

बागपत में कई वांछित गिरफ्तार, अवैध सामग्री बरामद

बागपत। उत्तर प्रदेश में बागपत के बड़ौत क्षेत्र में पुलिस ने कई वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से अवैध सामग्री बरामद की है। कोतवाली प्रभारी अजय शर्मा ने शुक्रवार को बताया कि पुलिस ने वांछित वारण्टी और अवैध वस्तु की बरामदगी अभियान के तहत अलग अलग क्षेत्रों में आपराधिक वारदातों में लिप्त शकील, अमित, देशपाल, राकेश, सुखदेव, नरेश और पवन को गिरफ्तार उनके कब्जे से नगदी, हथियार और अन्य अवैध सामग्री बरामद की। सभी अभियुक्तों को संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर न्यायालय में पेश किया गया जहाँ से उन्हे जेल भेज दिया गया है।

यूपी के 17 जिलों में बाढ़ का कहर

लखनऊ। हर साल की तरह इस बार भी उत्तर प्रदेश बाढ़ की चपेट में है। प्रदेश की प्रमुख नदियां गंगा, यमुना, घाघरा, राप्ती और शारदा अलग-अलग स्थानों पर खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। लगातार भारी बारिश और नेपाल से आने वाले पानी का बहाव राज्य की नदियों के उफान का कारण बन रहा है। हालात ऐसे हैं कि सूबे के 17 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। इन जिलों के 666 गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं, जबकि इनमें से आधे से अधिक गांव बाढ़ के पानी में डूबे हुए हैं। कई स्थानों पर जलस्तर कम हुआ है तो कटान की समस्या ने लोगों को परेशान कर दिया है। बाढ़ से प्रभावित लोगों ने ऊंचे स्थानों पर या तटबंधों पर शरण ले रखी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिये हैं कि तटबंधों पर लगातार गश्त की जाए और भूमि क्षरण रोकने के कदम उठाये जाएं।

सेना प्रमुख ने मध्य कमान की ऑपरेशनल तैयारियों को देखा

-मध्य कमान के अन्तर्गत आने वाली उत्तराखंड से सटी सीमा पर चौकसी बरतने के निर्देश

-राज्यपाल आंनदीबेन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से की मुलाकात

लखनऊ/एजेंसी। सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे शुक्रवार को राजधानी लखनऊ पहुंचे। उन्होंने नेपाल और चीन से सटी सीमाओं के हालातों और सेना की तैयारियों को लेकर मध्य कमान के सैन्य अफसरों के साथ चर्चा की। उन्होंने मध्य कमान के अन्तर्गत आने वाली उत्तराखंड से सटी सीमा पर लिपुलेख के पास चीनी सेना की तैनाती और भारत की ओर से उठाये गए कदमों की समीक्षा की और चौकसी बरतने के निर्देश दिए। सेना प्रमुख को मध्य कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ लेफ्टिनेंट जनरल आईएस घुमन ने सैन्य ऑपरेशनल और प्रशासनिक दोनों पहलुओं पर जानकारी दी गई। जनरल नरवणे ने मध्य क्षेत्र में सैन्य बलों की क्षमता वृद्धि और आपरेशनल प्रभावशीलता और बुनियादी ढांचे के विकास को सुनिश्चित करने के लिए किए जा रहे प्रयासों पर संतोष व्यक्त किया। उन्होंने ऑपरेशनल तैयारियों के लिए मध्य कमान की प्रशंसा की। जनरल नरवणे ने उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बहुत कठिन मौसम की स्थिति में काम कर रहे अग्रिम क्षेत्रों में सैनिकों द्वारा किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। लखनऊ से प्रस्थान करने से पहले जनरल नरवणे ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की और अहम विषयों पर चर्चा की। भारतीय थल सेनाध्यक्ष बनने के बाद जनरल नरवणे पहली बार अधिकारिक दौरे पर राजधानी लखनऊ पहुंचे थे। वह विशेष सर्विस विमान ने चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पहुंचे। वहां से हेलिकॉप्टर से वह छावनी के सूर्या खेल परिसर पहुंचे। यहां से सड़क मार्ग से जनरल नरवणे मध्य कमान मुख्यालय पहुंचे। उनका लखनऊ का दौरा इसलिए भी अहम माना जा रहा है, क्योंकि पिछले कुछ समय से चीन और भारत के बीच एलएसी पर तनाव की स्थिति है।

हाल ही में उत्तराखंड से सटी सीमा पर लिपुलेख के पास चीन ने जवानों की संख्या बढ़ा दी है। यह इलाका मध्य कमान के अन्तर्गत आता है।

अपने दौरे के दौरान जनरल नरवणे ने नेपाल और चीन से सटी सीमाओं के हालातों और सेना की तैयारियों को लेकर सैन्य अफसरों के साथ चर्चा की और निर्देश दिए। बाद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक ट्विट करके कहा' भारतीय थल सेना के अध्यक्ष मनोज मुकुंद नरवणे जी से आज शिष्टाचार भेंट हुई।

शेयर बाजार: सेंसेक्स और निफ्टी मामूली बढ़त के साथ बंद

नई दिल्ली। गिरावट के साथ खुलने वाले शेयर बाजार की चाल आज दिनभर सुस्त रही। सप्ताह के अंतिम कारोबारी दिन शुक्रवार को बाजार मामूली बढ़त के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 15 अंकों की मामूली तेजी के साथ 38040 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी ने 13.90 अंकों की बढ़त के साथ 11,214.05 के स्तर पर आज के कारोबार को विराम दिया। निफ्टी गेनर की लिस्ट में आज एशियन पेंट्स टॉप पर है। इसके शेयर 4.65 फीसद की तेजी के साथ 1807 रुपये 80 पैसे पर बंद हुए। वहीं बजाज फाइनेंस, यूपीएल अैर इंडसइंड बैंक भी हरे निशान के साथ बंद हुए। गिरावट वाले स्टॉक में टाइटन, एचसीएलटेक, इन्फोसिस, सन फार्मा और महिंद्रा एंड महिंद्रा के रहे।

उपभोक्ता अनुभव सर्वे में इन दो ऑनलाइन रिटेलर ने मारी बाजी, हासिल किया ये स्थान

नयी दिल्ली। ऑनलाइन रिटेलर अमेजन और डी-मार्ट उपभोक्ता अनुभव सर्वे में विजेता बनी हैं। यह सर्वे डेटा और परामर्शक कंपनी कन्तार ने किया है। कन्तार सीएक्स प्लस 2020 रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेजन सामान्य खुदरा तथा फैशन खुदरा खंड में पहले स्थान पर रही है। डी-मार्ट ने ग्राहकों को हुए अनुभव के हिसाब से किराना श्रेणी में पहला स्थान हासिल किया है।

सामान्य खुदरा तथा फैशन खुदरा खंड दोनों में अमेजन के बाद फ्लिपकार्ट दूसरे स्थान पर रही है। सामान्य खुदरा तथा फैशन खुदरा खंड में तीसरा स्थान क्रमशः डी-मार्ट और मिन्त्रा का रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि तीन में दो क्षेत्रों में अमेजन शीर्ष रिटेलर कंपनी रही है। डी-मार्ट किराना खंड में विजेता रही है। वहीं फ्लिपकार्ट तीनों क्षेत्रों में शीर्ष तीन स्थानों पर रही है।

कोरोना महामारी और अमेरिका से तनाव के बावजूद जुलाई में बढ़ा चीन का निर्यात

बीजिंग। कोरोना वायरस महामारी तथा अमेरिका के साथ जारी व्यापार तनाव के बाद भी जुलाई महीने में चीन का निर्यात साल भर पहले की तुलना में 7.5 प्रतिशत बढ़ गया। इससे संकेत मिलता है कि चीन की अर्थव्यवस्था कोरोना वायरस महामारी के प्रकोप से उबरने लगी है। शुक्रवार को जारी आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, आलोच्य महीने के दौरान अमेरिका को चीन के निर्यात में 12.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गयी। इस दौरान चीन का कुल निर्यात 237.6 अरब डॉलर रहा। यह जून 2020 की तुलना में तीन प्रतिशत अधिक है। जुलाई माह के दौरान चीन का आयात 1.4 प्रतिशत कम होकर 175.3 अरब डॉलर रहा। चीन में कोरोना वायरस महामारी का प्रकोप सबसे पहले शुरू हुआ। दिसंबर 2019 में महामारी की शुरुआत के बाद चीन ठप्प होने वाली पहली वैश्विक अर्थव्यवस्था रहा।

हालांकि उसने महामारी पर सबसे पहले काबू भी किया और मार्च में सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी ने कोविड-19 पर विजय का दावा किया। इससे पहले जून तिमाही में चीन के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में 3.2 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गयी। चीन की जीडीपी में यह वृद्धि मार्च तिमाही की 6.8 प्रतिशत की गिरावट के बाद आयी। चीन का निर्यात वैश्विक औसत की तुलना में तेज गति से सामान्य स्थिति में लौट रहा है। इससे पता चलता है कि चीन के विनिर्माता महामारी से अब भी जूझ रही अन्य अर्थव्यवस्थाओं की हिस्सेदारी पर कब्जा जमाने लगे हैं।

कोविड-19 टीके की दस करोड़ खुराक का उत्पादन करेगा सीरम इंस्टीट्यूट भारत

नयी दिल्ली। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (एसआईआई) ने शुक्रवार को कहा कि उसने भारत तथा अन्य कम व मध्यम आय वाले देशों के लिये कोविड-19 टीके की 10 करोड़ खुराक का उत्पादन करने को लेकर गावि और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के साथ गठजोड़ किया है। सीरम इंस्टीट्यूट ने एक बयान में कहा, ''यह गठजोड़ सीरम इंस्टीट्यूट को विनिर्माण क्षमता बढ़ाने में मदद करने के लिये अग्रिम पूंजी प्रदान करेगा, ताकि एक बार किसी टीका या टीके को नियामकीय मंजूरियों तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्वीकृति मिल जाने के बाद गावि कोवैक्स एएमसी के तहत 2021 की पहली छमाही तक भारत व अन्य कम-मध्यम आय वाले देशों में वितरण के लिये पर्याप्त खुराक का उत्पादन किया जा सके।'' कंपनी ने बताया कि उसने प्रति खुराक तीन डॉलर यानी करीब 225 रुपये की किफायती दर निर्धारित की है। यह वित्तपोषण एस्ट्राजेनेका और नोवावैक्स के संभावित टीकों के विनिर्माण में भी समर्थन प्रदान करेगा। इन दो कंपनियों के टीके अभी परीक्षण से गुजर रहे हैं। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन अपने निवेश कोष के माध्यम से गावि को 15 करोड़ डॉलर का जोखिम-रहित धन मुहैया करायेगा, जिसका उपयोग संभावित टीकों के विनिर्माण में सीरम इंस्टीट्यूट का समर्थन करने और भविष्य में कम व मध्यम आय वाले देशों के लिये टीके की खरीद में किया जायेगा। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) अदार पूनावाला ने कहा, ''कोविड-19 के खिलाफ हमारी लड़ाई को मजबूत बनाने की कोशिश में सीरम इंस्टीट्यूट ने भारत और निम्न व मध्यम आय वाले देशों के लिये कोविड-19 के टीकों की 10 करोड़ खुराक तैयार करने को गावि तथा बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के साथ गठजोड़ किया है।''

महिलाओं, छोटे कारोबारियों के लिए जमाएं लेने वाला सूक्ष्म ऋण संगठन बनाने की योजना: गडकरी

मुंबई। (एजेंसी)

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने शुक्रवार को कहा कि सरकार महिलाओं और छोटे कारोबारियों को जल्द से जल्द से 10 लाख रुपये तक का कर्ज देने के लिए जमाएं स्वीकार करने वाला एक 'सामाजिक सूक्ष्मवित्त संगठन' गठित करने की योजना बना रही है। उन्होंने कहा कि यह विचार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित और बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक के संस्थापक मोहम्मद यूनुस के साथ एक चर्चा के दौरान आया। एमएसएमई और सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्री ने कहा कि इसकी पुष्टि वित्त मंत्रालय और ''शीर्ष प्राधिकरण'' के साथ चर्चा के बाद की जाएगी। भारत में पहले ही देश के विभिन्न हिस्सों में सूक्ष्म ऋण देने वाले संगठन हैं, और इनमें से कुछ लघु वित्त बैंक के रूप में काम भी कर रहे हैं, जिससे उन्हें जमाओं तक पहुंच मिलती है।

उल्लेखनीय है कि नीतिनिर्माओं द्वारा जमाएं लेने की इजाजत बेहद सावधानी के साथ दी जाती है। फिक्की एफएलओ के साथ बातचीत में गडकरी ने कहा कि सरकार ऐसी व्यवस्था के बारे में विचार कर रही है, जहां तीन दिनों में महिला उद्यमियों को 10 लाख रुपये तक का ऋण दिया जा सकता है। इस व्यवस्था के बारे में समझाते हुए उन्होंने कहा, ''आप (वित्तपोषण इकाई) पंजीकरण करा सकते हैं।आपको आरबीआई से लाइसेंस मिलेगा, आप जमा राशि स्वीकार कर सकते हैं और छोटे लोगों को ऋण दे सकते हैं। हम इस तरह का तंत्र विकसित कर रहे हैं। हम लाल फीताशाही के बिना बेहद सरल प्रक्रिया के साथ सामाजिक सूक्ष्म और लघु संस्थानों के लिए इस तरह की व्यवस्था विकसित कर रहे हैं।''

इसे भी पढ़ें- केंद्रीय मंत्री बोले, कैलाश मानसरोवर मार्ग पर 85 प्रतिशत काम पूरा, परियोजना की लागत 12,000 करोड़ रुपये

उन्होंने कहा कि इस संबंध में नीति आयोग पहल कर रहा है और इसके आधार एक नीति बनाई जाएगी। गडकरी ने कहा, ''सभी छोटे लोगों को धन मिलेगा। विचार यह है कि हम ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार की संभावना कैसे बना सकते हैं।'' उन्होंने स्वीकार किया कि अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है और साथ ही देश भर में औद्योगिक क्लस्टर बनाने की जरूरत पर जोर दिया।

आरबीआई के इस नए सिस्टम से अब चेक से पेमेंट करना होगा और भी सुरक्षित, बैंक को देने होंगे ये डिटेल्स

नयी दिल्ली। (एजेंसी)

अगर आप भी चेक से लेन-देन और भुगतान जैसी चीजें करते है तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। बता दें कि आरबीआई ने चेक पेमेंट के नियमों में बदलाव किए है। इस नए बदलाव के तहत अब आप और भी सुरक्षित तरीकें से चेक से पेमेंट कर सकेंगे। इसके लिए आरबीआई ने सभी चेक के लिए पॉजिटिव पे सिस्टम को लागू किया है। तो आइये जानते है कि क्या है यह सिस्टम और कैसे करेगा ये काम?

आरबीआई के इस सिस्टम से अब चेक से भुगतान करने में अधिक सुरक्षा मानकों का ध्यान रखा जाएगा। इस नए सिस्टम के अनुसार अब कोई भी चेक पेमेंट से होने वाली छेड़छाड़ और धोखाधड़ी नहीं कर पाएगा। जानकारी के मुताबिक आरबीआई ने 50 हजार रुपए या उससे अधिक के चेक भुगतान के लिए पॉजिटिव पे सिस्टम को लागू करने का फैसला किया है। इस सिस्टम के जरिए अगर ग्राहक को 50,000 रुपये या इससे ज्यादा की रकम का चेक जारी करना होगा तो उससे पहले खाताधारक को चेक के बारे में बैंक को पूरी जानकारी देनी होगी। इसके लिए खाताधारक को चेक नंबर, चेक डेट, पेई का नाम, खाता नंबर, रकम आदि की डिटेल और चेक की आगे और पीछे की फोटो भी बैंक को शेयर करनी होगी। साथ ही जब ग्राहक अपने चेक को कैश में बदलने के लिए बैंक में जमा कराएगा तब बैंक को पॉजिटिव सिस्टम के जरिए पहले से मिली चेक की सारी डिटेल्स को उस चेक से मैच करेगा। अगर चेक दूसरे चेक के डिटेल से बिल्कुल मेल खा जाती है तब ही चेक क्लियर होगा वरना नहीं। इस सिस्टम से धोखाधड़ी होने की संभावना बिल्कुल नहीं होगी। इस सिस्टम के साथ ही आरबीआई ने देशभर में चेक ट्रंकेशन सिस्टम का इस्तेमाल बढ़ाने का भी फैसला किया है।

अब बिना इंटरनेट के कार्ड और मोबाइल के जरिए कर सकेंगे डिजिटल पेमेंट

नयी दिल्ली। (एजेंसी)

डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए आरबीआई ने अब ऑफलाइन रिटेल पेमेंट्स की पायलट स्कीम को मंजूरी दे दी है। इस स्कीम के मुताबिक अब आप बिना किसी इंटरनेट कनेक्टिविटी के भी बड़ी आसानी से ऑफलाइन पेमेंट कर सकेंगे। आरबीआई के गाइडलाइंस के अनुसार इंटरनेट कनेक्टिविटी की कमी के कारण कई डिजिटल ट्रांजेक्शन बीच में ही अटक जाते है या होते ही नहीं है, इसी को देखते हुए अब लोग आसानी से कार्ड और वॉलेट से ऑफलाइन पेमेंट कर पाएंगे। इस स्कीम से शहरी के साथ-साथ ग्रमीण इलाकों में भी डिजिटल ट्रांजेक्शन को बढ़ावा मिलेगा। जानकारी के मुताबिक इस ऑफलाइन पमेंट से आप केवल छोटी रकम के पेमेंट कर पाएंगे। इसकी उच्चतम रकम 200 रूपये होगी और टोटल लेनदेन की सीमा केवल 2000 रूपये तक की होगी।

आरबीआई के मुताबिक स्लो इंटरनेट की कमी और इंटरनेट की धीमी गति से कई बार डिजिटल पेमेंट करने में काफी दिक्कते आती है। इसी को देखते हुए अब कार्ड,वॉलेट या मोबाइल डिवाइस के जरिये बिना किसी इंटरनेट के ऑफलाइन पेमेंट किया जा सकेगा। आरबीआई ने 'स्टेटमेंट ऑफ डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी पॉलिसीज' में बताया कि उन्होंने कंपनियों को ऑफलाइन पेमेंट सॉल्यूशन डेवलप करने को कहा है। इसके चलते कम वैल्यू के ऑफलाइन मोड में इनबिल्ट फीचर्स के साथ छोटी वैल्यू के पेमेंट की पायलट स्कीम को मंजूरी का प्रस्ताव पेश किया गया है। बता दें कि इससे भविष्य में यूएसएसडी कोड के इस्तेमाल से ऑफलाइन पेमेंट काफी संभव हो जाएगा। इससे यूपीआई पिन से बिना इंटरनेट या स्मार्टफोन के ट्रांजेक्शन भी बड़ी आसानी से किए जा सकते है। आरबीआई न केवल शहरी बल्कि ग्रामीण इलाकों में डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन को काफी पहले से ही बढ़ावा दे रहा है। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इन इलाकों में कई सालों से *99स की स्कीम चला रहा है जिससे बड़ी आसानी से मोबाइल बैंकिंग सर्विस फीचर केवल मोबाइल के जरिए हासिल किए जा सकते है। जानकारी के मुताबिक, सरकार डिजिटल पेमेंट की सुविधा उन इलाकों में सबसे ज्यादा पहुंचाने की कोशिश कर रही है जहां इंटरनेट की कनेक्टिविटी बिल्कुल न के बराबर है।

ट्रंप की चीनी कंपनियों पर कड़ी कारवाई, अमेरिका में सूचीबद्ध चीनी कंपनियों को हटाने का किया फैसला

वाशिंगटन। (एजेंसी)

ट्रंप प्रशासन ऐसी चीनी कंपनियों पर कड़ी कार्रवाई करने के प्रस्ताव पर विचार कर रहा है, जो अमेरिका में सूचीबद्ध हैं और अमेरिकी ऑडिट प्रावधानों का पालन नहीं करती हैं। एक मीडिया रिपोर्ट में यह बात कही गई। वाल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रस्ताव के मुताबिक न्यूयार्क स्टॉक एक्सचेंज या नास्डैक जैसे अमेरिकी शेयर बाजारों में सूचीबद्ध चीनी कंपनियां अमेरिकी नियमों के लेखा परीक्षण के अधीन होंगी या उन्हें शेयर बाजार से हटा दिया जाएगा। समाचार पत्र ने कहा कि इन नियमों का पालन करने के लिए चीनी लेखा परीक्षकों को अपने लेखांकन के कागजात अमेरिकी सरकार के विशेष ऑडिट नियामक सार्वजनिक कंपनी लेखा निरीक्षण बोर्ड की निगरानी के साथ साझा करना होगा।

रिपोर्ट में वित्त मंत्रालय और प्रतिभूति तथा विनिमय आयोग विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के हवाले से कहा गया है कि जो चीनी कंपनियां अभी तक सूचीबद्ध नहीं हुई हैं, लेकिन अमेरिका में एक प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश (आईपीओ) की योजना बना रही हैं, उन्हें एनवाईएसई या नास्डैक पर सार्वजनिक होने से पहले इन नियमों का पालन करना होगा। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी प्रतिभूति तथा विनिमय आयोग के अध्यक्ष जे क्लेटन ने कहा ये सिफारिशें कांग्रेस के कानून के अनुरूप हैं और बराबरी के मुकाबले के महत्व पर केंद्रित हैं। इस संबंध में अमेरिकी सीनेट ने मई में कानून पारित किया था, जिसके बाद यह कदम उठाया गया है। कानून के अनुसार तीन साल में इन नियमों का पालन नहीं करने वाली चीनी कंपनियों को शेयर बाजार से हटा दिया जाएगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि ट्रंप प्रशासन का ताजा कदम चीनी कंपनियों पर नकेल कसने की कोशिश का हिस्सा है।

लैंक्सेस का 'रिलाय+ऑन विरकॉन' कोरोनावायरस सार्स-कोव-2 को केवल 60 सेकेंड्स में निष्क्रिय कर देता है

मुंबई.ओपन सर्च

स्पेशियल्टी केमिकल्स कंपनी लैंक्सेस द्वारा निर्मित ब्रॉड स्पेक्ट्रम डिसइंफेक्टेन्ट 'रिलाय+ऑन विरकॉन' सार्स-कोव-2 वायरस के विरूद्ध तेजी से काम करता है। यह लैंक्सेस द्वारा कठोर सतह के विषाणुनाशक विसंक्रमण उत्पादों के लिये यू.एस. एनवायरनमेन्टल प्रोटेक्शन एजेंसी (ईपीए) के अनुसार स्वतंत्र विश्लेषण प्रयोगशाला माइक्रोबैक लेबोरेटोरीज के माध्यम से हाल ही में किये गये एक अध्ययन का परिणाम है।

'रिलाय+ऑन विरकॉन' ने केवल 60 सेकंड में डाल्यूशन रेशो 1 : 100 पर सार्स-कोव-2 वायरस को तेजी से और पूरी तरह अक्रिय कर दिया और इन-यूज डाल्यूशन पर 10 मिनट कॉन्टैक्ट टाइम का इकोनॉमिकल शो 1 : 600 था।

इस प्रकार का डाटा उन डिसइंफेक्टेन्ट्स के लिये जरूरी है, जो सार्स-कोव-2 से लड़ने का दावा करते हैं। माइक्रोबैक दुनिया की उन कुछ परीक्षण प्रयोगशालाओं में से एक है, जिन्हें यू.एस. हेल्थ अथॉरिटी सीडीसी (सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल) ने ऐसे परीक्षणों के लिये प्रमाणित किया है। हाइजीनिक सफाई और विसंक्रमण की अच्छी पद्धतियाँ अब पहले से ज्यादा महत्वपूर्ण हैं लैंक्सेस में बिजनेस डायरेक्टर डिसइंफेक्शन एनेलीज़ बिशफ ने कहा, ''वैश्विक कोरोनावायरस महामारी से लड़ने के लिये अभी कोई टीका या सामान्य तौर से अनुमोदित दवा उपलब्ध नहीं है। इसलिये सामाजिक दूरी और हाथ धोने के अलावा विसंक्रमण इस जानलेवा श्वसन रोग के फैलाव को रोकने में मदद करने वाला एक अत्यंत महत्वपूर्ण साधन है। अभी हाइजीनिक सफाई और विसंक्रमण की अच्छी पद्धतियाँ सबसे महत्वपूर्ण हैं।

'रिलाय+ऑन विरकॉन' द्वारा इतनी तेजी से सार्स-कोव-2 को अक्रिय किये जाने की बात से लोगों को यह भरोसा होगा कि वे जिस विसंक्रमण उत्पाद का उपयोग कर रहे हैं, वह व्यवहारिक उपयोग में तेज और प्रभावी है।

11 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों ने जुलाई में मुफ्त अनाज का वितरण नहीं किया: पासवान

नयी दिल्ली। (एजेंसी)

अगस्त खाद्य मंत्री राम विलास पासवान ने शुक्रवार को कहा कि पंजाब और पश्चिम बंगाल समेत 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) के तहत जुलाई में मुफ्त अनाज का वितरण नहीं किया। उन्होंने कहा कि इसके परिणामस्वरूप राशन दुकानों के जरिये मुफ्त खाद्यान्न पिछले महीने 81 करोड़ लाभार्थियों में से केवल 62 प्रतिशत तक ही पहुंच पाया। उन्होंने राज्यों से अनाज वितरण में तेजी लाने का आग्रह किया। पासवान ने कहा कि जुलाई में कम अनाज वितरण का कारण यह भी है कि कुछ राज्य दो महीने, तीन महीने या छह महीने में एक बार में ही अनाज वितरण का कार्यक्रम चलाते रहे हैं। पीएमजीकेएवाई के तहत अप्रैल से ही राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून (एनएफएसए) के तहत चिन्हित लाभार्थियों को मुफ्त अनाज का वितरण किया जा रहा है। इस पहल का मकसद कोविड-19 महामारी के कारण लोगों को होने वाली कठिनाइयों से राहत दिलाना है।

इसके अंतर्गत प्रति लाभार्थी 5 किलो अनाज (गेहूं या चावल) और एक किलो चना उपलब्ध कराया जा रहा है। योजना शुरू में तीन महीने के लिये लागू की गयी थी लेकिन बाद में इसे बढ़ाकर नवंबर तक कर दिया गया। पासवान ने संवाददाता सम्ममेलन में कहा, ''पहले तीन महीनों में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों ने पीएमजीकेएवाई के तहत करीब 95 प्रतिशत लाभार्थियों को अनाज का वितरण किया। लेकिन जुलाई में वितरण 62 प्रतिशत पर आ गया।'' उन्होंने कहा कि पिछले महीने कुल 81 करोड़ लाभार्थियों में से 49.87 करोड़ को अनाज वितरित किया गया। इन्हें करीब 24.94 लाख टन अनाज वितरित किये गये। पासवान ने यह भी कहा कि पंजाब, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, पुडुचेरी, नगालैंड, मिजोरम, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीपसमूह समेत 11 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों ने जुलाई माह में अनाज का वितरण नहीं किया। उन्होंने कहा कि माह के दौरान करीब नौ राज्यों ने 90 प्रतिशत वितरण किया जबकि पांच राज्यों ने 80 प्रतिशत अनाज मुफ्त वितरण किया। मंत्री ने कहा कि खाद्यान्न का वितरण जारी है।

इसे भी पढ़ें- 'वन नेशन-वन राशन कार्ड' योजना में शामिल हुएजम्मू-कश्मीर, मणिपुर, नागालैंड और उत्तराखंड- पासवान

पीएमजीकेवाई के तहत अगस्त में अब तक राज्य 72,711 टन अनाज राशन की दुकानों के जरिये 1.45 करोड़ लाभार्थियों को वितरित किये। उन्होंने कहा, ''कई राज्य अनाज का वितरण दो महीने, तीन महीने या छह महीने में एक बारगी कर रहे हैं। ज्यादातर वितरण चालू महीने में हो जाना चाहिए। बाढ़ प्रभावित राज्यों में अनाज वितरण की स्थिति के बारे में मंत्री ने कहा कि असम और बिहार में वितरण कार्य प्रभावित हुआ है। इन राज्यों में पीएमजीकेएवाई के तहत जुलाई में क्रमशः केवल 21 प्रतिशत और 52 प्रतिशत लाभार्थियों को अनाज

वितरित किये गये। दिल्ली में घरों तक अनाज की डिलिवरी को लेकर चिंता जताते हुए पासवान ने कहा कि यह सुविधा उन लाभार्थियों के लिये बेहतर है, जो राष्ट्रीय राजधानी में रह रहे हैं। उन्होंने कहा, ''लेकिन जो बाहर से आते हैं और राशन लेना चाहते हैं, उनके लिये क्या होगा। मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री (अरविंद केजरीवाल) से आग्रह करता हूं कि इस मामले पर गौर करें।'' पासवान ने कहा कि राशन कार्ड 'पोर्टेबिलिटी' सेवा 'एक देश-एक राशन कार्ड' से मार्च, 2021 तक सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) को जोड़ दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अब तक 24 राज्यों और संघ शासित प्रदेशों को इससे जोड़ा जा चुका है।

opensearch

विधायक केपी मलिक ने जैन मुनियों के दर्शन कर लिया आशीर्वाद

जैन स्थानक मंडी में चातुर्मास हेतु विराजमान है संघ संचालक मुनि नरेश चंद्र

नई दिल्ली (ओपन सर्च)। स्थानीय जैन स्थानक मंडी बड़ौत में चातुर्मास के लिए विराजमान गुरु सुदर्शन संघ संचालक जैन समाज के वरिष्ठ मुनि श्री नरेश चंद्र महाराज के दर्शन हेतु अलग-अलग राज्यों के दर्शनार्थियों व श्रद्धालुओं का आगमन हो रहा है, बड़ौत विधायक केपी मलिक ने आज जैन मुनि नरेश चंद्र जी महाराज एवं तपस्वी सुधीर मुनि जी आदि संतों के दर्शन किए व मार्गदर्शन प्राप्त किया। विधायक केपी मलिक ने वरिष्ठ जैन मुनि को उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री द्वारा संचालित धार्मिक सहिष्णुता के जारी किए गए कार्यक्रमों के विषय में जानकारी देते हुए उनसे आशीर्वाद की कामना की एवं कहा कि जैन मुनियों की त्याग तपस्या व पवित्र जीवन के कारण भारत भूमि पर अभी भी साधु-संतों का वर्चस्व व सम्मान किया जा रहा है जो कि गौरव की बात है।

बड़ौत नगर में आपके चातुर्मास से जो पवित्र वातावरण बना हुआ है उसके लिए बहुत विधानसभा की जनता आप के प्रति कृतज्ञता का भाव रखती है! उपस्थित श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए गुरु सुदर्शन संघ संचालक मुनि नरेश चंद्र महाराज ने भी कहा की कोरोना जैसी महामारी से लड़ने में उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री व स्थानीय प्रशासन ने बहुत बड़ा सहयोग किया व मानवता की रक्षा की। जिसके लिए आप सभी आशीर्वाद के पात्र हैं मानव जाति की रक्षा के लिए हर संभव प्रयत्न करने ही चाहिए। इस अवसर पर स्थानकवासी जैन समाज के अध्यक्ष शिखर चंद जैन, मार्गदर्शक डॉ अमित राय जैन, मनोज जैन, अनुराग जैन, पवन कुमार जैन, विधायक प्रतिनिधि प्रदीप कुमार जैन, मूलचंद जैन आदि लोग उपस्थित रहे!

कोरोना के बीच जरुरी स्वास्थ्य सेवाओं पर भी दे जोर : डब्ल्यूएचओ

कोलकाता.एजेंसी। विश्व स्वास्थ संगठन ने दक्षिण-पूर्व एशियाई क्षेत्र के देशों से वैश्विक महामारी कोरोना वायरस 'कोविड-19' के दौरान अन्य स्वास्थ्य सेवाओं पर भी जोर देने की अपील की है ताकि अन्य सेवाएं भी सुचारु रूप से चलती रहें। डब्ल्यूएचओ दक्षिण-पूर्व एशिया क्षेत्र की निदेशक डॉ. पूनम खेत्रपाल सिंह ने आज इस क्षेत्र के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ एक वर्चुअल बैठक में अन्य स्वास्थ्य सेवाओं पर जोर देने की अपील करते हुए कहा, ''कोरोना महामारी के कारण दक्षिण-पूर्वी एशियाई क्षेत्र के देशों में स्वास्थ्य सेवाओं पर अतिरिक्त असर पड़ा है। पिछली महामारी के प्रकोपों? से पता चला है कि एक प्रकोप के कारण आवश्यक सेवाओं में होने वाली दिक्कतें महामारी से भी अधिक घातक हो सकती हैं।'' कोरोना महामारी शुरू होने के बाद से स्वास्थ्य कर्मियों, वैकल्पिक देखभाल को रद्द करना, आउट पेशेंट सेवाओं को बंद करना, अपर्याप्त व्यक्तिगत सुरक्षात्मक उपकरण, उपचार नीति में परिवर्तन और आवश्यक सेवाओं की डिलीवरी महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित हुयी है। डॉ. खेत्रपाल सिंह ने कहा, ''आवश्यक सेवाओं को कैसे बनाए रखा जा सकता है उसे लेकर हमें अपने प्रमाण और ज्ञान के आधार को मजबूत करना चाहिए। हमें अपने अनुभवों और सीख को साझा करने तथा स्थानीय संदर्भों के अनुरूप नीतियों को अपनाने के लिए प्रयासों को नए सिरे से जारी रखना चाहिए।''

बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने नई शिक्षा नीति का श्रेय पीएम मोदी को दिया

नई दिल्ली.एजेंसी। तीन दशक बाद देश में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति तैयार होने का श्रेय भाजपा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शुक्रवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दृढ़ इच्छाशक्ति के कारण एक उत्कृष्ट राष्ट्रीय शिक्षा नीति हम सभी के सामने आई है। उन्होंने अपने बयान में कहा, बदलते समय में अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार विकसित की गई शिक्षा नीति बच्चों में न केवल सीखने की जिज्ञासा को बढ़ाएगी बल्कि उन्हें, उनके भविष्य के लक्ष्यों के अनुरूप उपयोगी ज्ञान अर्जित करने की व्यवस्था भी प्रदान करेगी।

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आगे कहा, प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन एवं दृढ़ इच्छाशक्ति के फल स्वरूप एक उत्कृष्ट राष्ट्रीय शिक्षा नीति हम सभी के समक्ष आई है। यह एक समावेशी तथा सार्वभौमिक शिक्षा नीति है जो भारत को पुनः विश्व पटल के शीर्ष पर स्थापित करने के लिए प्रभावी होगी। भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा का यह बयान शुक्रवार को नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर शिक्षाविदों को प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन के बाद आया है। बता दें कि बीते दिनों केंद्रीय कैबिनेट ने देश की नई शिक्षा नीति को मंजूरी दी थी। इससे पूर्व है वर्ष 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति तैयार हुई थी, जिसे 1992 में संशोधित किया गया था।

वर्ष 2015 से लगातार विचार-विर्मश के बाद डॉ. के. कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का प्रारूप तैयार किया गया। जिसे कैबिनेट से मंजूरी मिली। अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने की तैयारी चल रही है। नई शिक्षा नीति तैयार करने के लिए 36 राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों के 2.5 लाख ग्राम पंचायतों, 6600 ब्लॉक, 6000 शहरी स्थानीय निकायों, 676 जिलों में परामर्श और सर्वे का सहारा लिया गया।

'ईट राइट इंडिया' अभियान के लिए फूड सिस्टम विजन प्राइज की घोषणा

डॉ. हर्ष वर्धन ने सीएसआईआर और एफएसएसएआई के बीच खाद्य और पोषण से संबंधित सहयोगी अनुसंधान और सूचना प्रसार पर समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर समारोह की अध्यक्षता की

ओपन सर्च

नई दिल्ली। केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉ. हर्ष वर्धन ने आज भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) और भारतीय वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर) के बीच खाद्य और पोषण से संबंधित सहयोगी अनुसंधान और सूचना प्रसार पर समझौता ज्ञापन (एमओयू) हस्ताक्षर समारोह की अध्यक्षता की। इस अवसर पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री श्री अश्विनी कुमार चौबे उपस्थित रहे। इस एमओयू का उद्देश्य खाद्य और पोषण क्षेत्र में सहयोगी अनुसंधान और सूचना प्रसार करना है। एफएसएसएआई और सीएसआईआर को इस नवाचार पहल के लिए बधाई देते हुए डॉ. हर्ष वर्धन ने कहा कि इससे दोनों प्रमुख संगठनों की क्षमता और फैकल्टी को संयुक्त प्रयास होंगे। उन्होंने यह भी कहा कि एमओयू से खाद्य संरक्षा और पोषण अनुसंधान के क्षेत्र में प्रौद्योगिकियों और कार्यक्रमों की पहचान से इस क्षेत्र का विकास होगा। साथ ही सीएसआईआर के पास नवाचार प्रौद्योगिकियों की उपलब्धता को मान्यता मिलेगी और इन्हें भारतीय व्यापार जगत और कंपनियों के विनियमन में इस्तेमाल किया जा सकेगा। इससे खाद्य उपभोग, जैविक जोखिम की घटनाओं, खाद्य में मिलावट, उभरते जोखिम की पहचान, इनमें कमी लाने की रणनीतियों और रैपिड अलर्ट सिस्टम लागू करने से संबंधित डेटा संकलन भी किया जा सकेगा। दोनों संगठन देशभर में प्रयोगशाला नेटवर्क के गुणवत्तापूर्ण आश्वासन को मजबूत बनाने की दिशा में सहयोग करेंगे ताकि खाद्य उत्पादों की गुणवत्ता और संरक्षा के बारे में विश्वसनीय रिपोर्टिंग के तरीकों का इस्तेमाल और वैधता सुनिश्चित की जा सके। एमओयू के बारे में डॉ. हर्ष वर्धन ने कहा यह एमओयू एक अत्यंत महत्वपूर्ण कदम है जो भारत के लिए बेहतर भविष्य बनाएगा जिससे खाद्य और पोषण, खाद्य और उपभोक्ता सुरक्षा समाधान के क्षेत्र में सहयोगी अनुसंधान और सूचना का प्रसार किया जा सकेगा। इन दो प्रमुख संस्थानों के बीच सहयोग से न्यू फूड सिस्टम-2050 के विजन को पूरा करने में योगदान मिलेगा। डॉ. हर्ष वर्धन ने एफएसएसएआई को ईट राइट अभियान के लिए रॉकफेलर फाउंडेशन के पुरस्कार के लिए 10 वैश्विक संगठनों में से एक चुने जाने के लिए बधाई दी। इस संगठन को 2050 तक विकसित करने की आकांक्षा वाले पोषक फूड सिस्टम विकसित करने के प्रेरक विजन की संगठन को मान्यता मिली है। डॉ. हर्ष वर्धन ने कहा कि यह पुरस्कार खाद्य संरक्षा और पोषण की दिशा में एफएसएसएआई के संपूर्ण और पथ प्रदर्शक दृष्टिकोण की सशक्त मान्यता है। इससे इस संगठन के विस्तार पथ का भी विजन झलकता है। उन्होंने कहा ÷सभी के लिए स्वास्थ्य के विजन को शारीरिक अभ्यास और दैनिक जीवन में पोषक आहार के चयन से हासिल किया जा सकता है। ईट राइट इंडिया विजन सुरक्षित, स्वस्थ्य और सतत आहार विकसित करने के बारे में है। इसमें सभी पक्ष शामिल हैं और खाद्य उत्पादन, प्रसंस्करण, वितरण, गुणवत्ता और पहचान क्षमता से संबंधित प्रौद्योगिकी का सहयोग है और इससे सही खान-पान की प्रक्रियाओं के बारे में उपभोक्ता सशक्त बनते हैं। डॉ. हर्ष वर्धन ने उजागर किया कि 2050 के न्यू फूड सिस्टम से स्वस्थ, पोषक, पौध आधारित, स्थानीय, मौसमी और स्वदेशी खाद्य, जैविक रूप से उत्पादित खाद्य की मांग में उछाल आएगा। उन्होंने कहा कि इससे यह भी स्पष्ट होगा कि जलवायु अनुकूल खाद्य उत्पादन सिस्टम, भूमि और जल संसाधन संरक्षण, भोजन के नुकसान में कमी और वेल्यू चेन के दौरान खाद्य की बर्बादी में कमी, स्वः सतत स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं के लिए लघु स्तर की उत्पाद इकाइयों में वृद्धि, पर्यावरण अनुकूल पैकेजिंग विकल्प, बर्बादी की रीप्रपजिंग पर अधिक फोकस दिया जाएगा।

गहलोत सरकार पर कोई संकट नहीं

बसपा विधायकों को सम्मन तामील, अब सत्र से पहले बाड़ाबंदी कहीं भाजपा में ना हो जाए

हरीश गुप्ता

जयपुर। राजस्थान में चल रही सियासी घमासान पर अब ब्रेक लगते नजर आ रहे हैं। शुक्रवार को उच्च न्यायालय के सम्मन बसपा विधायकों को तामील होने के बाद अब संभावना जताई जा रही है, कहीं सत्र से पहले भाजपा विधायकों की बाड़ेबंदी ना हो जाए। उधर चर्चा इस बात की भी जोरों पर है कि सरकार और महामहिम के बीच कोई गुप्त समझौता हो चुका है।

गौरतलब है विधायक दल की बैठक के बाद सरकार की ओर से राज्यपाल को 21, 24 और 27 जुलाई को 15 वीं विधानसभा के पंचम सत्र बुलाए जाने के पत्र दिए गए। हर पत्र में कुछ सवाल खड़े कर राज्यपाल सचिवालय की ओर से वापस सरकार को लौटा दिए गए। उधर 29 जुलाई को जब गोविंद सिंह डोटासरा को पीसीसी चीफ का पदभार ग्रहण कार्यक्रम चल रहा था तभी मुख्यमंत्री गहलोत के पास राजभवन से बुलावा आया और वे [illegible] वहां से राजभवन की ओ[illegible] चल [illegible] राज्यपाल से उनकी करीब आधे घंटे चर्चा हुई। उसके बाद राजभवन से विधानसभा सत्र आहूत करने की स्वीकृति जारी हो गई। सबसे बड़ी बात तो यह है कि पहले जो सवाल उठाए जा रहे थे, सभी गौण हो गए। सचिवालय की गलियारों में चर्चाएं जोरों पर है, दोनों के बीच कोई गुप्त समझौता हो गया।

सूत्रों ने बताया कि शुक्रवार को बसपा विधायकों को उच्च न्यायालय का सम्मन भी तामील हो गया। [illegible] बसपा विधायक टेंशन फ्री हैं। वैसे भी उनका तर्क है कि उन्होंने पार्टी का विलय नहीं किया है, विधायक दल का विलय किया है।

सूत्रों ने बताया कि अब मामला सुलझता नजर आ रहा है। उधर बसपा विधायकों पर आंच आती है, जिसकी संभावना शून्य है, तो भी सरकार पर कोई संकट नहीं है। उसका कारण है सरकार ने राज्यपाल को दिए किसी भी पत्र में बहुमत साबित या फ्लोर टेस्ट की [illegible] नहीं की है। यह बात [illegible] [illegible] तो [illegible] लेकिन भाजपा चुप है। अंदर खाते भाजपा रणनीति तैयार कर रही थी, लेकिन भाजपा की कद्दावर नेता वसुंधरा राजे के दिल्ली जाने के बाद भाजपा नेताओं के सपनों पर पानी फिर गया। भाजपा को तो अब नए सिरे से रणनीति तैयार करनी होगी, वह भी यह सोच कर कि पार्टी विधायकों का एक बड़ा धड़ा उनके साथ ही न खड़ा हो। कहीं ऐसा ना हो विधानसभा अध्यक्ष किसी बिल पर 'हां पक्ष'-'ना पक्ष' का मत लें और यह धड़ा 'ना' बोलने की जगह मात्र नारेबाजी करते नजर आए।

सूत्रों की मानें तो पार्टी में वसुंधरा के कद को दिल्ली वाले भी हल्के में नहीं लेते। कहीं ऐसा ना हो कांग्रेस की तर्ज पर सत्र से पहले भाजपा विधायकों की बाड़ेबंदी हो जाए। वैसे भी कहा जाता है जैसे गहलोत को, ठीक उसी तरह राजे को समझना भी आसान ही नहीं नामुमकिन है। यह भी तय है सत्र के बाद गहलोत देश में एक बड़े ने[illegible] के रूप में उभर कर आएंगे, [illegible] अपना खेल पहले भी दिखा [illegible] हैं

opensearch

जम्मू-कश्मीर में 4जी इंटरनेट मामले पर कमेटी गठित नहीं

नई दिल्ली.एजेंसी। सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर में 4जी इंटरनेट के मामले पर अभी तक किसी कमेटी का गठन नहीं होने पर दायर अवमानना याचिका पर आज सुनवाई फिर टाल दिया है। जस्टिस एनवी रमना की अध्यक्षता वाली बेंच ने 11 अगस्त को अगली सुनवाई करने का आदेश दिया।

कोर्ट ने कहा कि आगे अब सुनवाई टाली नहीं जाएगी। शुक्रवार को सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि जम्मू-कश्मीर के नए उप-राज्यपाल कल ही नियुक्त हुए हैं। वे इस मामले में जवाब देने के लिए समय की मांग कर रहे हैं। जस्टिस रमना ने मेहता से पूछा कि हम जमीनी हकीकतों से अलग यह जानना चाहते हैं कि क्या कुछ इलाकों में 4-जी इंटरनेट शुरू करना संभव है। मेहता ने कहा कि नए उप-राज्यपाल के कार्यभार संभालने के बाद कुछ स्थितियां बदली हैं जिन पर विचार करना जरूरी है। इसका वकील हुफैजा अहमदी ने विरोध करते हुए कहा कि पहले सॉलिसिटर जनरल कह रहे थे कि जवाब देने की जरूरत नहीं है, अब कह रहे हैं कि जवाब देंगे। कोर्ट ने पिछली 16 जुलाई को केंद्र सरकार और जम्मू-कश्मीर प्रशासन को नोटिस जारी किया था। याचिका फाउंडेशन ऑफ मीडिया प्रोफेशनल्स ने दायर की है।

पिछली 11 मई को सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर में 4जी इंटरनेट की मांग करने वाली याचिका खारिज करते हुए 4जी की जरूरत पर विचार करने के लिए केंद्र सरकार को एक हाई पावर्ड कमेटी का गठन करने का निर्देश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि इस कमेटी की अध्यक्षता केंद्रीय गृह सचिव करेंगे। यह कमेटी याचिकाकर्ताओं की समस्याओं पर गौर करेगी।

कोविड बीमारी से ठीक होने की दर लगभग 68% की नई ऊंचाई पर पहुंची

नई दिल्ली. (ओपन सर्च)

कोविड मरीजों के ठीक होने की दर 68% की रिकॉर्ड ऊंचाई पर है जबकि मृत्यु दर भी 2.05 प्रतिशत के निचले स्तर पर पहुंच गया है

भारत दो महत्वपूर्ण उपलब्धियों- कोविड-19 मरीजों के बीच ठीक होने की दर में लगातार बढ़ोतरी और कममृत्यु दर जो वैश्विक औसत से भी कम बना हुआ है, के साथ कोविड-19 के उपचार के मार्ग पर आगे बढ़ रहा है। कोविड मरीजों के ठीक होने की दर 68% की रिकॉर्ड ऊंचाई पर है जबकि मृत्यु दर भी 2.05 प्रतिशत के निचले स्तर पर पहुंच गया है। इस प्रकार कोविड-19 रोगियों के बीच कम मृत्यु दर बना हुआ है। इन दोनों की वजह से भारत में इस बीमारी से ठीक होने वाले लोगों की संख्या और इसके सक्रिय मामलों की संख्या के बीच अंतर (7.7 लाख से अधिक) निरंतर बढ़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटों में 49,769मरीजों के ठीक होने के साथ ही इस बीमारी से स्वस्थ होने वाले मरीजों की कुल संख्या 13,78,105 हो गई है। अस्पतालों के बुनियादी ढांचे में सुधार और केंद्र द्वारा जारी नैदानिक उपचार प्रोटोकॉल में शामिल देखभाल मानकों के माध्यम से अस्पताल में भर्ती मरीजों के सही उपचार पर जोर देने से इस बीमारी से ठीक होने की दर में सुधार सुनिश्चित हुआ है। पिछले 2 हफ्तों में बीमारी से ठीक होने के दैनिक औसत मामले (7दिन पर औसत) लगभग 26,000से बढ़कर 44,000मामले हो गए हैं। केंद्र और राज्य/केंद्रशासित प्रदेश सरकारों द्वारा केंद्रित और समन्वित रोकथाम उपायों, मरीजों के पर्यवेक्षित आइसोलेशन के साथ व्यापाक स्तर पर परीक्षण और प्रभावी उपचार के निरंतर प्रयासों की वजह से इस बीमारी के सक्रिय मामलों के प्रतिशत में गिरावट और बीमारी से ठीक होने की दर में वृद्धि दोनों सुनिश्चित हुई है।

हमारी संस्कृति का निर्माण हमारा चरित्र करता है

मनीषीश्रीसंतमुनिविनयकुमार जी आलोक

चंडीगढ (ब्यूरो)। मनुष्य की महानता की पहचान उसके पद, अधिकार, ऐश्वर्य या धन-संपदा से नहीं, बल्कि उसकी विनम्रता, उदारता और कर्तव्य परायणता से होती है मनुष्य की महानता की पहचान उसके पद, अधिकार, ऐश्वर्य या धन-संपदा से नहीं, बल्कि उसकी विनम्रता, उदारता और कर्तव्य परायणता से होती है। व्यक्ति का चरित्र ही उसकी महानता की सच्ची कसौटी है। यानी उसके चरित्र की पूर्ति धन, यश, विद्वत्ता आदि में से कोई नहीं कर सकता। महान व्यक्ति अपने चरित्र की पवित्रता बनाए रखने के लिए हर तरह के त्याग के लिए हमेशा तैयार रहता है। चरित्र के बगैर व्यक्ति का जीवन वैसा ही है जैसे रीढ़ की हड्डी के बगैर शरीर। स्वामी विवेकानंद के शरीर पर भगवा वस्त्र और पगड़ी को देखकर एक विदेशी व्यक्ति ने टिप्पणी की थी। यह आपकी कैसी संस्कृति है। तन पर केवल एक भगवा चादर लपेट रखी है। कोट-पैंट जैसा कुछ भी पहनावा नहीं है। इस पर स्वामी जी मुस्कराए और बोले-हमारी संस्कृति आपकी संस्कृति से बिल्कुल अलग है। आपकी संस्कृति का निर्माण आपके दर्जी करते हैं, जबकि हमारी

संस्कृति का निर्माण हमारा चरित्र करता है। ये शब्द मनीषीसंत मुनिश्री विनयकुमार जी आलोक ने कहे।

मनीषीश्रीसंत ने आगे कहा- संस्कृति वस्त्रों में नहीं, बल्कि चरित्र के विकास में है। हमारे चरित्र का निर्माण हमारे विचार करते हैं। इसलिए चरित्र को बदलने के लिए विचारों को बदलना जरूरी होता है। असल में ज्ञान का सामान्य अर्थ जानकारी है, लेकिन वास्तविक ज्ञान आत्मज्ञान की जानकारी है। आत्मज्ञान ही वह अमृत है जिसे पाने के बाद और कुछ पाना शेष नहीं रह जाता। एक संत के पास उनका एक शिष्य आया और उनसे पूछा, ह्यमैं कौन हूं?ह्न गुरुजी ने एक थाली में पानी भरकर कहा था इसमें अपना मुख देखोगे तो तुम अपना साक्षात्कार कर लोगे। जब शिष्य ने उसमें अपना मुख देखा तो उसे लगा कि वह अति सुंदर है, लेकिन अगले ही पल उसे महसूस हुआ कि समय के साथ उसके मुख का स्वरूप भी बदल जाएगा और तब वह इतना सुंदर नहीं रहेगा। उसी पल उसे अपने सुंदर मुख से घृणा होने लगी और वह यह बात समझ गया कि जो चीज कुछ समय बाद जीर्ण-क्षीण हो जाए वह उसका स्वरूप कैसे हो सकता है।

जब व्यक्ति ह्यमैंह्न को त्यागता है तभी वह महान बनता है। ह्यमैंह्न का त्याग तभी संभव है जब व्यक्ति खुद पर संयम रख सके। खुद पर काबू रखने वाला व्यक्ति आत्मप्रशंसा से बचता है जिससे उसमें धीरज, सेवा, शुद्धता, शांति, आज्ञा, अनुशासन और मेहनत के भाव पनपते हैं। ऐसे व्यक्ति सत्य का साथ कभी नहीं छोड़ते और मनुष्य की सेवा को ही अपना धर्म मानते हैं।

मनीषीश्रीसंत ने अंत मे फरमाया- संपूर्ण ज्ञान तब मात्र शून्य सिद्ध हो जाता है जब चारित्रिक पतन के कारण व्यक्ति इन्हें व्यवहार में नहीं उतार पाता। कोई कितने भी बड़े विद्यालय-विश्वविद्यालय में पठन-पाठन की श्रेष्ठता की श्रेणी में निस्संदेह गिना जाए, पर यदि वह अपने चरित्र को नहीं संभाल पाता है तो उसकी श्रेष्ठता सामाजिक स्तर पर अमान्य ही होती है। चरित्र का संरक्षण कर साधारण मनुष्यों ने जीवन में बहुत ऊंचाइयां प्राप्त की हैं। स्वामी विवेकानंद चरित्रवान व्यक्ति के रूप में भलीभांति स्थापित हैं। उनकी आध्यात्मिक, दार्शनिक अंतर्दृष्टि से कौन विद्वान परिचित नहीं है। चरित्र में सज्जनता आदि मानवीय गुणों को शामिल किया जाता है।

14 अगस्त को राजस्थान की जनता को मिलेगी गहलोत सरकार के कुशासन से मुक्ति : केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी

स्थानीय भाजपा कार्यालय में प्रेसवार्ता के दौरान कृषि राज्यमंत्री कैलाश चौधरी ने मांगा नैतिकता के आधार पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से इस्तीफा

जैसलमेर (ओपन सर्च)
स्वर्णनगरी जैसलमेर इन दिनों प्रदेश के सियासी घमासान का अखाड़ा बना हुआ है। पिछले एक सप्ताह से ज्यादा समय हो गया है, जब राजस्थान की गहलोत सरकार जैसलमेर के सूर्यगढ़ और गोरबंध पैलेस होटल में ठहरी हुई है। इस बीच केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्यमंत्री कैलाश चौधरी भी अपने तीन दिवसीय जैसलमेर दौरे पर हैं। केंद्रीय मंत्री ने शुक्रवार को स्थानीय भाजपा कार्यालय में पत्रकार वार्ता के दौरान प्रदेश की कांग्रेस सरकार को जनता विरोधी बताते हुए कहा कि प्रदेश में जो वर्तमान हालात हैं, उसके लिए कांग्रेस और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद जिम्मेदार हैं। केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा कि प्रदेश का आमजन और किसान परेशान है। कोरोना का संकट और आपराधिक घटनाएं बढ़ रही है। दूसरी तरफ राजस्थान की कांग्रेस सरकार होटलों में कैद होकर बिरियानी खाने और स्विमिंग पूल की मौज-मस्ती में व्यस्त है। एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते जनता के दर्द को देखकर मन में दुःख होता है। कृषि राज्यमंत्री चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस नेता बिना किसी तर्क और तथ्य के अपने घर की लड़ाई का ठीकरा भाजपा और राज्यपाल पर फोड़ रहे है। यह परंपरा निश्चित रूप से निंदनीय और चिंतनीय है। श्री कैलाश चौधरी ने कहा कि यह गहलोत और पायलट की आपसी लड़ाई है, जिसका खामियाजा राजस्थान की जनता भुगत रही है। परंतु कांग्रेस नेता इसका दोषारोपण भाजपा पर कर रहे है, लेकिन भाजपा का इससे कोई संबंध नहीं है। उन्होंने कहा कि गहलोत अपने विधायकों का भरोसा खो चुके हैं, इसलिए उन्हें इस तरीके से कैद किया गया है। केंद्रीय कृषि राज्यमंत्री कैलाश चौधरी ने कहा- 'हम शक्ति परीक्षण की मांग नहीं कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने जनमत खो दिया है और खुद ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। डेढ़ साल से ज्यादा समय बिता चुकी कांग्रेस सरकार ने अभी तक अपने घोषणापत्र का एक भी वादा पूरा नहीं किया है। न तो राहुल गांधी के खोखले वादे के मुताबिक किसानों का कर्ज माफ किया, न युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दिया और न ही टिड्डी संकट के समय केन्द्र सरकार की कोई मदद कर रही है।केन्द्र सरकार ने रखीआत्मनिर्भर भारत की नींव = वहीं केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी ने केंद्र की मोदी सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि इन 6 वर्षों के कार्यकाल में न सिर्फ कई ऐतिहासिक गलतियों को सुधारा है बल्कि 6 दशक की खाई को पाट कर विकासपथ पर अग्रसर एक आत्मनिर्भर भारत की नींव भी रखी है। यह 6 वर्ष का कार्यकाल 'गरीब कल्याण व रिफ़ार्म के समांतर समन्वय की एक अभूतपूर्व मिसाल है। चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी पर भारत की जनता का जो अटूट विश्वास है वैसा देश की जनता का अपने नेतृत्व में विश्वास दुनिया में विरले ही देखने को मिलता है।

संगान भय-मुक्त व मधुर हो : आचार्य महाश्रमण

पूज्य प्रवर ने की स्वरों के गुण एवं दोषों की व्याख्या

हैदराबाद (ओपन सर्च)
अहिंसा यात्रा प्रणेता आचार्य महाश्रमण जी जैन आगम ठाणं प्रवचन माला के अन्तर्गत नित नवीन ज्ञान प्रदान कर सभी को प्रेरणा प्रदान कर रहे हैं इसी कड़ी में सात स्वरों की व्याख्या करते हुए कहा कि शास्त्र में प्रश्न किये गये है कि सात स्वर किनसे उत्पन्न होते है, गीत की जाति क्या है,गीत का उच्छ्वास काल कितना होता है, गीत के आकर कितने होते है ? ठाणं में सातों स्वरों का उत्पति स्थान- नाभि, गीत की जाति-रुदन, गीत का काल -उच्छ्वास व गीत का आकर मृदु, तीव्र व मंद बताया है । गीत के 6 दोष ध्यान देने योग्य है -1. भीत - भयभीत होकर गाना,जिसे स्टेज फिअर कह सकते हैं 2. द्रुत - शीघ्रता से गाना 3. हर्श्व - शब्दों को लघु बनाकर गाना या मात्रा के अनुसार न गाना 4. उत्ताल यानि ताल के अनुसार न गाना 5. काक स्वर यानि कर्कश व कौवे की तरह गाना,कर्ण कटु गाना 6. नाक से गाना, यदि ऐसी आदत हो गई

हो तो उस पर ध्यान देना । उसी के विपरीत गीत के आठ गुण भी उल्लेखित है 1. पूर्ण अर्थात आरोह-अवरोह आदि परीपूर्ण होना 2. रत - अच्छी लय,राग व गायन में तन्मयता 3. अलंकृत - विभिन्न स्वरों से सुशोभित होना 4. व्यक्त - शब्द व भाषा स्पष्ट हो 5. नियमित स्वर युक्त गाना 6. मधुर स्वर से गाना ।. वाध्य व गायन सामग्री का अनुगमन करना 8. कोमल लय से गाना। आचार्य श्री ने आगे फरमाया कि इसके अतिरिक्त आठ गुण ओर भी है - 1. पूर्ण विशुद्ध 2. कंठ फटे नहीं 3. शिरो विशुद्ध, सिर से उत्पन्न होकर भी नाक से न गाया जाय 4. मृदु, कोमल 5. रिधित 6. परबद्ध ।. समताल, पाद नर्तक 8. सातों स्वर सम हो । गीतकार की रचनाओं के लिए भी कुछ और निर्देश है - 1. निर्दोष 2. अर्थ युक्त, सार युक्त 3. हेतु युक्त 4. अलंकृत 5. उपनीत 6. सोपचार ।. परिमित 8. प्रिय, मधुर । छंद के तीन प्रकार है 1. लघु गुरु समान हो 2. अर्ध सम 3. सर्व विषम । भाषा का जो उल्लेख शास्त्रों में है वह है संस्कृत और प्राकृत, क्योंकि यह आगम व प्राचीन ऋषियों की वाणी है ।कुल मिलाकर यह सात स्वरों का स्वर मंडल है। आज हिंदी, राजस्थानी, गुजराती व अन्य प्रांतीय भाषाओं में भी गीत लिखे जाते है पर गुणवत्ता सबके लिए जरूरी है और गीत भगवान की भक्ति के लिए गाये जाए तो गीत की सुमधुरता अपने आप बढ़ जाती है।

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक व सम्पादक विजय कुमार द्वारा आदित्य ग्राफिक्स, प्रताप भवन 5, बहादुर शाह जफर मार्ग, आई.टी.ओ. नई दिल्ली-110002 से मुद्रित कराकर 1536/108 गणेशपुरा रोड, त्रीनगर दिल्ली-110035 से प्रकाशित। सम्पादक : विजय कुमार RNI No. : DELHIN/2015/66886
अखबार में प्रकाशित तथ्यों एवं लेखों से सम्पादक का सहमत होना अनिवार्य नहीं, किसी भी कानूनी वाद विवाद का निपटारा दिल्ली न्यायालय के अधीन होगा। मोबइल : 9210092542 फोन :- 011-27380260 E-mail : opensearchdelhi@gmail.com